I A S

GS WORLD

IAS PCS

Committed To Excellence

P C S

(27 अगस्त से 11 सितंबर तक)

आलेख सार

अंक - 17

संपादकीय Analysis 360°

एक कदम, सफलता की ओर...

प्रिय अभ्यर्थियों!

जैसा कि आप जानते हैं कि जी०एस० वर्ल्ड प्रबंधन पिछले कुछ वर्षों से लगातार आपके अध्ययन सामग्री की गुणवत्ता संवर्धन हेतु सतत् प्रयासरत है, जिसके लिए दैनिक स्तर पर अंग्रेजी समाचार-पत्रों का सार एवं जी.एस. वर्ल्ड टीम द्वारा सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है। साथ ही साप्ताहिक स्तर पर हिन्दी समाचार-पत्रों का सार उपलब्ध कराया जाता था, किंतु सिविल सेवा परीक्षा के बढ़ते स्तर एवं बदलते प्रश्नों को देखते हुए जी.एस. वर्ल्ड प्रबंधन ने साप्ताहिक समाचार-पत्रों के सार के स्थान पर अर्द्धमासिक स्तर पर संपादकीय Analysis 360^0 आरंभ किया है।

संपादकीय Analysis 360^0 में नया क्या है?

- इसमें महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विभिन्न हिन्दी समाचार-पत्रों में आए संपादकीय लेखों का सार उपलब्ध कराया जा रहा है।
- इन संपादकीय लेखों को समग्रता प्रदान करने के लिए इनसे जुड़ी सभी बेसिक अवधारणाओं को जी.एस. वर्ल्ड टीम द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।
- इन मुद्दों से संबंधित 2013 से अब तक सिविल सेवा परीक्षा में पूछे गए प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को भी नीचे दिया गया है, जिससे अभ्यर्थी उस मुद्दे से जुड़े प्रश्नों को समझ सकें।
- इन मुद्दों से संबंधित संभावित प्रश्नों को भी इन आलेखों के साथ दिया गया है, जिसका अभ्यास अभ्यर्थी स्वयं कर संस्थान में अपने उत्तर की जाँच भी करा सकते हैं।

जी.एस. वर्ल्ड प्रबंधन आपके उज्ज्वल एवं सफल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है।...

नीरज सिंह
(प्रबंध निदेशक, जी.एस. वर्ल्ड)

GS World
Committed To Excellence

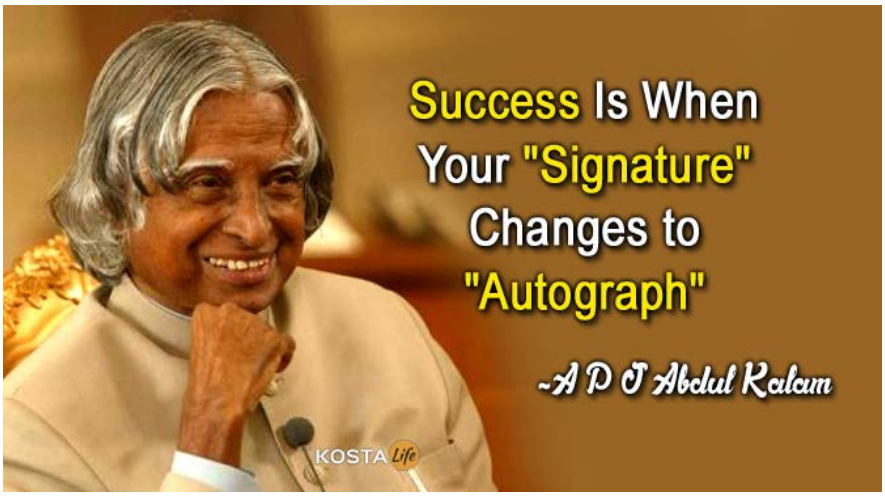

विषय-सूची

1. एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन 4

2. एक साथ चुनाव की संभावना 13

3. देश की पहली जैव जेट ईंधन संचालित उड़ान 18

4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका 23

5. गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या का समाधान 28

6. समाधान प्रणाली की तरफ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड 34

7. भारतीय रिजर्व बैंक की नोटबंदी पर सालाना रिपोर्ट 38

8. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत 45

9. अंतरिक्ष में जाने का भारतीय सपना 50

GS World
Committed To Excellence

एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-2 (गवर्नेंस) से संबंधित है।

भारतीय खिलाड़ियों ने एशियाड में श्रेष्ठ प्रदर्शन करके ओलंपिक के लिए उम्मीदें जगा दी हैं, भारत इन खेलों का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहा। कुल पदकों के मामले में उसने अब तक के अपने सबसे अधिक 69 पदक जीते, जबकि स्वर्ण पदकों के मामले में 1951 के पहले एशियाई खेलों के 15 स्वर्ण पदकों की बराबरी की। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार-पत्रों 'अमर उजाला', 'नवभारत टाइम्स', 'पत्रिका', 'जनसत्ता', 'दैनिक जागरण' तथा 'दैनिक ट्रिब्यून' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

पदकों की दौड़ में पीछे (अमर उजाला)

एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ियों द्वारा जीते मेडल पर अखबारों में विजेताओं के नाम सुर्खियों में छपने लगे, जैसे इस बार देश ने वास्तव में कमाल करके दिखा दिया हो। रेडियो और टीवी पर भी इन पदकों की इतनी चर्चा हुई कि जैसे हम भुलाने की कोशिश कर रहे हों कि चीन के खिलाड़ियों ने हमसे चार गुना ज्यादा मेडल जीते हैं। जब तक हम उन चीजों को लेकर गौरवान्वित होते रहेंगे, जिन पर हमें शर्मिंदा होना चाहिए, तब तक परिवर्तन लाने की संभावना नहीं है। खेलकूद में परिवर्तन लाया जा सकता है, लेकिन तभी, जब हम स्वीकार करेंगे कि हमको शर्मिंदा होना चाहिए कि इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इतने थोड़े खिलाड़ी पैदा करता है।

कारण कई हैं। एक यह कि हमारी सरकारों ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। कोई तीस वर्ष पहले हमने बड़े शान से एशियाड खेल दिल्ली में आयोजित किया था, जिसके लिए आलीशान स्टेडियम बने। लेकिन खेल समाप्त होने के बाद ये खंडहर बनते गए हैं, क्योंकि खेल मंत्रालय ने इनको आम खिलाड़ियों के लिए कभी खोला ही नहीं। यहाँ सिर्फ विशेष कार्यक्रम होते हैं, जिनमें विदेशी खिलाड़ी भाग लेने आते थे। दूसरा कारण यह है कि हम अपने खिलाड़ियों को वह ट्रेनिंग ही नहीं देते, जो अन्य देश देते हैं। तीसरा कारण यह है कि शुरू से क्रिकेट के अलावा हमने किसी भी खेल को अहमियत नहीं दी है। लेकिन इन सबसे बड़ा एक कारण और भी है, जिसका हम जिक्र तक नहीं करते। वह यह कि हम अक्सर शहरों और महानगरों में कुशल खिलाड़ी ढूँढते हैं और वह भी सिर्फ मध्यवर्ग के बच्चों में।

ग्रामीण क्षेत्रों तक हमारी दृष्टि पहुंचती ही नहीं है। बहुत साल पहले जब हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय खेल मंत्री थे, तब उन्होंने मेरा ध्यान इस ओर दिलाया था, जब मैं यह पूछने उनके पास गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में हम हमेशा इतने पीछे क्यों रहते हैं। उन्होंने मुझे कहा था, इसलिए कि हम खिलाड़ी गलत जगहों पर ढूँढ रहे हैं। जो छोटे बच्चे पुरानी बावलियों में गहरे पानी में डुबकियाँ लगाकर सिक्के ढूँढकर दो पैसे कमाते हैं, उनको तैरने की ट्रेनिंग दी जाए, तो वे विदेशों में बहुत नाम कमा सकते हैं।

बहुगुणा जी ने और भी उदाहरण दिए। गाँवों में तकरीबन हर बच्चे को घुड़सवारी सीखनी पड़ती है, लेकिन किसी एक बच्चे में अगर खास हुनर दिखता है, तो दब जाता है, क्योंकि उसको न ट्रेनिंग दी जाती है और न ही किसी बड़ी स्पर्धा में भाग लेने का अवसर। कोई इत्तफाक नहीं है कि हरियाणा जैसे ग्रामीण राज्य से पहलवान आज लड़कियाँ भी बनती जा रही हैं। ग्रामीण जीवन अपने देश में इतना कठिन है कि कमजोर बच्चे भी अपने-आप ताकतवर बन जाते हैं।

हार के बावजूद (नवभारत टाइम्स)

एशियाड में कबड्डी के अब तक के सारे स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम को गहरा झटका लगा है। ईरान के हाथों पुरुष और महिला, दोनों ही टीमों को हार का सामना करना पड़ा। पुरुष टीम उससे सेमीफाइनल में हारी जबकि महिला टीम फाइनल में। पुरुषों के दूसरे सेमीफाइल में पाकिस्तान की टीम दक्षिण कोरिया से हार गई। इस तरह एशिया स्तर की कबड्डी में भारत ही नहीं, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की बादशाहत खत्म हो गई है।

1990 में जब पहली बार एशियन गेम्स में कबड्डी शामिल हुई तो भारत और पाकिस्तान इसकी सबसे बड़ी ताकत थे। लेकिन यह विचित्र संयोग है कि इस बार भारत और पाकिस्तान दोनों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। हमारे लिए यह भले ही एक बुरी खबर हो पर हमारे देसी खेल कबड्डी के लिए इसे अच्छी खबर कहा जाएगा। इस खेल में ईरान और साउथ कोरिया जैसे मुल्कों के सामने आने से इसकी चमक और गरिमा बढ़ी है। क्या पता, इनसे प्रेरणा लेकर कल कुछ और भी देश कबड्डी में आगे आएं और इसे ओलंपिक में शामिल करने की मांग तेज हो जाए। इस तरह एक ठेठ उत्तर भारतीय खेल देखते-देखते ग्लोबल हो जाएगा।

सच्चाई यह है कि आज अगर कबड्डी को चमक-दमक का मुकाम हासिल हुआ है तो इसका श्रेय भारत को ही जाता है। हमारे लोग जहाँ भी गए, वहाँ उन्होंने इसको लोकप्रिय बनाने की कोशिश की है। 1980 में कपूरथला से इंग्लैंड गए अशोक दास ने वहाँ लड़कियों की अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी टीम तैयार की। ईरान और साउथ कोरिया जैसी टीमों को धार देने का श्रेय भी भारत को ही जाता है।

ईरान के कुछ इलाकों में हजारों साल से कबड्डी जैसा एक खेल खेला जाता था जिसमें 'कबड्डी-कबड्डी' की जगह 'जूद्धजू' कहते थे। लेकिन यह सिर्फ मनोरंजन के लिए खेला जाता था। 21 साल पहले वहाँ इसके लिए एक नेशनल फेडरेशन की स्थापना हुई और ईरान में कबड्डी का सिलसिला चल निकला। इसी तरह एशियाड में शामिल होने से दक्षिण कोरिया में इस खेल के प्रति जिज्ञासा बढ़ी और इसमें कई अच्छे खिलाड़ी आए।

भारत में प्रो कबड्डी लीग शुरू होने से इन देशों के खिलड़ियों को भारतीयों के साथ खेलने का अवसर मिला। ईरान के फजल अत्रचली काफी पैसे पर भारतीय फ्रेंचाइजी यू मुंबा की ओर से खेल रहे हैं, जबकि साउथ कोरियाई टीम के कप्तान जांग कुन ली लगातार दूसरे साल बंगाल वारियर्स के लिए खेलने वाले हैं। उनके अलावा आठ और खिलाड़ी विभिन्न भारतीय फ्रेंचाइजी के साथ अनुबंधित हैं। जाहिर है, कबड्डी के कई गुर इन्होंने भारत में आकर सीखे हैं। यही नहीं, इन दोनों टीमों ने भारत के पूर्व खिलाड़ियों को अपना प्रशिक्षक बनाया है और इस क्रम में हमें चुनौती देने लायक बने हैं। इसे पॉजिटिव रूप में लेने की जरूरत है, हालाँकि आगे हमें सजग रहना होगा और अपनी तैयारी ज्यादा पुख्ता करनी होगी।

तो सोचिए कि अगर हर ग्राम पंचायत में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध की जाए, स्टेडियम बनाए जाएँ और जिम खोले जाएँ, तो क्या हो सकता है। काफी हद तक ये सारे काम राज्य सरकारों के तहत आते हैं, लेकिन देश के लिए खेल नीति तैयार करना केंद्र सरकार का काम न होता, तो दिल्ली में खेल मंत्रालय न होता। परिवर्तन तब आएगा, जब हमारी सरकारों की सोच में परिवर्तन आएगा।

चीन और रूस जैसे देशों में सरकार खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने का पूरा बोझ उठाती हैं। अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में धनवान खेलों में और खिलाड़ियों पर निवेश करते हैं। भारत में हम न इधर के हैं, न उधर के, सो हमारे कुशल बच्चों का हुनर अक्सर बेकार जाता है।

दिखावे की बातें (पत्रिका)

भारत में खेलों को लेकर जिम्मेदार नेताओं के मौसमी या क्षणिक बयान आने लगे हैं, जिनमें दिखावा ज्यादा है और अफसोस कम। दरअसल एशियाई खेलों में प्रदर्शन ऐसा नहीं हो रहा है कि केन्द्र सरकार ढिंढोरा पीट सके, इसलिए खेलों में सुधार की पारंपरिक चर्चा शुरू कर दी गई है। सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बयान दिया है कि अगले वर्ष तक स्कूलों में पाठ्यक्रम आधा हो जाएगा और खेल की कक्षा जरूरी हो जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी कई बार संकेत दे चुके हैं।

इनसे पहले भी कई बार केन्द्रीय मंत्रियों ने खेलों में क्रांति लाने की बात कही थी, लेकिन पदक तालिका से लोगों का ध्यान हटते ही जिम्मेदार नेता फिर खेल से खिलवाड़ शुरू कर देते हैं। कोई पूछे और देखे तो सही कि जापान, ईरान जैसे देश कैसे आगे निकल गए। इन देशों के लोग जब पदक तालिका में भारत की उपस्थिति देखते होंगे, तो क्या सोचते होंगे? क्या भारत सरकार और भारत के लोगों ने अभी भी खेलों के महत्त्व को नहीं समझा है?

भारत सरकार ऐसा मान रही है कि देश में बच्चों पर पढ़ाई का बोझ इतना ज्यादा है कि उनके पास खेलने के लिए समय नहीं बचता है, तो पढ़ाई को आधा करना होगा। यदि शिक्षा विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं, तो काश यह काम पहले हो गया होता। यह काम चुनावी वर्ष के लिए नहीं छोड़ना चाहिए था। हालाँकि महत्त्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि पाठ्यक्रम आधा करने से बहुत फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि एनसीईआरटी को देश के ज्यादातर स्कूल नहीं मानते। ऐसे निजी स्कूलों का पाठ्यक्रम और भी दिखावटी व जटिल होता है। ऐसे निजी स्कूलों को जब सरकार एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम लागू करने के लिए मजबूर नहीं कर पाई, तो उसका आधा पाठ्यक्रम इनमें कैसे लागू होगा?

केन्द्र सरकार का दूसरा कदम होगा- खेल की क्लास को जरूरी बनाना। यह भी एक मुश्किल काम है। नियम तो यह भी है कि बिना खेल के मैदान या बिना खेल सुविधा के स्कूल नहीं खुल सकते, लेकिन उसका पालन नहीं होती है। देश में ज्यादातर निजी स्कूल ऐसे हैं, जिनके पास खेल के मैदान नहीं है, वे कैसे खेल को अनिवार्य बनाएंगे? क्या उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, जिनके पास मैदान नहीं है या जिनके पास इंडोर खेल सुविधा भी नहीं है? हमारी सरकारों का शिक्षा व निजी स्कूलों के प्रति जो लचीला, नीतिहीन ढर्रा रहा है, उसमें वे निजी स्कूलों पर कड़ाई नहीं कर सकतीं। यदि कड़ाई नहीं होगी, तो स्कूल न तो पहले पदक विजेता देते थे और न आगे देंगे। जिन बच्चों में व्यक्तिगत प्रतिभा और लगन होगी, वही आगे बढ़ते थे और आगे भी ऐसा ही होगा।

स्वर्णिम उपलब्धि (जनसत्ता)

जकार्ता में चल रहे एशियाई खेलों में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल कर पदक तालिका में भारत को एक और सम्मान दिलाया। यह एक बड़ी उपलब्धि इस लिहाज से है कि एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत को सोने का तमगा मिला। इस बार नीरज चोपड़ा ने मई में डायमंड लीग शृंखला में 87.43 मीटर के अपने ही प्रदर्शन में सुधार किया और एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 88.06 मीटर का नया राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया। हालाँकि वे 2014 के 89.75 मीटर के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए, लेकिन उनकी ताजा जीत और स्वर्ण पदक की खूबसूरती यह है कि इस प्रतियोगिता में दूसरे विजेता यानी रजत और कांस्य पदक हासिल करने वाले खिलाड़ी नीरज से काफी पीछे रहे। यानी कहा जा सकता है कि इस बार नीरज की होड़ खुद से थी और मैदान में उन्होंने अपनी क्षमता को साबित भी किया। इससे पहले 1982 में नई दिल्ली में हुए एशियाई खेलों में गुरतेज सिंह ने कांस्य पदक जीता था। इस तरह नीरज एशियाई खेलों की भाला फेंक स्पर्धा में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने।

जाहिर है, इतने लंबे समय के बाद इस खेल में भारत की शानदार कामयाबी सबके लिए खुश होने की बात है। लेकिन इसके साथ यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इतनी बड़ी आबादी वाला हमारा देश भाला फेंक जैसे खेल में कोई पदक हासिल करने से बीते छत्तीस साल तक वंचित क्यों रहा! इसका कारण भारत में खेल नीति का वह पक्ष है, जहाँ प्रतिभाओं की खोज और उनके प्रशिक्षण के पहलू पर बहुत ज्यादा काम नहीं किया जाता। इसके अलावा, जिन खेलों में भारत अपनी अच्छी-खासी मौजूदगी दर्ज कर सकता है, उनमें भी कई बार बेहद कमजोर उपस्थिति दिखती है। जबकि ऐसे तमाम उदाहरण हैं, जिनमें दूरदराज या ग्रामीण इलाकों में मौजूद प्रतिभाएँ अगर किन्हीं वजहों से सामने आ सकीं तो उन्हें बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा प्रशिक्षण की जरूरत नहीं पड़ी। दिक्कत यह है कि क्रिकेट जैसे खेल को जिस तरह बढ़ावा दिया गया, उससे देश भर में इस खेल को काफी लोकप्रियता मिली। यह अच्छी बात है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस वजह से बाकी खेलों को अपेक्षित महत्त्व नहीं मिल सका।

इसके अलावा, इस बार मैदान में भारत के कई अन्य खिलाड़ियों ने अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज की और देश के लिए पदक हासिल किए। मसलन, खेलों के शुरुआती दौर में ही बजरंग पूनिया ने पुरुष कुश्ती में, फिर विनेश फोगाट ने महिला कुश्ती में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। तीरंदाजी सहित कुछ अन्य खेलों में भी भारत के खिलाड़ियों ने बेहतरीन और विजयी प्रदर्शन किए। फिलहाल आठ स्वर्ण, सोलह रजत और इक्कीस कांस्य पदकों के साथ भारत सूची में नौवें स्थान पर है। लेकिन चूँकि अभी खेलों को खत्म होने में तीन दिन बाकी हैं, इसलिए और पदकों की उम्मीद की जानी चाहिए। लेकिन इस बार अफसोस की बात यह रही कि आमतौर पर सभी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में कबड्डी में सब पर हावी रहने वाला भारत के पुरुष और महिला टीमों को इस बार स्वर्ण से वंचित रहना पड़ा। जबकि खासतौर पर कबड्डी में भारत को दुनिया भर में बादशाहत हासिल थी। हालाँकि पदक जीत या हार का पैमाना माने जाते हैं, इसलिए इनका अपना महत्त्व है। उम्मीद है कि इस बार के नतीजे से भारतीय खिलाड़ी भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन के लिए खुद को तैयार करेंगे।

खेलों का सच बहुत स्याह है। पदक तालिका में भारत की कमजोर उपस्थिति देख नेताओं को ही क्यों, किसी भी स्कूल संचालक या शिक्षक को भी शर्म नहीं आती। पहले जिम्मेदारों को जिम्मेदारी का अहसास तो हो। केवल कागजी प्रस्तावों और सुधारों से भारत का सम्मान नहीं बढ़ने वाला। पहले देश के सभी स्कूलों को नए पाठ्यक्रम व मैदान के साथ तैयार करना होगा, उसके बाद ही देश का नाम खेल पदक तालिकाओं में ऊपर चमकेगा।

भारतीय खिलाड़ियों ने एशियाड से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके जगा दी ओलंपिक के लिए उम्मीदें (दैनिक जागरण)

एशियाड में इस बार भारत को जैवलिन थ्रो, शॉटपुट, हेप्टाथलान, पुरुष 1500 मीटर और लाइट-फ्लाइवेट मुक्केबाजी में एशियाई खेलों के इतिहास का पहला स्वर्ण पदक हासिल हुआ। राही सरनोबत इन खेलों की निशानेबाजी स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली अब तक की पहली भारतीय महिला खिलाड़ी रहीं। घुड़सवारी में भारत को 42 साल बाद रजत पदक हासिल हुआ और इतने ही वर्षों बाद भारत को कुश्ती में दो स्वर्ण मिले। बैडमिंटन की वैयक्तिक स्पर्धा में भारत को 36 साल बाद पदक हासिल हुए। टेबल टेनिस में दो कांस्य पदक जीतने के साथ ही भारत ने इस खेल में अब तक के सूखे को समाप्त किया। मंजीत सिंह ने 800 मीटर दौड़ में 36 साल बाद भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। इसी तरह दूती चंद ने महिलाओं की सौ मीटर और मोहम्मद अनस ने पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा में भारत को 32 साल बाद रजत पदक दिलाए।

महिला हॉकी टीम ने 20 साल बाद रजत अपने नाम किया, जबकि हाल में विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला हिमा दास ने 400 मीटर दौड़ में न सिर्फ राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ रजत जीता, बल्कि भारत को इन खेलों का छठा रिले स्वर्ण दिलाने में भी अहम भूमिका निभायी। इतना ही नहीं, नीरज चोपड़ा ने जैवलिन में और तेजिंदर पाल सिंह तूर ने ओलंपिक स्तर का प्रदर्शन करके भविष्य के लिए उम्मीदें जगा दीं।

परिणामस्वरूप भारत इन खेलों का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहा। कुल पदकों के मामले में उसने अब तक के अपने सबसे अधिक 69 पदक जीते, जबकि स्वर्ण पदकों के मामले में 1951 के पहले एशियाई खेलों के 15 स्वर्ण पदकों की बराबरी की। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत ने पिछली बार से चार स्वर्ण और 14 रजत पदक अधिक जीते।

बेशक पदक तालिका में भारत आठवें स्थान पर रहा, लेकिन इससे उसके अगले एशियाई खेलों में शीर्ष पाँच में पहुंचने की उम्मीदें जग गई हैं। चीन, जापान तथा दक्षिण कोरिया की बादशाहत को हम स्वीकार कर चुके हैं और इंडोनेशिया को मेजबान होने का फायदा मिला है जिससे वह पेनकॉक सिलेट जैसे अपने देश की मार्शल आर्ट में 16 में से 14 स्वर्ण जीतने में सफल रहा। यह खेल न पहले कभी एशियाई खेलों का हिस्सा था और न ही आगे इसके बने रहने की कोई उम्मीद है। उज्बेकिस्तान, ईरान और चाइनीज ताईपेई पांचवें से सातवें स्थान पर रहे। इनमें उज्बेकिस्तान के भारत से सात स्वर्ण अधिक हैं, जबकि ईरान के चार और ताईपेई के दो स्वर्ण अधिक हैं। यदि भारत की कबड्डी में बादशाहत कायम रहती तो निश्चय ही इसके स्वर्ण की संख्या ईरान और ताईपेई के बराबर होती। उस स्थिति में भारत इन दोनों देशों को पाँच रजत अधिक हासिल करने के आधार पर पीछे छोड़ने में सफल हो जाता। भविष्य में हॉकी, कंपाउंड तीरंदाजी और बैडमिंटन और वेटलिफ्टिंग में भारत की स्थिति बेहतर हो सकती है।

हिप हिप हुर्रे (नवभारत टाइम्स)

एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके सबका दिल जीत लिया है। भारत ने 15 गोल्ड और 24 सिल्वर मेडल समेत 69 मेडल जीते। इससे पहले उसने 2010 में चीन के ग्वांगझू में हुए एशियन गेम्स में 65 मेडल हासिल किए थे। हमारे खिलाड़ियों ने उन खेलों में भी अपना जलवा दिखाया जिनमें भारत की अब तक कोई खास पहचान नहीं थी। हमने उस दौर को पीछे छोड़ दिया है जब माना जाता था कि देश में क्रिकेट के अलावा किसी और खेल का माहौल ही नहीं है। बाकी खेलों में भारतीय खिलाड़ी बस अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जाते हैं।

तब यहाँ तक कहा जाता था कि एथलेटिक्स जैसे खेलों के लायक भारतीयों की मनोदैहिक संरचना ही नहीं है। खैर उस एथलेटिक्स में भी हमें इस बार शानदार सफलता मिली है। हेप्टाथलॉन में स्वप्ना बर्मन ने देश को पहली बार गोल्ड मेडल दिलाया। करीब पाँच दशकों के बाद अरपिंदर सिंह ने तिहरी कूद (ट्रिपल जंप) में गोल्ड मेडल जीता। एशियाड में टेबल टेनिस, बैडमिंटन, नौकायन और महिला कुश्ती में भारतीयों के सफल होने की बात दूर की कौड़ी मानी जाती थी, लेकिन इस बार हमने इन क्षेत्रों में भी झंडे गाड़े और कई अन्य क्षेत्रों में कड़ी चुनौती पेश की। ब्रिज जैसे अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय खेल में भी भारतीय खिलाड़ियों ने गोल्ड जीतकर सबको चकित किया। देश को मेडल दिलाने में युवा खिलाड़ियों का जबर्दस्त योगदान रहा। 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीतने वाले सौरभ चौधरी महज 16 साल के हैं। ट्रैप इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाले लक्ष्य की उम्र 19 साल है। डबल ट्रैप में सिल्वर मेडल जीतने वाले शार्दुल विहान 15 साल के हैं। यह इस बात का संकेत है कि नई पीढ़ी अलग-अलग खेलों में रुचि ले रही है और उसे समुचित प्रशिक्षण मिलने लगा है। कई खिलाड़ी तो बेहद पिछड़े इलाकों और कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि से आए हैं, मगर उनके जज्बे में कोई कमी नहीं है। इस बार सबसे बड़ा उलटफेर था कबड्डी में। एशियन गेम्स में कबड्डी का गोल्ड मेडल भारतीय टीम के लिए तय माना जाता था। लेकिन इस बार पुरुष और महिला दोनों ही टीमों ने निराश किया।

इस पर विचार होना चाहिए कि दूसरे देश हमसे सीखकर हमें ही कैसे हरा रहे हैं? हमें अपनी तैयारी और मजबूत करनी होगी। यह बात तो तय है कि समाज में खेल को लेकर एक पॉजिटिव माहौल बन गया है। सरकार की जागरूकता का असर दिख रहा है। विदेशी कोच लाने का प्रयोग सफल हुआ है। कई नई अकादमियाँ खुलीं हैं जिनका युवाओं को फायदा मिल रहा है। लेकिन खेलों को प्रोत्साहन देने के प्रयासों में और गति लाने की जरूरत है। आज हरियाणा जैसे राज्य से ही काफी ज्यादा खिलाड़ी आ रहे हैं। खेलों के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर देश भर में फैलाना होगा। नौकरशाही संबंधी बाधाएँ भी दूर करनी होंगी, तभी ओलंपिक में भी हमें झोली भरकर मेडल मिल सकेंगे।

अभावों की टीस से सुनहरी चमक तक (दैनिक ट्रिब्यून)

अभावों की टीस आँखों में आँसू तो लाती ही है मगर उससे मुक्ति के एहसास से भी अश्रुधारा बहने लगती है। जकार्ता में संपन्न एशियाई खेलों में बेटी स्वप्ना बर्मन को कामयाबी की छलांग से लक्ष्य के करीब पहुंचते देख माँ बाशोना इतनी भाव-विभोर हुई कि दहाड़ मार-मार कर रोने लगी। फिर उसने खुद को घर में बनाये काली के मंदिर में कैद कर लिया। इस दौरान वह उस स्वर्णिम अवसर को नहीं देख पाई जब बेटी के गले में हेप्टाथलॉन स्पर्धा जीतने पर सोने का मेडल पहना तिरंगा लहराया गया। माँ के रुदन का यह वीडियो सोशल मीडिया में खासा वायरल हुआ, जो बताता है कि कष्टों से मुक्ति की छटपटाहट कितनी हृदयविदारक होती है।

इस बार ज्यादातर नए चैंपियन सामने आए। चाहे वह शॉटपुट में तेजिंदर सिंह तूर हों, हेप्टाथलान में स्वप्ना सरकार या 1500 मीटर में जिनसन जॉनसन और 800 मीटर में मंजीत। इसी तरह जूनियर से सीनियर में आई हिमा दास का इन खेलों में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाना रहा हो या फिर मिल्खा सिंह के रिकॉर्ड को इस सीजन में दो बार सुधारने वाले मोहम्मद अनस का बरसों बाद 400 मीटर रेस में रजत जीतना रहा हो। इसी तरह मंजीत सिंह ने 800 मीटर रेस में केरल के जिनसन जॉनसन सहित सभी एथलीटों को हराकर यह साबित कर दिया कि हरियाणा और पंजाब के एथलीट केवल फील्ड स्पर्धाओं तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ट्रैक स्पर्धा में केरल के नंबर एक एथलीट और बाकी दिग्गजों को पीछे छोड़ने का भी माद्दा रखते हैं।

हालाँकि दूती चंद को महिलाओं की सौ और 200 मीटर, अरपिंदर सिंह को पुरुषों की ट्रिपल जंप और जिनसन जॉनसन को पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में कड़ी प्रतियोगिता की कमी का फायदा मिला। हालाँकि जॉनसन ने रियो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता से बेहतर टाइमिंग दिए, लेकिन यह भी सच है कि रियो में इस स्पर्धा का प्रदर्शन शताब्दी के सबसे कमजोर प्रदर्शनों में से एक था। असल बात यह थी कि इस स्पर्धा में 2002 के एशियाई खेलों के बाद से सबसे हल्की प्रतियोगिता देखने को मिली थी, जिसका जॉनसन को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से दूर रहते हुए भी फायदा मिला।

कुश्ती में 1976 में भारत को करतार सिंह और राजेंदर सिंह ने स्वर्ण मेडल दिलाए थे। इस बार बजरंग और विनेश ने स्वर्ण जीतकर बरसों पुराने प्रदर्शन की याद ताजा करा दी। इसी तरह पीटी ऊषा से लेकर ट्रिपल जंपर मोहिंदर पाल सिंह गिल और श्रीराम सिंह जैसे एथलीटों के बरसों पुराने प्रदर्शन को इस बार दोहराया गया। एक अच्छी बात यह भी है कि इस बार भारत का प्रदर्शन ओलंपिक स्पोर्ट्स में काफी अच्छा रहा। यही शिकायत पिछले वर्षों में सामने आती रही है। मगर इस बार ब्रिज के स्वर्ण को छोड़कर भारत ने सभी स्वर्ण ओलंपिक खेल स्पर्धाओं में ही जीते। भारतीय खिलाड़ियों के कई स्पर्धाओं के प्रदर्शन में ओलंपिक पदक की आहट दिखाई दी।

जर्मन कोच के साथ ज्यादातर समय फिनलैंड में बिताने वाले नीरज चोपड़ा ने रियो ओलंपिक के रजत पदक के काफी करीब प्रदर्शन किया और वह लगातार डायमंड लीग में भाग लेकर दुनिया के शीर्ष एथलीटों के बीच अपने प्रदर्शन को सुधारने में जुटे हुए हैं। इसी तरह तेजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉटपुट में अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके ओलंपिक के लिए उम्मीदें जगा दी हैं। तूर का 20.75 मीटर का प्रदर्शन रियो ओलंपिक के टॉप पाँच खिलाड़ियों में आता है। ये दोनों एथलीट भविष्य के सितारे हैं और उनके प्रदर्शन से ओलंपिक में पदक की उम्मीदें जगी हैं।

यह उजला प्रदर्शन कुछ खेलों में भारत के लिए सबक भी है जैसे भारत को वेटलिफ्टिंग, तैराकी, गोताखोरी, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, वॉलीबाल, बास्केटबॉल, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, केनोइंग और क्याकिंग, तलवारबाजी, गोल्फ, पेनकॉक सिलाट और साइक्लिंग में खाली हाथ लौटना पड़ा है। तीरंदाजी को भारत की विरासत कहा जाता है, मगर आज तक भारत को इस खेल की ओलंपिक स्पर्धा में एक भी वैयक्तिक पदक नसीब नहीं हुआ है।

हालाँकि इस बार पदक जीतने वाले ज्यादातर खिलाड़ी निजी स्तर पर कड़ी मेहनत से आगे बढ़े हैं। इन्हें अगर भविष्य में भारतीय खेल व्यवस्था से भी भरपूर सहयोग मिले तो निश्चय ही भारत अगले एशियाई खेलों में टॉप पाँच में होगा और एक आयोजन से कम से कम आठ से दस खिलाड़ी ओलंपिक स्तर के तैयार होते दिखाई देंगे। जरूरत है ऐसी ही प्रतिभाओं को सहेजने की और नई प्रतिभाओं को आगे लाने की।

सचमुच एक रिक्शा चालक की बेटी का इस मुकाम तक पहुंचना किसी तिलिस्मी कहानी से कम नहीं है। उस पर 'कोढ़ में खाज' यह कि पिता पंचन बर्मन ने एक स्ट्रोक के बाद चारपाई पकड़ ली और माँ चाय बागान में मजदूरी करके बेटी को सपने सच करने में लगी रही। माँ बोशाना कहती है कि हम स्वप्ना की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाये, उसके लिये ट्रेनिंग के लिये पैसे जुटाने भी मुश्किल थे। मगर उसने कभी शिकायत नहीं की।

स्वप्ना के संघर्ष और मुश्किलों की शृंखला यहीं खत्म नहीं होती। कुदरत ने भी उसके साथ न्याय नहीं किया था। उसके पैरों में बारह उंगलियां थीं। आम जीवन में भले ही ये ज्यादा परेशानी न पैदा करती हो मगर एक खिलाड़ी के लिये बारह उंगलियों के साथ दौड़ना, वह भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में आसान नहीं था। भले ही अब स्वप्ना ने उस भारतीय मिथक को सच साबित किया हो, जिसमें एक पैर में छह उंगली वाले को भाग्यशाली माना जाता है, मगर उसका सफर इतना भी आसान न था। साइंस की भाषा में इसे पॉलिडैक्टिली कहते हैं, जो जन्म से होता है। जो जन्म के समय किसी जीन की बनावट में बदलाव आने से होता है। एक खिलाड़ी के लिये इसके साथ दौड़ना मुश्किल होता है। उसके नाप के जूते नहीं मिलते। यही वजह है कि उसे कई प्रतियोगिताओं में बिना जूते के बाहर कर दिया जाता था। स्वप्ना के परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि महँगे जूते मंगवा सके। जब भी जूतों की दुकान में जाती, उसके पैर के साइज के जूते नहीं मिलते, क्योंकि उसे आगे से चौड़े जूते चाहिए होते थे। कई बार जूतों की वजह से वह नहीं चुनी गई। घर में जूतों के लिये पैसे नहीं थे तो इलाज तो दूर की कौड़ी थी। बाद में किसी रिश्तेदार की मदद से ऑर्डर देकर जूते मंगवाये गये।

स्वप्ना को दुख इस बात का भी रहा कि एशियाड की तैयारी के वक्त उसके दोस्तों ने उसे नकार दिया। वे कहते थे कि जकार्ता जाकर क्या करेगी, तेरे बस का पदक जीतना नहीं है। उसकी गरीबी और पैरों की वजह से उसे हिकारत से देखा जाता। वह बताती कि कई बार दिन-रात लोगों की टिप्पणियों से आहत होकर रोती रही। फिर उसने संकल्प लिया कि जो लोग उसे पदक का दावेदार नहीं मान रहे हैं, वह उन लोगों को गलत साबित करेगी। स्वप्ना ने एक मुलाकात में कहा भी कि अपनी तैयारी के दिनों में मैं नकारात्मक लोगों से घिरी थी। जिससे मनोबल प्रभावित होता है। फिर मेरे कोच ने कहा, 'स्वप्ना तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम निश्चित रूप से पदक लेकर आओगी।' आज उसके जीवन में रोशनी है।

स्वप्ना जिन मुश्किलों से निकलकर सफलता के मुकाम तक पहुंची है, वह उसके लिये आसान नहीं थी। एशियाई चैंपियनशिप और एशियाड के बीच वह चोटिल हो गई थी। टखने की चोट के बावजूद वह ट्रेनिंग करती रही। कैंप के दौरान दोस्तों ने नकार दिया था कि वह पदक नहीं जीत सकती, मगर उसने कभी हार नहीं मानी।

भारत में बहुत कम लोग हेप्टाथलॉन के बारे में जानते हैं। यह खेल आसान नहीं है। स्वप्ना इस खेल में स्वर्ण पदक लाने वाली पहली भारतीय महिला है। यह खेल सात चरण में होता है। जिसमें सौ मीटर फर्राटा दौड़, हाई जंप, शॉटपुट, दो सौ मीटर की दौड़, लांग जंप, जेवलिन थ्रो और आठ सौ मीटर की दौड़। स्वप्ना ने चीनी खिलाड़ी को हराकर यह खिताब जीता। बावजूद इसके कि उसके दाँत में असहनीय दर्द था। उसे जबड़े पर बैंडेज चिपकाना पड़ा ताकि वह बेहतर खेल सके। पहले पिछड़ने के बाद उसने 6026 अंक हासिल करके चीनी खिलाड़ी को हराया।

अभावों व मुश्किलों से जूझने वाली स्वप्ना को जीतने के बाद भी विसंगति झेलनी पड़ी। पश्चिम बंगाल सरकार ने उसे महज दस लाख रुपये दिये, जबकि अन्य राज्यों में करोड़ों रुपए दिये जा रहे हैं। मगर वह

Committed To Excellence

जहाँ और भी हैं जकार्ता से आगे (दैनिक ट्रिब्यून)

ऐसे वक्त जबकि हमारा राजनीतिक नेतृत्व कीचड़ उछाल प्रतिस्पर्धा में ही उलझा है, हमारे खिलाड़ियों ने जकार्ता एशियाड में देश का मान बढ़ा कर बता दिया है कि भारत के असली रत्न कौन हैं। यह सही है कि आबादी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर होने के बावजूद भारत 'एशियाड' में भी पदक तालिका में आठवें स्थान पर नजर आया, लेकिन मत भूलिए कि पदक आबादी के अनुपात में नहीं मिलते, वे तो खेल के मैदान में अपने जीवट और कौशल से जीतने पड़ते हैं। जकार्ता एशियाड का सबसे उजला पहलू यही रहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि जीवट में वे किसी से कम नहीं। हां, कौशल निखारने के लिए उच्चस्तरीय प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और सुविधाओं की दरकार अवश्य है। दरअसल जकार्ता एशियाड में 15 स्वर्ण पदकों समेत कुल 69 पदक जीत कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारत का 1951 के पहले ही एशियाड में 15 स्वर्ण पदक जीतना भी बताता है कि देश के नौनिहालों में प्रतिभा-क्षमता की कमी कभी नहीं रही। हां, उस प्रतिभा को कम उम्र में ही पहचान कर तराशते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्षमता में तब्दील कर सकने वाला तंत्र हम आज तक विकसित नहीं कर पाये, वरना हमारे कई राज्यों से भी कम आबादी वाले देश अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं की पदक तालिका में हमसे ऊपर नजर नहीं आते।

इसके बावजूद अगर हमारे खिलाड़ियों ने जकार्ता में यादगार प्रदर्शन करते हुए देश को रिकॉर्ड 69 पदक जितवाये हैं तो जश्न तो बनता है। 15 स्वर्ण पदक तो हमने पहले एशियाड में भी जीते थे, लेकिन यह पहली बार है जब 24 रजत भी जीते हैं। बेशक 2010 के एशियाड में भी भारत ने 65 पदक जीते थे, लेकिन जकार्ता की उपलब्धि 4 पदकों की वृद्धि से भी कहीं बड़ी है। इसलिए भी कि इंचियोन में हम दो स्वर्ण पदकों समेत महज 13 पदकों पर सिमट गये थे। और इसलिए भी कि जकार्ता में 16 साल के सौरभ से लेकर 60 साल के प्रणब बर्मन तक ने भारत की शान बढ़ायी। 15 साल का शार्दुल विहान भी पदक जीतने में पीछे कहाँ रहा। पदकों की संख्या का महत्त्व अपनी जगह है, लेकिन भविष्य की दृष्टि से उससे भी कहीं ज्यादा महत्त्वपूर्ण है कि किस तरह की विषम पृष्ठभूमि से आये खिलाड़ियों ने किस तरह गैर परंपरागत खेलों में पदक जीते। जिस स्वप्ना बर्मन ने हेप्टाथलॉन में देश के लिए पहला स्वर्ण जीता, उसका मजदूर परिवार जिस गांव में रहता है, वहाँ जाने के लिए अब रातोंरात सड़क बनायी जा रही है, ताकि उसकी उपलब्धियों पर अपनी पीठ थपथपाते हुए हमारे राजनेता घर जाकर साथ फोटो खिंचवा सकें। याद रहे कि जकार्ता या उसके अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक जीत कर भारत की शान बढ़ाने वालों में विषम पृष्ठभूमि से आने वाली स्वप्ना अकेली नहीं है। 16 साल के निशानेबाज सौरभ के पास साल भर पहले तक अभ्यास के लिए अपनी पिस्तौल तक नहीं थी। नतीजतन पिता को कर्ज लेकर खरीदनी पड़ी। कहने का अर्थ यह भी कि जकार्ता में रिकॉर्ड संख्या में पदक हमारे खेल तंत्र की बदौलत नहीं, इसके बावजूद आये हैं।

60 साल से टेबल टेनिस एशियाई खेलों में शामिल है, पर जकार्ता में पहली बार भारत के हिस्से दो कांस्य पदक आ पाये। जकार्ता में पहली बार एशियाड में शामिल किये गये ब्रिज में भी भारत खाली हाथ नहीं लौटा। हमारे हिस्से एक स्वर्ण और दो कांस्य पदक आये। कुश्ती में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी विनेश फौगाट के पदक की चमक अपनी जगह है, पर महिला बैडमिंटन में पी. वी. सिंधु के रजत और साइना नेहवाल के कांस्य पदक का महत्त्व भी कम नहीं। अमित सरकारी नौकरी पाकर संतुष्ट है। भारत के स्टार मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हेप्टाथलॉन में स्वर्ण जीतने वाली स्वप्ना बर्मन के लिये इनामी राशि बढ़ाने की मांग की है। वहीं स्वप्ना कहती है कि मीडिया से मुझे दस लाख व सरकारी नौकरी मिलने की खबर मिली है। लोग कह रहे हैं कि इनाम की रकम कम है। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। मैं इससे खुश हूँ।

नकद इनाम में असमानता (अमर उजाला)

इंडोनेशिया में भारत 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य के साथ कुल 69 पदक जीतकर आठवें स्थान पर रहा। यह एशियाई खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। आजकल पदक विजेता खिलाड़ियों को राज्यों द्वारा नकद इनाम देने की घोषणाओं का दौर चल रहा है। पर इन घोषणाओं में इतनी असमानता है कि पदक जीतने वाले कुछ खिलाड़ियों में हीन भावना आ सकती है कि वे किसी राज्य विशेष से ताल्लुक क्यों नहीं रखते, क्योंकि वहाँ ज्यादा नकद इनाम मिलता है। यह देश में खेलों की प्रगति के लिहाज से अच्छा नहीं है।

हरियाणा और ओडिशा के खिलाड़ियों के लिए पदक जीतना किस्मत बदलने वाला साबित हो रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों की किस्मत पदक जीतने पर भी नहीं बदल पा रही। स्वर्ण पदक विजेताओं बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को हरियाणा सरकार ने तीन-तीन करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। वहीं दुती चंद के 100 और 200 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने पर ओडिशा सरकार ने प्रति पदक डेढ़ करोड़ यानी कुल तीन करोड़ रुपये देने की घोषणा की। पर हेप्टाथलान में स्वर्ण पदक जीतने वाली स्वप्ना बर्मन को पश्चिम बंगाल सरकार ने 10 लाख रुपये और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है।

कई बार घोषणाओं के बाद भी अमल होने में समय लग जाता है। इस बार 3,000 मीटर स्टीपल चेज में रजत पदक जीतने वाली रायबरेली की सुधा सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 लाख रुपये और राजपत्रित अधिकारी की नौकरी देने की घोषणा की। सुधा सिंह ने 2010 के ग्वांग झू एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तब उन्होंने सरकार को नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। पर नौकरी संबंधी उनकी पुरानी फाइल सरकारी गलियारों में घूम रही है और अब नौकरी की नई घोषणा हो गई है!

सबसे कम उम्र में स्वर्ण जीतने वाले निशानेबाज सौरभ चौधरी को उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 लाख रुपये देने की घोषणा की, तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज राही सरनोबत को भी महाराष्ट्र सरकार ने 50 लाख रुपये देने की घोषणा की। साफ है कि कुछ रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को मिले नकद इनाम से भी कम राशि स्वर्ण पदक विजेताओं को मिल रही है।

इनामी राशि में असमानता पहली बार नहीं हो रही। 2016 के रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने रजत और साक्षी मलिक ने कांस्य जीता था। दीपा करमाकर ने जिम्नास्टिक में चौथा स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया था। सिंधु को आंध्र प्रदेश ने तीन करोड़ रुपये और एक प्लॉट दिया, तो तेलंगाना ने भी मोटी राशि दी। ऐसे ही साक्षी को हरियाणा सरकार से करोड़ों रुपये मिले। पर त्रिपुरा से ताल्लुक रखने वाली दीपा कुछ लाख में ही सिमट गई। इस साल भारत के अंडर-19 विश्व कप जीतने पर सभी खिलाड़ियों को 30-30 लाख रुपये दिए गए। पर यहाँ तो कई स्वर्ण पदक जीतने वालों को भी इतनी रकम नहीं मिली।

GS World
Committed To Excellence

पंघाल ने जिस तरह मुक्केबाजी की लाइटवेट श्रेणी में 49 कि.ग्रा. में स्वर्ण जीता, उसे कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? तेजिंदर पाल तूर ने तो शॉटपुट में नया रिकॉर्ड बनाते हुए पदक जीता। कहने का अर्थ यह कि संख्या के अलावा भी हर पदक का अपना अलग महत्त्व है क्योंकि वह कहीं-न-कहीं उज्ज्वल भविष्य की आस भी जगाता है। कहना नहीं होगा कि अगर कबड्डी, कुश्ती और हॉकी सरीखे परंपरागत खेलों में भी हम आशातीत प्रदर्शन कर पाते तो न सिर्फ पदकों की संख्या बढ़ती, बल्कि पदक तालिका में भारत का नाम भी कुछ पायदान और चढ़ जाता। यह साधारण असफलता नहीं है कि एशियाई खेलों के पहले सभी सात स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष कबड्डी टीम को जकार्ता में कांस्य पर ही संतोष करना पड़ा और स्वर्ण पदक ईरान की टीम ले गयी, जिसका कोच एक भारतीय ही था। इसी तरह महिला कबड्डी में भी दो बार स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत को जकार्ता में रजत पर ही संतोष करना पड़ा। हॉकी में भी भारत की पुरुष और महिला टीमों का प्रदर्शन, पदक जीतने के बावजूद, निराशाजनक ही रहा।

बेशक हार-जीत किसी भी खेल का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे सबक तो सीखे ही जाने चाहिए। हार का सबक सुधार है तो जीत का सबक अपनी क्षमता-संभावनाओं को पहचान कर और बेहतर प्रदर्शन की तैयारी करना। जकार्ता में जिस तरह कम उम्र के खिलाड़ियों ने भी गैर परंपरागत खेलों में पदक जीते हैं, वह भारत की बेहतर क्षमता-संभावनाओं का उज्ज्वल संकेतक है। अगर सरकार खेलसंघों को निहित स्वार्थी राजनेताओं-नौकरशाहों से मुक्त करा कर दूरगामी खेल नीति के तहत शहर ही नहीं, गांव के स्तर पर भी प्रतिभा तलाशने और फिर उन्हें निखारने का निष्पक्ष एवं विश्वसनीय तंत्र विकसित कर पाये तो उसके परिणाम 2020 के ओलंपिक में भी चौंकाने वाले निकल सकते हैं। जकार्ता में कुल जीते गये 69 पदकों में से 45 व्यक्तिगत स्पर्धाओं में आये हैं, और ज्यादातर पदक विजेता कम उम्र और ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं- ये तथ्य बहुत कुछ कहते हैं, जिसे समझने की जरूरत है। आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जकार्ता में मिले पदकों में भी हरियाणा की हिस्सेदारी एक-तिहाई है। 69 में 19 पदक हरियाणवियों ने जीते हैं। बेशक इसका श्रेय सरकार से ज्यादा हरियाणवी समाज और उसकी खेल संस्कृति को जाता है, जिससे अन्य राज्यों को प्रेरणा लेनी चाहिए। कभी खेल के मैदान में पंजाब की तूती बोलती थी। जकार्ता एशियाड में भी खिलाड़ियों की संख्या के लिहाज से हरियाणा (77) के बाद पंजाब (56) दूसरे स्थान पर ही था, लेकिन व्यक्तिगत पदक अकेले तेजिंदर पाल तूर ही जीत पाये। कहना नहीं होगा कि न सिर्फ पंजाब, बल्कि उत्तर प्रदेश-बिहार सरीखे बड़े राज्यों को भी अपने यहाँ हरियाणा जैसी खेल संस्कृति विकसित करने की जरूरत है। जाहिर है, यह काम सरकार और समाज को मिलकर ही करना होगा। खेल जीवन लंबा नहीं होता। इसलिए उसे आकर्षक और सुरक्षित बनाने के लिए खिलाड़ियों को इनाम और रोजगार, दोनों ही मिलने चाहिए, पर राज्यों की खेल नीतियों में जबरदस्त विषमता और विरोधाभास है। मसलन हरियाणा में स्वर्ण पदक विजेता को तीन करोड़ रुपये मिलते हैं तो हिमाचल में मात्र एक लाख रुपये। यही नहीं, 30 में से सिर्फ चार राज्यों में ही पदक विजेता को इनाम और नौकरी, दोनों मिलते हैं। ये तथ्य हमारे खेल तंत्र और खेल नीति को बेनकाब करने वाले हैं। जब तक यह दशा नहीं सुधरती, दिशा में बदलाव की आशा बहुत व्यावहारिक नहीं होगी। व्यक्तिगत प्रयासों को जब समाज और सरकार का समर्थन मिलेगा, तभी तो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भारत पदक तालिका में पायदान-दर-पायदान चढ़ेगा।

खिलाड़ियों के सम्मान के लिए इस असमानता को पाटना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए इनामी राशि जिस तरह तय की है, वैसी ही नीति सभी राज्यों द्वारा बनाने की जरूरत है। यह नीति समान हो, अन्यथा खिलाड़ियों में हीन भावना पनप सकती है। इंडोनेशिया में पदक जीतने वाले ज्यादातर खिलाड़ी गरीबी में गुजर-बसर कर अपने जज्बे के बूते इस मुकाम तक पहुँचे हैं। इसलिए उनके जज्बे को तोड़ने वाला कोई काम नहीं होना चाहिए।

GS World टीम...

सारांश

- कोई तीस वर्ष पहले हमने बड़े शान से एशियाड खेल दिल्ली में आयोजित किया था, जिसके लिए आलीशान स्टेडियम बने। लेकिन खेल समाप्त होने के बाद ये खंडहर बनते गए हैं, क्योंकि खेल मंत्रालय ने इनको आम खिलाड़ियों के लिए कभी खोला ही नहीं। यहाँ सिर्फ विशेष कार्यक्रम होते हैं, जिनमें विदेशी खिलाड़ी भाग लेने आते थे।
- 1990 में जब पहली बार एशियन गेम्स में कबड्डी शामिल हुई तो भारत और पाकिस्तान इसकी सबसे बड़ी ताकत थे। लेकिन यह विचित्र संयोग है कि इस बार भारत और पाकिस्तान दोनों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा।
- ईरान के कुछ इलाकों में हजारों साल से कबड्डी जैसा एक खेल खेला जाता था जिसमें 'कबड्डी-कबड्डी' की जगह 'जुझुजू' कहते थे। लेकिन यह सिर्फ मनोरंजन के लिए खेला जाता था। 21 साल पहले वहाँ इसके लिए एक नेशनल फेडरेशन की स्थापना हुई और ईरान में कबड्डी का सिलसिला चल निकला।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बयान दिया है कि अगले वर्ष तक स्कूलों में पाठ्यक्रम आधा हो जाएगा और खेल की कक्षा जरूरी हो जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी कई बार संकेत दे चुके हैं।
- भारत सरकार ऐसा मान रही है कि देश में बच्चों पर पढ़ाई का बोझ इतना ज्यादा है कि उनके पास खेलने के लिए समय नहीं बचता है, तो पढ़ाई को आधा करना होगा। यदि शिक्षा विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं, तो काश! यह काम पहले हो गया होता।
- केन्द्र सरकार का दूसरा कदम होगा- खेल की क्लास को जरूरी बनाना। यह भी एक मुश्किल काम है। नियम तो यह भी है कि बिना खेल मैदान या खेल सुविधा के स्कूल नहीं खुल सकते, लेकिन उसका पालन नहीं होता है। देश में ज्यादातर निजी स्कूल ऐसे हैं, जिनके पास खेल के मैदान नहीं है, वे कैसे खेल को अनिवार्य बनाएंगे?
- जकार्ता में चल रहे एशियाई खेलों में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल कर पदक तालिका में भारत को एक और सम्मान दिलाया। यह एक बड़ी उपलब्धि इस लिहाज से है कि एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत को सोने का तमगा मिला।

- एशियाड में इस बार भारत को जैवलिन थ्रो, शॉटपुट, हेप्टाथलान, पुरुष 1500 मीटर और लाइट-फ्लाइवेट मुक्केबाजी में एशियाई खेलों के इतिहास का पहला स्वर्ण पदक हासिल हुआ। राही सरनोबत इन खेलों की निशानेबाजी स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली अब तक की पहली भारतीय महिला खिलाड़ी रहीं। घुड़सवारी में भारत को 42 साल बाद रजत पदक हासिल हुआ और इतने ही वर्षों बाद भारत को कुश्ती में दो स्वर्ण मिले। बैडमिंटन की वैयक्तिक स्पर्धा में भारत को 36 साल बाद पदक हासिल हुए। टेबल टेनिस में दो कांस्य पदक जीतने के साथ ही भारत ने इस खेल में अब तक के सूखे को समाप्त किया। मंजीत सिंह ने 800 मीटर की दौड़ में 36 साल बाद भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। इसी तरह दूती चंद ने महिलाओं की सौ मीटर और मोहम्मद अनस ने पुरुषों की 400 मीटर की स्पर्धा में भारत को 32 साल बाद रजत पदक दिलाए।
- महिला हॉकी टीम ने 20 साल बाद रजत अपने नाम किया, जबकि हाल में विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला हिमा दास ने 400 मीटर दौड़ में न सिर्फ राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ रजत जीता, बल्कि भारत को इन खेलों का छठा रिले स्वर्ण दिलाने में भी अहम भूमिका निभायी।
- परिणामस्वरूप भारत इन खेलों का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहा। कुल पदकों के मामले में उसने अब तक के अपने सबसे अधिक 69 पदक जीते, जबकि स्वर्ण पदकों के मामले में 1951 के पहले एशियाई खेलों के 15 स्वर्ण पदकों की बराबरी की। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत ने पिछली बार से चार स्वर्ण और 14 रजत पदक अधिक जीते।
- बेशक पदक तालिका में भारत आठवें स्थान पर रहा, लेकिन इससे उसके अगले एशियाई खेलों में शीर्ष पाँच में पहुंचने की उम्मीदें जग गई हैं। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया की बादशाहत को हम स्वीकार कर चुके हैं और इंडोनेशिया को मेजबान होने का फायदा मिला है जिससे वह पेनकॉक सिलेट जैसे अपने देश की मार्शल आर्ट में 16 में से 14 स्वर्ण जीतने में सफल रहा।
- एक अच्छी बात यह भी है कि इस बार भारत का प्रदर्शन ओलंपिक स्पोर्ट्स में काफी अच्छा रहा। यही शिकायत पिछले वर्षों से सामने आती रही है। मगर इस बार ब्रिज के स्वर्ण को छोड़कर भारत ने सभी स्वर्ण ओलंपिक खेल स्पर्धाओं में ही जीते।
- एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके सबका दिल जीत लिया है। भारत ने 15 गोल्ड और 24 सिल्वर मेडल समेत 69 मेडल जीते। इससे पहले उसने 2010 में चीन के ग्वांगझू में हुए एशियन गेम्स में 65 मेडल हासिल किए थे।
- 15 स्वर्ण पदक तो हमने पहले एशियाड में भी जीते थे, लेकिन यह पहली बार है जब 24 रजत भी जीते हैं। बेशक 2010 के एशियाड में भी भारत ने 65 पदक जीते थे, लेकिन जकार्ता की उपलब्धि 4 पदकों की वृद्धि से भी कहीं बड़ी है। इसलिए भी कि इंचियोन में हम दो स्वर्ण पदकों समेत महज 13 पदकों पर सिमट गये थे।
- 60 साल से टेबल टेनिस एशियाई खेलों में शामिल है, पर जकार्ता में पहली बार भारत के हिस्से दो कांस्य पदक आ पाये। जकार्ता में पहली बार एशियाड में शामिल किये गये ब्रिज में भी भारत खाली हाथ नहीं लौटा। हमारे हिस्से एक स्वर्ण और दो कांस्य पदक आये।
- जकार्ता में कुल जीते गये 69 पदकों में से 45 व्यक्तिगत स्पर्धाओं में आये हैं, और ज्यादातर पदक विजेता कम उम्र और ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैंख्रये तथ्य बहुत कुछ कहते हैं, जिसे समझने की जरूरत है। आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जकार्ता में मिले पदकों में भी हरियाणा की हिस्सेदारी एक-तिहाई है। 69 में 19 पदक हरियाणवियों ने जीते हैं।
- जकार्ता एशियाड में भी खिलाड़ियों की संख्या के लिहाज से हरियाणा (77) के बाद पंजाब (56) दूसरे स्थान पर ही था, लेकिन व्यक्तिगत पदक अकेले तेजिंदर पाल तूर ही जीत पाये।
- खेल जीवन लंबा नहीं होता। इसलिए उसे आकर्षक और सुरक्षित बनाने के लिए खिलाड़ियों को इनाम और रोजगार, दोनों ही मिलने चाहिए, पर राज्यों की खेल नीतियों में जबरदस्त विषमता और विरोधाभास है। मसलन हरियाणा में स्वर्ण पदक विजेता को तीन करोड़ रुपये मिलते हैं तो हिमाचल में मात्र एक लाख रुपये। यही नहीं, 30 में से सिर्फ चार राज्यों में ही पदक विजेता को इनाम और नौकरी, दोनों मिलते हैं। ये तथ्य हमारे खेल तंत्र और खेल नीति को बेनकाब करने वाले हैं।
- आजकल पदक विजेता खिलाड़ियों को राज्यों द्वारा नकद इनाम देने की घोषणाओं का दौर चल रहा है। पर इन घोषणाओं में इतनी असमानता है कि पदक जीतने वाले कुछ खिलाड़ियों में हीन भावना आ सकती है कि वे किसी राज्य विशेष से ताल्लुक क्यों नहीं रखते, क्योंकि वहाँ ज्यादा नकद इनाम मिलता है। यह देश में खेलों की प्रगति से लिहाज से अच्छा नहीं है।
- खिलाड़ियों के सम्मान के लिए इस असमानता को पाटना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए इनामी राशि जिस तरह तय की है, वैसी ही नीति सभी राज्यों द्वारा बनाने की जरूरत है। यह नीति समान हो, अन्यथा खिलाड़ियों में हीन भावना पनप सकती है। इंडोनेशिया में पदक जीतने वाले ज्यादातर खिलाड़ी गरीबी में गुजर-बसर कर अपने जज्बे के बूते इस मुकाम तक पहुँचे हैं।

एशियन गेम्स

- एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रत्येक चार वर्ष बाद आयोजित होने वाली बहु-खेल प्रतियोगिता है जिसमें केवल एशिया के विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं।
- इन खेलों का नियामन एशियाई ओलम्पिक परिषद द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक परिषद के पर्यवेक्षण में किया जाता है। प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान के लिए स्वर्ण, दूसरे के लिए रजत और तीसरे के लिए कांस्य पदक दिए जाते हैं, जिस परम्परा का शुभारम्भ 1951 में हुआ था।

- प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली (भारत) में किया गया था, जिसने 1972 में पुनः इन खेलों की मेजबानी की।
- एशियाई खेलों के नवीनतम संस्करण 2018 में इण्डोनेशिया के जकार्ता तथा पालेमबांग नगरों में सम्पन्न हुए। अगला संस्करण 2022 में होगा जो चीन के हांगझोऊ नगर द्वारा आयोजित किया जायेगा।
- अट्ठारहवें एशियाई खेल, जो कि जकार्ता पालेमबांग 2018 के नाम से भी जाने जाते हैं, सम्पूर्ण एशिया की सबसे बड़ी बहुखेल प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन 18 अगस्त से 2 सितम्बर, 2018 के मध्य इण्डोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग शहरों में किया जायेगा।
- ऐसा पहली बार है जब एशियाई खेल दो नगरों जकार्ता (जो कि पूर्व में 1962 एशियाई खेलों का आयोजन कर चुका है) तथा दक्षिण सुमात्रा प्रान्त की राजधानी पालेमबांग में आयोजित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त आयोजन स्थल दोनों नगरों के समीप स्थित बानदुंग तथा बांतेन में भी हैं। उद्घाटन व समापन समारोह जकार्ता के गेलोरा बुंग कर्णो स्टेडियम में आयोजित होंगे।
- पहली बार ई स्पोर्ट्स तथा कैनोए पोलो को भी प्रदर्शनी खेलों के रूप में शामिल किया गया है। ई स्पोर्ट्स को 2022 एशियाई खेलों में मुख्य खेलों में शामिल किया जायेगा।
- वियतनाम की राजधानी हनोई को वास्तविक रूप से मेजबान चुना गया था जिसने बोली के दौरान सुराबया तथा दुबई को पछाड़ा था। इस नगर को आधिकारिक रूप से 2012 को मेजबान चुना गया था, मगर मार्च 2017 से वियतनाम की इतने बड़े स्तर के आयोजन सम्पन्न कराने की क्षमता पर प्रश्न उठने लगे। यह चिन्ता मुख्य रूप से अपेक्षित बजट US+150 मिलियन को लेकर थी।
- अप्रैल 2014 को वियतनामी प्रधानमन्त्री गुयेन तन दुंग हनोई का मेजबानी से नाम वापस लेने की अधिकारिक रूप से घोषणा की। उन्होंने इसके लिये मुख्य रूप से कम तैयारियों तथा आर्थिक मंदी का हवाला दिया। वियतनाम पर किसी प्रकार का जुर्माना भी नहीं लगाया गया।
- हनोई के आयोजन से नाम वापसी के पश्चात् एशिया ओलम्पिक समिति (ओसीए) ने कहा कि इण्डोनेशिया, चीन व संयुक्त अरब अमीरात मेजबानी पाने के सशक्त दावेदार हैं। चूँकि इण्डोनेशियाई नगर सुरबया बोली में दूसरे स्थान पर रहा था। इस कारण से उसकी दावेदारी प्रबल थी और चयनित होने की अवस्था में वह इन खेलों की मेजबानी को तैयार भी था।
- फिलीपीन्स तथा भारत ने भी आयोजन में रुचि दिखायी लेकिन भारत अपनी दावेदारी प्रस्तुत नहीं कर सका क्योंकि ओसीए ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी से अंतिम तिथि बढ़ाने के बावजूद भी कोई भी जवाब नहीं मिला।
- 2018 एशियाई खेलों के प्रतीक का पहली बार अनावरण 9 सितम्बर, 2015 को देश के राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर किया गया। इसका प्रतीक चिह्न इण्डोनेशिया के दुर्लभ पक्षी पारादाइसा पर आधारित था।
- इसकी आलोचना होने पर आयोजकों ने इस आकृति को जनवरी 2016 में वापस ले लिया। इसकी अंतिम आकृति जुलाई 2016 को जारी हुई जिसका शीर्षक 'एशिया की उर्जा' था जो कि गेलोरा बुंग कर्णो स्टेडियम की प्रतिकृति के ऊपर छपा था, जिसका प्रमुख उद्देश्य एशियाई देशों के मध्य एकता को प्रतिबिम्बित करना था।
- सी दिन इन खेलों के चिह्न के साथ-साथ तीन शुभंकर भी जारी हुए जो भिन-भिन पक्षी, बवियन हिरण अतुंग तथा जावी गैण्डा काका थे। ये तीनों ही क्रमशः देश के पूर्वी, मध्य तथा पश्चिमी भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ ही वे क्रमशः रणनीति, गति तथा ताकत को भी दर्शाते हैं।
- जुलाई 2018 में इण्डोनेशियाई एशियाई खेल आयोजन समिति ने पदक की आकृतियों का अनावरण किया, जिसमे एशियाई खेलों का प्रतीक तथा बाटिक तरीके से सभी इण्डोनेशियाई क्षेत्रों की सांस्कृतिक विविधता और उनके मध्य संगठन को दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त इसके माध्यम से अट्ठारहवें एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की सांस्कृतिक, धार्मिक तथा नस्ली विविधता को भी दर्शाया गया है
- एशियाई ओलम्पिक परिषद के सभी 46 सदस्यों ने इन खेलों में भाग लिया। कुछ स्पर्धाओं में उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की एकीकृत टीम ने हिस्सा लिया, जैसा कि उन्होंने पहले 2018 के शीतकालीन ओलम्पिक के दौरान भी किया था। दोनों देशों ने उद्घाटन तथा समापन समारोह में भी एकीकृत ध्वज के अन्तर्गत भाग लिया
- यह 1951 के बाद भारत का एशियाई खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। यानी भारत ने स्वर्ण पदकों के मामले में 67 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।
- साल 1951 में हुए एशियाई खेलों को पहले एशियाई खेल कहा जाता है। इनका आयोजन दिल्ली में 4 से 11 मार्च के बीच हुआ था। इन्हें फर्स्ट एशियाड भी कहा जाता है।
- आयोजन समिति ने एशिया के लगभग सभी देशों को न्योता भेजा था मगर चीन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था, जबकि कश्मीर विवाद के कारण पाकिस्तान ने हिस्सा लेने से इंकार कर दिया था।
- इन खेलों में भारत समेत 11 देशों के 189 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। मेडल टेली में जापान सबसे ऊपर था और उसके बाद भारत दूसरे नंबर पर था। जापान को 24 गोल्ड, 21 सिल्वर और 15 कांस्य पदकों के साथ कुल 60 पदक मिले थे, वहीं भारत को 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य पदकों के साथ 41 पदक मिले थे।
- जकार्ता में चल रहे एशियाई खेलों में स्वर्ण पदकों के मामले में जहाँ भारत ने 1951 के रिकॉर्ड की बराबरी की हैं, वहीं मेडलों की कुल संख्या के आधार पर भी उसने इन खेलों के इतिहास में अपना बेस्ट रिकॉर्ड बनाया है।
- 15 स्वर्ण, 24 रजत और 29 कांस्य पदकों को मिलाकर भारत के कुल पदकों की संख्या 69 हो गई है। इससे पहले भारत ने साल 2010 में चीन के ग्वांगझू में हुए एशियाई खेलों में 65 मेडल हासिल करके अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था।
- पिछले एशियाई गेम्स (2014) में भारत 57 पदक ही जीत पाया था, जिनमें 11 स्वर्ण पदक थे। भारत दक्षिण कोरिया के इंचियोन में हुए खेलों में आठवें नंबर पर रहा था।

* * *

PT / Mains - प्रश्न

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. जकार्ता में हुए एशियाई खेलों में भारत के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में सोने का तमगा जीता?
   (a) वरुण
   (b) वर्षा गौतम
   (c) अभिषेक वर्मा
   (d) नीरज चोपड़ा

   (उत्तर-D)

2. 2018 एशियाई खेलों का प्रतीक चिह्न क्या आधारित किया गया था?
   (a) हाथी
   (b) पारादाइसा
   (c) होदोरी
   (d) पोपो एवं कुक्कू

   (उत्तर-B)

3. एशियाई खेलों-2018 में पदक तालिका में भारत का कौन-सा स्थान है?
   (a) तीसरा
   (b) पांचवाँ
   (c) आठवाँ
   (d) दसवाँ

   (उत्तर-C)

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. एशियाई खेल, 2018 में प्रथम स्थान पर चीन रहा है।
   2. प्रथम एशियाई खेल 1952 में भारत में सम्पन्न हुए थे।
   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

   (उत्तर-C)

5. किस भारतीय राज्य का 2018 के एशियाई खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है?
   (a) हरियाणा
   (b) उत्तर प्रदेश
   (c) पंजाब
   (d) तमिलनाडु

   (उत्तर-A)

6. हाल ही में सम्पन्न हुए एशियाई खेल-2018 के संदर्भ में आगामी ओलम्पिक खेलों के लिए भारत की तैयारियों पर चर्चा करें।

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न

1. निम्नलिखित में से कौन-सा शहर एशियाई खेलों के लिए 1951 से 2006 तक सर्वाधिक बार मेजबान रहा है?
   (a) दिल्ली
   (b) बैंकॉक
   (c) टोक्यो
   (d) बीजिंग

   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2007, उत्तर-B)

2. निम्नलिखित में से कौन एक फुटबॉल क्लब नहीं है?
   (a) आर्सेनल
   (b) एस्टॉन क्लिा
   (c) चेल्सीया
   (d) मोंटे कार्लो

   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2009, उत्तर-D)

3. निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
   (a) बारबोश स्पॉटाकोवा : जेवलिन थ्रो
   (b) पामेला जेलिमो : वेटलिफ्टिंग
   (c) सान्या रिचर्ड्स : स्प्रिंट
   (d) येलेना ईसईनबायेवा : पोल वॉल्ट

   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2009, उत्तर-B)

4. खिलाड़ी ओलंपिक्स में व्यक्तिगत विजय और देश के गौरव के लिए भाग लेते हैं। वापसी पर, विजेताओं को विभिन्न संस्थाओं द्वारा नकद प्रोत्साहनों की बौछार की जाती है। प्रोत्साहन के तौर पर पुरस्कार कार्यविधि के तर्काधार के मुकाबले, राज्य प्रायोजित प्रतिभा खोज और उसके पोषण के गुणावगुण पर चर्चा कीजिए।

   (IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-2, वर्ष-2014)

GS World
Committed To Excellence

एक साथ चुनाव की संभावना

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-2 (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

आम चुनाव अगले साल अप्रैल-मई में संभावित है, वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम विधान सभा के चुनाव भी इस साल के अंत में होने हैं। गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार एक साथ लोकसभा और विधान सभा चुनाव करवाने के पक्ष में है। केंद्र ने इसके पीछे तर्क दिया है कि एक साथ होने से सरकार के खर्च में कमी आएगी और राजस्व की बचत होगी। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार-पत्रों 'दैनिक जागरण' तथा 'दैनिक ट्रिब्यून' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

एक साथ चुनाव की बात कहकर पीएम मोदी ने इसे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत बताया (दैनिक जागरण)

प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में एक साथ चुनाव कराने को लेकर हो रही चर्चा को लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत बताकर एक तरह से इस मसले को नए सिरे से उभारने का ही काम किया है। यह इसलिए उल्लेखनीय है, क्योंकि चंद दिन पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा था कि कानूनी ढाँचे का निर्माण किए बिना एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि फिलहाल एक साथ चुनाव की कोई संभावना नहीं।

प्रधानमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त के विचारों को विरोधाभासी नहीं समझा जाना चाहिए। जहाँ प्रधानमंत्री एक साथ चुनाव पर बहस को जारी रखने की पैरवी कर रहे हैं, वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त इस बहस को किसी अंजाम तक पहुँचाने की जरूरत रेखांकित कर रहे हैं। इस जरूरत की पूर्ति इस मुद्दे पर स्वस्थ बहस से ही संभव है। विडंबना यह है कि स्वस्थ बहस के नाम पर आरोप-प्रत्यारोप की संकीर्ण राजनीति अधिक हो रही है। जो राजनीतिक दल एक साथ चुनाव के विचार से सहमत नहीं वे कोई ठोस तर्क देने के बजाय यह कहने में लगे हुए हैं कि सरकार लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है।

कुछ नेता साथ-साथ चुनाव को क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के लिए खतरा बता रहे हैं तो कुछ केवल विरोध के लिए विरोध जताने में लगे हुए हैं। ऐसे लोग यह जानने-समझने के लिए भी तैयार नहीं हैं कि स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक लोकसभा और विधान सभाओं के चुनाव एक साथ ही होते रहे। यदि पहले एक साथ चुनाव कराना संभव था तो अब क्यों नहीं है? इस सवाल का कोई ठोस जवाब अभी तक सामने नहीं आ सका है।

अब जब यह करीब-करीब स्पष्ट है कि आगामी लोकसभा चुनावों के साथ विधान सभाओं के चुनाव होने की संभावना बहुत क्षीण है तब बेहतर यह होगा कि अगले से अगले आम चुनावों के साथ विधान सभाओं के चुनाव कराने पर स्वस्थ दृष्टिकोण से बहस पर ध्यान केंद्रित किया जाए। ऐसा करते समय राजनीतिक दलों को अपने चुनावी हितों के साथ-साथ राष्ट्रीय हितों पर भी ध्यान देना होगा। वे इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि बार-बार चुनाव होते रहने से केवल राष्ट्रीय संसाधनों पर ही बोझ नहीं पड़ता, बल्कि राजनीतिक विमर्श एक संकुचित दायरे तक ही सीमित रहता है। इसके चलते राजनीतिक दल राष्ट्रीय महत्त्व के मसलों पर नीर-क्षीर ढंग से विचार करने के बजाय चुनावी लाभ लेने की होड़ में फँसे रहते हैं। ऐसा करके एक तरह से वे अपना और साथ ही देश का भी समय जाया करते हैं।

सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने उठाई मत पत्र से चुनाव कराने की मांग (दैनिक जागरण)

निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव सुधारों पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने मत पत्र से चुनाव कराने की जो मांग की उसे गैर-जरूरी मांग के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा लगता है कि कुछ विपक्षी दलों ने जनता के मन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रति संशय पैदा करने की ठान ली है। शायद यही कारण है कि उनकी ओर से ऐसे सवाल उछाले गए कि खराब ईवीएम से केवल भाजपा को ही वोट क्यों जाते हैं? इस सवाल का कोई जवाब इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि यह सवाल ही दुष्प्रचार का एक हिस्सा है।

ईवीएम को लेकर कैसे-कैसे दुष्प्रचार होते रहे हैं और किस तरह मीडिया का एक हिस्सा भी उसमें शामिल होता है, इसका एक उदाहरण पिछले साल उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों के दौरान तब मिला था, जब सहारनपुर की एक निर्दलीय प्रत्याशी इस सफेद झूठ के साथ सामने आई थी कि उसके हिस्से में तो खुद उसके घरवालों के ही वोट नहीं दर्ज हुए। उसकी शिकायत को सही मानकर खूब हवा दी गई, लेकिन यह सामने आते ही सबको सांप सूंघ गया कि उसे 87 वोट हासिल हुए हैं। एक दुष्प्रचार तो दिल्ली विधान सभा में ही किया गया था।

आखिर कौन भूल सकता है कि खुद को इंजीनियर बताने वाले एक विधायक ने किस तरह ईवीएम सरीखे एक खिलौने के जरिये यह साबित करने का स्वांग किया था कि इस मशीन के जरिये वोट इधर-उधर किए जा सकते हैं? सभी को यह भी याद होगा कि इन इंजीनियर साहब के साथ-साथ अन्य दलों के प्रतिनिधि किस तरह ईवीएम से छेड़छाड़ करने की निर्वाचन आयोग की चुनौती को स्वीकार करने से पीछे हट गए थे?

यह समझ आता है कि राजनीतिक दल ईवीएम में और सुधार की जरूरत जताएँ और एक प्रतिशत से अधिक वोटों की जाँच की मांग करें, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं कि वे आगामी आम चुनाव मत पत्र से कराने पर जोर दें। यह तो एक तरह से देश को बैलगाड़ी युग में ले जाने वाली मांग है। क्या विपक्षी दल इससे परिचित नहीं कि मत पत्र से मतदान के दौरान किस तरह बड़े पैमाने पर धांधली होती थी? यदि वे भूल गए हों तो हाल में पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनावों का स्मरण करें, जब तृणमूल कार्यकर्ताओं ने मत पत्र लूटने के साथ मतपेटियाँ तालाबों और कुओं में फेंक दी थीं।

आखिर यह ढिठाई नहीं तो और क्या है कि निर्वाचन आयोग के समक्ष तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि ने यह कहने में भी संकोच नहीं किया

यदि राजनीतिक दल हर दो-चार माह में चुनाव की चिंता करते रहेंगे तो फिर वे राष्ट्रीय हितों की सुध कब लेंगे? प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र के लिए उत्तम परंपराएँ विकसित करने में अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान का स्मरण करते हुए यह भी कहा कि वह खुले मन से चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते थे। बेहतर होगा कि प्रधानमंत्री यह देखें कि एक साथ चुनाव के मसले पर खुले मन से चर्चा के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? इसी के साथ उन्हें अन्य राजनीतिक सुधारों को भी आगे बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी तमाम लोकतांत्रिक परंपराएँ निष्प्राण-निरर्थक-सी होकर रह गई हैं।

कि मत पत्र सुरक्षित हैं और साफ-सुथरी चुनाव प्रक्रिया में उनका बहुत योगदान है। ईवीएम को बदनाम करने के पहले विपक्षी दल यह याद रखें तो बेहतर कि दिल्ली, बिहार, पंजाब आदि राज्यों के विधान सभा चुनाव और हाल के कई उपचुनावों के नतीजे इसी मशीन से ही निकले हैं? समस्या केवल यह नहीं कि ईवीएम को संदिग्ध बताया जा रहा है, बल्कि यह भी है कि निर्वाचन आयोग की साख पर प्रहार किया जा रहा है। आयोग के बारे में राहुल गांधी का ताजा कथन दुष्प्रचार की राजनीति का हिस्सा ही नजर आता है।

चुनावी बिसात पर मोहरों की चाल (दैनिक ट्रिब्यून)

एक साथ चुनाव कराने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात पूरी होगी या फिर अलग-अलग लोकसभा-विधान सभा चुनाव की विपक्ष की मुराद, यह आने वाला समय ही बतायेगा, लेकिन चुनाव की बिसात बिछना शुरू हो गयी है। लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री को जो कुछ कहना था, वह तो कहा ही गया, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद का घटनाक्रम भी यही बताता है कि चुनावी बिसात पर कोई भी चाल चलने में, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। वाजपेयी आजाद भारत के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक थे, जिनकी अपने दल ही नहीं, देश के बाहर भी खासी प्रतिष्ठा थी, लेकिन जिस तरह से उनकी अस्थिकलश यात्राएँ देश भर में निकाली गयीं, उससे राजनीतिक विरोधियों को सवाल उठाने का मौका तो मिला। यह सवाल पूरी तरह अस्वाभाविक नहीं है कि अगर 1984 में राजीव गांधी और कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की शहादत से उपजी सहानुभूति लहर पर लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता था तो अब नरेंद्र मोदी और भाजपा क्या वैसा ही अटल जी के निधन के बाद बने माहौल में करने की दिशा में नहीं बढ़ रहे?

बेशक अटल एक अनूठे राजनेता थे। इस तथ्य से भी कौन इंकार कर सकता है कि उनका व्यक्तित्व जनसंघ और भाजपा के साथ-साथ विराट हुआ, लेकिन राष्ट्रीय नेताओं को दल विशेष की सीमा में नहीं बांधना चाहिए। इससे सबसे ज्यादा अन्याय उन नेताओं के साथ ही होता है। अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर देश भर में शोक जैसा माहौल दिखा, वैसा नयी पीढ़ी ने तो शायद ही पहले देखा हो। याद रखें कि बमुश्किल छह साल प्रधानमंत्री रह पाये वाजपेयी के प्रति देश का यह अनुराग-आदर तब था, जब वह पिछले 14 साल से सत्ता से दूर थे और लगभग एक दशक से सार्वजनिक जीवन से। कांग्रेस पर अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि उसने नेहरू परिवार के अलावा अन्य सभी नेताओं को नजरअंदाज किया। यह आरोप लगाने वालों में भाजपा अग्रणी रही है, पर अब जबकि वह खुद केंद्र समेत ज्यादातर राज्यों में सत्ता में है, कांग्रेस की गलतियां दोहराने के बजाय उनसे सबक सीखना चाहिए। नेहरू परिवार का ज्यादा महिमामंडन गलत था, तो अब उसे खारिज करना और भी बड़ी गलती होगी। हां, उन नेताओं को अवश्य उनका देय सम्मान मिलना चाहिए, जिन्हें दलगत संकीर्णता या परिवार विशेष के प्रति निष्ठा के चलते नजरअदांज कर दिया गया था।

दरअसल भाजपा और मोदी की रणनीति यह भी तय करेगी कि इसी साल संभावित राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधान सभाओं के चुनाव भी समय पर होंगे या नहीं। अगर एक साथ चुनाव की दिशा में बढ़ना तय हुआ तो संभव है कि इन तीन राज्यों के विधान सभा चुनाव कुछ माह विलंब से और अगले लोकसभा चुनाव समय से कुछ माह पहले कराये जायें। बहरहाल चुनाव जब भी हों, चुनावी बिसात बिछना शुरू हो गयी है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतभेद पर भी भारी मनभेद के जो बड़े उदाहरण दिये जा सकते हैं, उनमें से एक उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और मायावती का है। बसपा संस्थापक कांशीराम ने सपा के साथ चुनावी गठबंधन से सत्ता का जो प्रयोग किया था, वह आश्चर्यजनक रूप से सफल रहा, लेकिन उसका अंत बेहद कटु रहा। बकौल मायावती : मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने मीराबाई स्टेट गेस्ट हाउस में गुंडे भेज कर उन्हें मरवाने की साजिश रची, जिसे लाल जी टंडन और कलराज मिश्र जैसे भाजपा नेताओं की मदद से नाकाम किया गया।

मुलायम-माया की निजी रंजिश दो दशक तक राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बनी रही, लेकिन पहले लोकसभा और फिर विधान सभा चुनाव में भाजपा लहर में हुए सपा-बसपा के सफाये ने बुआ मायावती और भतीजे अखिलेश को अतीत की कड़वाहट भुला कर अस्तित्व बचाने के लिए साथ आने पर मजबूर कर दिया है। यह मजबूरी का साथ भी कितना मजबूत हो सकता है, इसका संकेत उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हुए उपचुनावों से साफ मिल जाता है। अगर भाजपा किसी भी तरह सपा-बसपा गठबंधन होने से नहीं रुकवा पायी और कांग्रेस-रालोद भी गठबंधन का हिस्सा बन गये तो 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में पासा पलटने में देर नहीं लगेगी। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार देश का दूसरा बड़ा राज्य है। वहाँ पिछले लोकसभा चुनाव में तो नीतिश कुमार के अलगाव के बावजूद रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी के साथ मिलकर भाजपा अपनी नैया पार लगाने में सफल हो गयी थी, लेकिन विधान सभा चुनाव में नीतिश-लालू-कांग्रेस के महागठबंधन को सत्ता पाने से नहीं रोक पायी।

अंतर्कथाओं में कितना सच है, यह तो उनके किरदार जानें, पर अंततः नीतिश कुमार जनता दल (यूनाइटेड) और सरकार समेत राजग में लौट आये। बिहार की सत्ता में भागीदारी के अलावा भी भाजपा के लिए यह बड़ा राजनीतिक दाँव होना चाहिए था, लेकिन बाद में हुए उपचुनाव से ऐसा साबित नहीं हुआ। तमाम बदनामी के बावजूद लालू बिहार की राजनीति में प्रासंगिक बने हुए हैं। दोनों बेटों में दरार का सच तो परिवार जाने, पर तेजस्वी राजनीतिक दांव-पेच में तो लालू के वारिस बनते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि लालू के जेल जाने के बावजूद न सिर्फ कांग्रेस ने राजद से रिश्ता बरकरार रखा है, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा के पाला बदलने की अटकलें भी जारी हैं। हाल में खीर प्रकरण से भाजपा भी बेचैन नजर आयी। नीतिश का भाजपा के साथ आना बिहार के समीकरण में महत्त्वपूर्ण तो है, पर उपेंद्र कुशवाहा अगर पाला बदल कर राजद-कांग्रेस के साथ चले जाते हैं तो समीकरण नये सिरे से बन सकते हैं। फिर रामविलास पासवान की राजनीति की बाबत तो कोई कुछ नहीं कह सकता। हाल के दशकों में केंद्र में किसी की भी सरकार रही हो, पासवान उसमें मंत्री अवश्य रहे हैं। फिर लोकसभा चुनाव हार चुके पासवान को राज्यसभा में भेजने का लालू का अहसान भी है।

देश के दो बड़े राज्यों में चुनावी बिसात पर मोहरों की यह चाल इसलिए और भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि देश के ज्यादातर राज्यों में अपने राजनीतिक चरम और सत्ता तक पहुँच चुकी भाजपा के ग्राफ में अब उतार की आशंकाएँ प्रबल नजर आ रही हैं। लगभग साढ़े चार साल के शासन के बाद भी ब्रांड मोदी की वैल्यू में गिरावट आयी है या नहीं, और आयी है तो कितनी, यह बहस का विषय हो सकता है, क्योंकि मोदी का विकल्प राष्ट्रीय स्तर पर फिलहाल तो नजर नहीं आता, लेकिन इसका अर्थ यह हरगिज नहीं होना चाहिए कि विधान सभा चुनावों में भी भाजपा की नैया ब्रांड मोदी के सहारे ही पार लग जायेगी। बेशक एक साथ चुनाव की सोच के मूल में एक मंशा यह भी है कि राज्य सरकारों की नाकामी पर मोदी नाम का पर्दा पड़ जाये, लेकिन लगभग पाँच दशक बाद एक साथ चुनाव होने पर मतदाता कैसे मतदान करेंगे, यह भी विश्वासपूर्वक नहीं कहा सकता। अलग-अलग चुनाव होने पर तो भाजपा की मुश्किलें बढ़ना तय है ही। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा को कांग्रेस से मुकाबला मुश्किल लग रहा है। दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भाजपा को बढ़त की उम्मीद अवश्य है, पर उत्तर भारतीय राज्यों में संभावित भारी नुकसान की भरपाई वहाँ से हो पायेगी, इसमें शक है। इसलिए भी आने वाले दिनों में चुनावी बिसात पर मोहरों की चाल देखना और भी दिलचस्प होगा।

GS World टीम...

सारांश

- प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में एक साथ चुनाव कराने को लेकर हो रही चर्चा को लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत बताकर एक तरह से इस मसले को नए सिरे से उभारने का ही काम किया है। यह इसलिए उल्लेखनीय है, क्योंकि चंद दिन पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा था कि कानूनी ढाँचे का निर्माण किए बिना एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि फिलहाल एक साथ चुनाव की कोई संभावना नहीं।
- जहाँ प्रधानमंत्री एक साथ चुनाव पर बहस को जारी रखने की पैरवी कर रहे हैं, वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त इस बहस को किसी अंजाम तक पहुँचाने की जरूरत रेखांकित कर रहे हैं। इस जरूरत की पूर्ति इस मुद्दे पर स्वस्थ बहस से ही संभव है।
- जो राजनीतिक दल एक साथ चुनाव के विचार से सहमत नहीं वे कोई ठोस तर्क देने के बजाय यह कहने में लगे हुए हैं कि सरकार लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है। कुछ नेता साथ-साथ चुनाव को क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के लिए खतरा बता रहे हैं तो कुछ केवल विरोध के लिए विरोध जताने में लगे हुए हैं। ऐसे लोग यह जानने-समझने के लिए भी तैयार नहीं कि स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक लोकसभा और विधान सभाओं के चुनाव एक साथ ही होते रहे।
- यदि राजनीतिक दल हर दो-चार माह में चुनाव की चिंता करते रहेंगे तो फिर वे राष्ट्रीय हितों की सुध कब लेंगे? प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र के लिए उत्तम परंपराएं विकसित करने में अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान का स्मरण करते हुए यह भी कहा कि वह खुले मन से चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते थे।
- निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव सुधारों पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने मत पत्र से चुनाव कराने की जो मांग की उसे गैर-जरूरी मांग के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा लगता है कि कुछ विपक्षी दलों ने जनता के मन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रति संशय पैदा करने की ठान ली है।
- यह समझ आता है कि राजनीतिक दल ईवीएम में और सुधार की जरूरत जताएँ और एक प्रतिशत से अधिक वोटों की जाँच की मांग करें, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं कि वे आगामी आम चुनाव मत पत्र से कराने पर जोर दें। यह तो एक तरह से देश को बैलगाड़ी युग में ले जाने वाली मांग है।
- दरअसल भाजपा और मोदी की रणनीति यह भी तय करेगी कि इसी साल संभावित राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधान सभाओं के चुनाव भी समय पर होंगे या नहीं। अगर एक साथ चुनाव की दिशा में बढ़ना तय हुआ तो संभव है कि इन तीन राज्यों के विधान सभा चुनाव कुछ माह विलंब से और अगले लोकसभा चुनाव समय से कुछ माह पहले कराये जायें।
- बेशक एक साथ चुनाव की सोच के मूल में एक मंशा यह भी है कि राज्य सरकारों की नाकामी पर मोदी नाम का पर्दा पड़ जाये, लेकिन लगभग पाँच दशक बाद एक साथ चुनाव होने पर मतदाता कैसे व्यवहार-मतदान करेंगे, यह भी विश्वासपूर्वक नहीं कहा सकता।
- अलग-अलग चुनाव होने पर तो भाजपा की मुश्किलें बढ़ना तय है ही। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा को कांग्रेस से मुकाबला मुश्किल लग रहा है। दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भाजपा को बढ़त की उम्मीद अवश्य है, पर उत्तर भारतीय राज्यों में संभावित भारी नुकसान की भरपाई वहाँ से हो पायेगी, इसमें शक है।

भारतीय चुनाव आयोग

- भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध-न्यायिक संस्थान है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए गया था।
- भारत निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को की गई थी। आयोग ने अपनी स्वर्ण जयंती 2001 में मनाई थी।
- भारत के संविधान ने संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल तथा भारत के राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के संचालन की पूरी प्रक्रिया का अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण का उत्तरदायित्व भारत निर्वाचन आयोग को सौंपा है।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष तक, या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक का होता है। उनका वही स्तर होता है जो कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का होता है तथा उन्हें उनके समतुल्य ही वेतन और अनुलाभ मिलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से, केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है।
- राजनीतिक दल विधि के अधीन निर्वाचन आयोग के साथ पंजीकृत है। आयोग उन पर सामयिक अंतरालों पर संगठन संबंधी निर्वाचन करवाने हेतु जोर देकर उनके कामकाज में आंतरिक दलीय लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। निर्वाचन आयोग के साथ इस प्रकार पंजीकृत

राजनैतिक दलों को निर्वाचन आयोग, अपने द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, साधारण निर्वाचनों में राजनैतिक दलों के मतदान प्रदर्शन के आधार पर राज्यीय एवं राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान करता है।

- निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायित्व है कि वह निर्वाचनों का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन करवाये। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, राज्य विधान सभा के चुनाव करवाता है, निर्वाचक नामावली तैयार करवाता है, राजनैतिक दलों का पंजीकरण करता है, राजनैतिक दलों का राष्ट्रीय, राज्य स्तर के दलों के रूप मे वर्गीकरण, मान्यता देना, दलों-निर्दलीयों को चुनाव चिन्ह देना, सांसद/विधायक की अयोग्यता (दल बदल को छोड़कर) पर राष्ट्रपति/राज्यपाल को सलाह देता है।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल भारत में आम चुनाव तथा राज्य विधान सभाओं के चुनाव में आंशिक रूप से 1999 में शुरू हुआ तथा 2004 से इसका पूर्ण इस्तेमाल हो रहा है।

भारतीय चुनाव

- भारतीय संसद में राष्ट्रप्रमुख, भारत के राष्ट्रपति- और दो सदन शामिल हैं जो विधानमंडल होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव पाँच वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचकमंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संघ और राज्य के विधानमंडलों के सदस्य शामिल होते हैं।
- भारत की संसद के दो सदन हैं। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, 543 सदस्यों का चयन पाँच वर्षों की अवधि के लिए एकल सीट निर्वाचन क्षेत्रों से होता है और दो सदस्यों को एंग्लो-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है
- राज्यों की परिषद (राज्यसभा) में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 233 सदस्यों का चयन छह वर्ष की अवधि के लिए होता है, जिसमें हर दो साल में एक तिहाई अवकाश ग्रहण करते हैं। इन सदस्यों का चयन राज्य और केंद्रशासित (संघ) प्रदेशों के विधायकों द्वारा किया जाता है। निर्वाचित सदस्यों का चयन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल अंतरणीय मत के माध्यम से किया जाता है। बारह नामित सदस्यों को आमतौर पर प्रख्यात कलाकारों (अभिनेताओं सहित), वैज्ञानिकों, न्यायविदों, खिलाड़ियों, व्यापारियों और पत्रकारों और आम लोगों में से चुना जाता है।
- भारत में 1967-68 तक लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। 1967-68 में कुछ विधान सभाओं के समय से पहले विघटित हो जाने के कारण यह प्रक्रिया बाधित हो गई। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिये।
- अलग समय पर चुनाव सरकारी मशीनरी पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं क्योंकि सशस्त्र बल व केंद्रीय कर्मचारियों की चुनाव में होने वाली नियुक्ति से उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। एकीकृत चुनाव कराने से उन्हें इससे राहत मिलेगी।
- चुनाव में बड़ी मात्रा में धन का निवेश, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कारणों में सबसे ऊपर है। इस क्रम में चुनाव की बारंबारता में रोक, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत कदम साबित हो सकता है।
- नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक में पीएम मोदी ने कहा था, हमने लोकसभा और विधान सभा के चुनाव एकसाथ कराने पर विचार-विमर्श का आह्वान कई पहलुओं को ध्यान में रखकर किया है, जिसमें वित्तीय बचत व संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की बात शामिल हैं।
- आजादी के बाद शुरुआती सालों में लोकसभा और विधान सभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। हालांकि, इसके लिए कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं थी। लेकिन सुविधा के नाते 1952 के पहले आम चुनाव के साथ ही राज्यों की विधान सभा के लिए भी चुनाव हुए थे। तकरीबन 15 साल तक विधान सभाओं के चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ चले लेकिन बाद में यह चक्र गड़बड़ा गया, क्योंकि कुछ राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला और कुछ सरकारें अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले गिर गई।
- लोकसभा और विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराने का सबसे बड़ा फायदा यही बताया जा रहा है कि इससे राजनीतिक स्थिरता आएगी। क्योंकि अगर किसी राज्य में कार्यकाल खत्म होने के पहले भी कोई सरकार गिर जाती है या फिर चुनाव के बाद किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो वहाँ आनन-फानन में नहीं बल्कि पहले से तय समय पर ही चुनाव होगा।
- पाँच साल तक किसी राज्य को अपनी विधान सभा के गठन के लिए इंतजार नहीं करना पड़े, इसके लिए यह सुझाव दिया जा रहा है कि ढाई-ढाई साल के अंतराल पर दो बार चुनाव हों। आधे राज्यों की विधान सभा का चुनाव लोकसभा के साथ हो और बाकी राज्यों का इसके ढाई साल बाद। अगर बीच में कहीं कोई राजनीतिक संकट पैदा हो और चुनाव की जरूरत पड़े तो वहाँ फिर अगला चुनाव ढाई साल के चक्र के साथ हो। विधि आयोग ने 1999 में अपनी 117वीं रिपोर्ट में राजनीतिक स्थिरता को ही आधार बनाकर दोनों चुनावों को एकसाथ कराने की सिफारिश की थी।
- लोकसभा और विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराने के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह दिया जा रहा है कि इससे चुनावी खर्च में काफी बचत होगी। केंद्र सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि दोनों चुनाव एक साथ कराने से तकरीबन 4,500 करोड़ रुपये की बचत होगी।
- एक साथ चुनाव होने से कई स्तर पर प्रशासकीय सुविधा की बात भी कही जा रही है। अलग-अलग चुनाव होने से अलग-अलग वक्त पर आदर्श आचार संहिता लगाई जाती है। इससे होता यह है कि विकास संबंधित कई निर्णय नहीं हो पाते हैं।
- लोकसभा और विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराने के पक्ष में यह बात भी कही जा रही है कि इससे चुनावों में आम लोगों की भागीदारी भी बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि देश में बहुत-से लोग हैं जिनका वोटर कार्ड जिस पते पर बना है, वे उस पते पर नहीं रहते बल्कि रोजगार या अन्य वजहों से दूसरी जगहों पर रहते हैं। अलग-अलग चुनाव होने की वजह से वे अपनी मूल जगह पर मतदान करने नहीं जाते। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो इनमें से बहुत सारे लोग एक बार में दोनों चुनाव होने की वजह से मतदान करने अपने मूल स्थान पर आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो चुनावों में मत प्रतिशत और दूसरे शब्दों में आम लोगों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ सकती है।

PT / Mains - प्रश्न

संभावित प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
   1. भारत निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है।
   2. संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1949 को की गई थी।
   3. भारत के संविधान ने संसद, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं गवर्नर के पदों के निर्वाचनों के संचालन की पूरी प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का उत्तरदायित्व भारत निर्वाचन आयोग को सौंपा है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) 1, 2 और 3 (b) 1 और 2
   (c) केवल 1 (d) 1 और 3

   (उत्तर-C)

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
   1. भारत के इतिहास में कभी भी लोकसभा, विधान सभा चुनाव एक साथ नहीं हुए।
   2. विधि आयोग ने 117 वीं रिपोर्ट में एकसाथ चुनाव कराने की अनुशंसा की।
   3. एकसाथ विधान सभा, लोकसभा चुनाव कराने का एकमात्र फायदा चुनाव खर्च में बचत मात्र है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) 1 और 3
   (c) 2 और 3 (d) केवल 2

   (उत्तर-D)

3. निम्नलिखित में कौन-से कार्य करने का उत्तरदायित्व चुनाव आयोग के पास है?
   1. राजनैतिक दलों को चुनाव प्रचार हेतु दिशा-निर्देश देना।
   2. राजनैतिक दलों का पंजीकरण करना।
   3. राजनैतिक दलों को दिये जाने वाले चंदे पर अंकुश लगाना।

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
   (a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 3
   (c) 2 और 3 (d) 1 और 3

   (उत्तर-A)

4. निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं?
   (a) ओ.पी. रावत (b) वी.एस. संपथ
   (c) नसीम जैदी (d) कुमारी आंचल

   (उत्तर-A)

5. हालिया समय में चर्चा में रह रहे 'एक देश एक चुनाव' के विषय में संभावित फायदों एवं हानियों की समीक्षा करें।

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न

1. निम्नलिखित में से कौन-सा आयोग संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया है?
   (a) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
   (b) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
   (c) चुनाव आयोग
   (d) केंद्रीय सतर्कता आयोग

   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2006, उत्तर-C)

2. भारतीय चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
   1. अधीक्षण, निर्देशित और कार्यान्वयन करना, मुक्त और निष्पक्ष चुनावों को करवाना।
   2. संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मतदाता सूची को तैयार करना।
   3. राजनीतिक दलों को पहचान देना एवं चुनाव लड़ रहे राजनीतिक दलों एवं व्यक्तियों को चुनाव चिह्न निर्गत करना।
   4. चुनावी विवादों के अंतिम निर्णय देना।

   उपर्युक्त में से कौन-से कार्य भारतीय चुनाव आयोग के हैं?
   (a) 1, 2 और 3
   (b) 2, 3 और 4
   (c) 1 और 3
   (d) 1, 2 और 4

   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2004, उत्तर-A)

3. निम्नलिखित में से कौन-सी अनुसूची दल-बदल विरोधी प्रावधानों से संबंधित है?
   (a) दूसरी अनुसूची
   (b) पाचवीं अनुसूची
   (c) आठवीं अनुसूची
   (d) दसवीं अनुसूची

   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2014, उत्तर-D)

4. "लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के एक ही समय में चुनाव, चुनाव-प्रचार की अवधि और व्यय को तो सीमित कर देंगे, परंतु ऐसा करने से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी।" चर्चा कीजिए।

   (IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-2, वर्ष-2017)

5. भारत में लोकतंत्र की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया है। सुझाए गए सुधार क्या हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने में वे किस सीमा तक महत्त्वपूर्ण हैं?

   (IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-2, वर्ष-2017)

GS World
Committed To Excellence

देश की पहली जैव जेट ईंधन संचालित उड़ान

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-3 (विज्ञान प्रौद्योगिकी) से संबंधित है।

जेट्रोफा बीज और विमानन टर्बाइन ईंधन से तेल के मिश्रण से देहरादून और दिल्ली के बीच देश की पहली जैव जेट ईंधन संचालित उड़ान सफल हुई। भारत के विमानन इतिहास में यह पहला मौका है, जब विमान में जैव ईंधन का सफल प्रयोग किया गया है। यह भारत में बायोफ्यूल से उड़ने वाली पहली फ्लाइट है। अभी तक केवल अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में यह प्रयोग सफल रहा है। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार-पत्रों 'दैनिक ट्रिब्यून' तथा 'जनसत्ता' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

उम्मीदों की उड़ान का हकीकत बनना (दैनिक ट्रिब्यून)

भारत अब उन चुनिंदा देशों की पाँत में शामिल हो गया है, जिन्होंने जैव ईंधन से विमान उड़ाने में सफलता पाई है। सस्ती उड़ान सेवा देने वाली कंपनी स्पाइसजेट ने देहरादून से दिल्ली के बीच बॉम्बार्डियर क्यू-400 विमान को जैव ईंधन से चलाने का सफल परीक्षण किया है। पेट्रोलियम वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम से आखिरकार रतनजोत (जट्रोफा) के फल से जैव ईंधन बना लिया गया। इस तकनीक को सबसे पहले अमेरिका ने हासिल किया था। इसके बाद आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा ने जैव ईंधन से विमान उड़ाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन इन देशों ने भारत को तकनीक देने से इंकार कर दिया था।

हालाँकि भारत का भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आईआईपी) 2012 में कनाडा की आंशिक मदद से कनाडा में ही जैव ईंधन से विमान उड़ाने का सफल प्रयोग कर चुका था। इस विमान को उड़ाने के बाद भारत विकासशील देशों में ऐसा पहला देश बन गया है, जिसने जैव ईंधन से विमान उड़ाने का कीर्तिमान रच दिया है। चीन और जापान फिलहाल ऐसा नहीं कर पाए हैं। विमानों में जैव ईंधन के प्रयोग से जहाँ भारत की तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी वहीं कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी।

संस्कृत में लिखी महर्षि भारद्वाज की पुस्तक 'वैमानिक शास्त्र' में सूरजमुखी के पौधे के फूलों से तेल निकालकर ईंधन बनाकर विमान उड़ाने का वर्णन है। अब रतनजोत के फलों से तेल बनाकर विमान उड़ाने का सिलसिला तेज हो गया है। भारत में जिस विमान को जैव ईंधन से उड़ाया गया है, उस रतनजोत की फसल का उत्पादन छत्तीसगढ़ के पाँच सौ किसानों ने किया है। इस उड़ान के लिए इस्तेमाल ईंधन में 75 प्रतिशत एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) और 25 प्रतिशत जैव जेट ईंधन का मिश्रण था। रतनजोत से बने इस ईंधन को पेट्रोलियम पदार्थ में बदलने का काम सीएसआईआर व भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून ने किया है। इसमें अहम भूमिका पेट्रोलियम वैज्ञानिक अनिल सिन्हा की रही है। उन्होंने 2012 में ही जट्रोफा के बीजों से बायोफ्यूल बनाने की तकनीक का पेटेंट करा लिया था।

हालाँकि जैव ईंधन से विमान उड़ाने के प्रयास एक दशक पहले से हो रहे हैं। 2008 से कई उड़ानों में जैव ईंधन का परीक्षण किए जाने का सिलसिला शुरू हुआ। 2011 में अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मैटेरियल द्वारा बायोफ्यूल को मान्यता देने के बाद से व्यावसायिक उड़ानों में इसका निरंतर इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत ने जैव ईंधन निर्माण की दिशा में अहम पहल शुरू की। डॉ. अनिल सिन्हा ने इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए 'एप्लिकेशन ऑफ बायोफ्यूल फॉर एविएशन' शीर्षक से शोध

कामयाबी की उड़ान (जनसत्ता)

पहली बार जैव ईंधन के इस्तेमाल से विमान उड़ाने में भारत ने जो कामयाबी हासिल की है, वह स्वच्छ ऊर्जा के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। सोमवार को जैव जेट ईंधन के प्रयोग से एक यात्री विमान को देहरादून से दिल्ली तक लाया गया। भारत के विमानन इतिहास में यह पहला मौका है जब विमान में जैव ईंधन का सफल प्रयोग किया गया। इस विमान में पच्चीस फीसद जैव ईंधन का उपयोग किया गया। इस उड़ान ने साबित कर दिया है कि विमानों को जैव ईंधन से उड़ाना असंभव नहीं है और यह जैव ईंधन भविष्य के बड़े ऊर्जा विकल्प के रूप में सामने आ सकता है। इस कामयाबी से भारत अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड जैसे उन पच्चीस देशों में शुमार हो गया है जो अपने यहाँ विमानों में जैव ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जटरोफा नाम की वनस्पति से यह ईंधन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और देहरादून स्थित भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने मिल कर तैयार किया है। सबसे अहम बात यह कि हम पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन का विकल्प खोजने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। हालाँकि अभी काफी कुछ किया जाना है।

जैव ईंधन तैयार करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने की जरूरत इसलिए है कि प्रदूषण कम करने का यह एक अच्छा विकल्प है। पहली बार उड़ान में जिस जैव ईंधन का प्रयोग हुआ है, वह हमारे वैज्ञानिकों की नौ साल की कड़ी मेहनत का प्रतिफल है। इस परियोजना पर पंद्रह करोड़ रुपए की लागत आई। यह ईंधन दूसरे ईंधनों के मुकाबले कार्बन और अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन भी कम करता है। इसकी खूबी यह है कि इकतालीस हजार फीट की ऊँचाई और शून्य से नीचे 47 डिग्री सेल्शियस तापमान पर यह जमेगा नहीं। इसलिए इसकी सफलता को लेकर बहुत उम्मीदें हैं। सरकार ने जल्द ही वैकल्पिक विमान ईंधन नीति घोषित करने की बात भी कही है, ताकि विमानन क्षेत्र में स्वच्छ जैविक ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। आज दुनिया के विकासशील देश वायु प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। ज्यादातर देशों में परिवहन व्यवस्था का ढाँचा पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम ईंधन पर ही निर्भर है। इसके अलावा और भी कई कामों में बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल होता है। इस समस्या से निजात स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों के विकास और इस्तेमाल से ही पाई जा सकती है।

जैव ईंधन का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि भारत की तेल आयात पर निर्भरता घटेगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। अभी देश में आठ लाख करोड़ रुपए के कच्चे तेल का आयात होता है और इसमें से तीस

Committed To Excellence

को अंजाम दिया। इस तेल को रतनजोत के अलावा ऐसे अखाद्य तेलों, लकड़ी और उसके उत्पादों, जानवरों की वसा और बायोमास से बनाया जा सकता है। इस तेल के एक हिस्से को पारंपरिक ईंधन पेट्रोल और डीजल में मिलाकर वायुयान चलाए जा सकते हैं।

अमेरिका में अनाज को सड़ाकर भी बड़ी मात्रा में जैव ईंधन बनाया जा रहा है। भारत में एक टन चावल के भूसे से 280 लीटर एथोनॉल का उत्पादन किया जा रहा है। इसका उपयोग वैकल्पिक ईंधन व ईंधन में मिश्रण के रूप में किया जाता है। इसका निर्माण भांग, गन्ना, आलू, मक्का, गेहूँ का भूसा और बाँस के छिलकों से भी किया जाता है। फसलों के जो अवशेष मनुष्य के खाने लायक नहीं होते, उससे एथोनॉल का उत्पादन सबसे अधिक होता है।

भारत सरकार ने 2009 से जैव ईंधन के प्रयोग की शुरुआत की थी। साल 2017-18 में एथोनॉल के मिश्रण से 597 मिलियन डॉलर की बचत हुई। सरकार का लक्ष्य है कि जैव ईंधन के प्रयोग से 1.74 अरब डॉलर के तेल के आयात में कमी लाई जाए। इस मकसद की पूर्ति के लिए 12 जैव ईंधन रिफाइनरियों की स्थापना की जानी है। दक्षिण एशियाई देश जो अपने तेल की 80 प्रतिशत आपूर्ति अरब देशों से तेल आयात करके करते हैं, वे इन रिफाइनरियों में 1.5 अरब डॉलर की पूंजी लगाएंगे। इससे 15000 नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद भी की जा रही है।

हजार करोड़ रुपए का तेल विमान ईंधन के लिए होता है। ऐसे में जैव ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ाते हुए पेट्रोल पर निर्भरता कम हो सकती है। कोशिश यह भी हो रही है कि जटरोफा के अलावा अखाद्य तेलों के बीजों से भी ईंधन बनाया जाए। विमानन क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार जो 'कार्ययोजना-2035' तैयार कर रही है उसमें सबसे ज्यादा जोर स्वच्छ ऊर्जा पर है। इसलिए वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती जैव ईंधन के व्यावसायिक उत्पादन की है। जैव ईंधन पर सरकार ने राष्ट्रीय नीति-2018 को मंजूरी दे दी है। अगर पेट्रोल और डीजल पर निर्भर देश की कुल ऊर्जा जरूरत में से पचास फीसद हिस्सा जैव ईंधन का उपयोग होने लगे तो यह ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी क्रांति होगी।

2007-08 में मध्य-प्रदेश सरकार ने रतनजोत के उत्पादन को प्रोत्साहित किया था। जबकि इसके बीज से तेल बनाने का कोई संयंत्र मध्य प्रदेश में आज भी नहीं है। निःशुल्क बीज देकर रतनजोत का उत्पादन कराया गया, लेकिन खरीदार नहीं मिले। नतीजतन किसानों ने इसका उत्पादन बंद कर दिया। इसके बीज जहरीले होते हैं। इस कारण 2007-08 में सैकड़ों बच्चों ने इसके फल पौष्टिक मानते हुए खा लिए। इस कारण अनेक बच्चों को अस्पतालों में भर्ती करना पड़ा। फिलहाल भारत के पास रतनजोत से ही जैव ईंधन बनाने की तकनीक है। भविष्य में नाहॉर और सैपियन नामक वनस्पतियों से जैव ईंधन बनाने की कोशिशें की जा रही हैं।

GS World टीम...

सारांश

- पहली बार जैव ईंधन के इस्तेमाल से विमान उड़ाने में भारत ने जो कामयाबी हासिल की है, वह स्वच्छ ऊर्जा के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। सोमवार को जैव जेट ईंधन के प्रयोग से एक यात्री विमान को देहरादून से दिल्ली तक लाया गया।
- भारत के विमानन इतिहास में यह पहला मौका है जब विमान में जैव ईंधन का सफल प्रयोग किया गया। इस विमान में पच्चीस फीसद जैव ईंधन का उपयोग किया गया। इस उड़ान ने साबित कर दिया है कि विमानों को जैव ईंधन से उड़ाना असंभव नहीं है और यह जैव ईंधन भविष्य के बड़े ऊर्जा विकल्प के रूप में सामने आ सकता है।
- इस कामयाबी से भारत अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड जैसे उन पच्चीस देशों में शुमार हो गया है जो अपने यहाँ विमानों में जैव ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जटरोफा नाम की वनस्पति से यह ईंधन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) और देहरादून स्थित भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने मिल कर तैयार किया है।
- जैव ईंधन तैयार करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने की जरूरत इसलिए है कि प्रदूषण कम करने का यह एक अच्छा विकल्प है। पहली बार उड़ान में जिस जैव ईंधन का प्रयोग हुआ है, वह हमारे वैज्ञानिकों की नौ साल की कड़ी मेहनत का प्रतिफल है।
- इस परियोजना पर पंद्रह करोड़ रुपए की लागत आई। यह ईंधन दूसरे ईंधनों के मुकाबले कार्बन और अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन भी कम करता है। इसकी खूबी यह है कि इकतालीस हजार फीट की ऊँचाई और शून्य से नीचे 47 डिग्री सेल्शियस तापमान पर यह जमेगा नहीं।
- सरकार ने जल्द ही वैकल्पिक विमान ईंधन नीति घोषित करने की बात भी कही है, ताकि विमानन क्षेत्र में स्वच्छ जैविक ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।
- ज्यादातर देशों में परिवहन व्यवस्था का ढाँचा पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम ईंधन पर ही निर्भर है। इसके अलावा और भी कई कामों में बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल होता है। इस समस्या से निजात स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों के विकास और इस्तेमाल से ही पाई जा सकती है।
- जैव ईंधन का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि भारत की तेल आयात पर निर्भरता घटेगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। अभी देश में आठ लाख करोड़ रुपए के कच्चे तेल का आयात होता है और इसमें से तीस हजार करोड़ रुपए का तेल विमान ईंधन के लिए होता है।
- ऐसे में जैव ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ाते हुए पेट्रोल पर निर्भरता कम हो सकती है। कोशिश यह भी हो रही है कि जटरोफा के अलावा अखाद्य तेलों के बीजों से भी ईंधन बनाया जाए। विमानन क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार जो 'कार्ययोजना-2035' तैयार कर रही है उसमें सबसे ज्यादा जोर स्वच्छ ऊर्जा पर है। इसलिए वैज्ञानिकों के

समक्ष सबसे बड़ी चुनौती जैव ईंधन के व्यावसायिक उत्पादन की है। जैव ईंधन पर सरकार ने राष्ट्रीय नीति-2018 को मंजूरी दे दी है।

- भारत अब उन चुनिंदा देशों की पांत में शामिल हो गया है, जिन्होंने जैव ईंधन से विमान उड़ाने में सफलता पाई है। सस्ती उड़ान सेवा देने वाली कंपनी स्पाइसजेट ने देहरादून से दिल्ली के बीच बॉम्बार्डियर क्यू-400 विमान को जैव ईंधन से चलाने का सफल परीक्षण किया है।
- पेट्रोलियम वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम से आखिरकार रतनजोत (जट्रोफा) के फल से जैव ईंधन बना लिया गया। इस तकनीक को सबसे पहले अमेरिका ने हासिल किया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा ने जैव ईंधन से विमान उड़ाने में कामयाबी हासिल की लेकिन इन देशों ने भारत को तकनीक देने से इनकार कर दिया था।
- हालाँकि भारत का भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आईआईपी) 2012 में कनाडा की आंशिक मदद से कनाडा में ही जैव ईंधन से विमान उड़ाने का सफल प्रयोग कर चुका था। इस विमान को उड़ाने के बाद भारत विकासशील देशों में ऐसा पहला देश बन गया है, जिसने जैव ईंधन से विमान उड़ाने का कीर्तिमान रच दिया है। चीन और जापान फिलहाल ऐसा नहीं कर पाए हैं। विमानों में जैव ईंधन के प्रयोग से जहाँ भारत की तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी वहीं कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी।
- संस्कृत में लिखी महर्षि भारद्वाज की पुस्तक 'वैमानिक शास्त्र' में सूरजमुखी के पौधे के फूलों से तेल निकालकर ईंधन बनाकर विमान उड़ाने का वर्णन है। अब रतनजोत के फलों से तेल बनाकर विमान उड़ाने का सिलसिला तेज हो गया है।
- भारत में जिस विमान को जैव ईंधन से उड़ाया गया है, उस रतनजोत की फसल का उत्पादन छत्तीसगढ़ के पाँच सौ किसानों ने किया है। इस उड़ान के लिए इस्तेमाल ईंधन में 75 प्रतिशत एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) और 25 प्रतिशत जैव जेट ईंधन का मिश्रण था।
- रतनजोत से बने इस ईंधन को पेट्रोलियम पदार्थ में बदलने का काम सीएसआईआर व भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून ने किया है। इसमें अहम भूमिका पेट्रोलियम वैज्ञानिक अनिल सिन्हा की रही है। उन्होंने 2012 में ही जट्रोफा के बीजों से बायोफ्यूल बनाने की तकनीक का पेटेंट करा लिया था।
- हालाँकि जैव ईंधन से विमान उड़ाने के प्रयास एक दशक पहले से हो रहे हैं। 2008 से कई उड़ानों में जैव ईंधन का परीक्षण किए जाने का सिलसिला शुरू हुआ। 2011 में अमेरिकन सोसायटी फॉर टेस्टिंग एंड मैटेरियल द्वारा बायोफ्यूल को मान्यता देने के बाद से व्यावसायिक उड़ानों में इसका निरंतर इस्तेमाल किया जा रहा है।
- भारत ने जैव ईंधन निर्माण की दिशा में अहम पहल शुरू की। डॉ. अनिल सिन्हा ने इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए 'एप्लिकेशन ऑफ बायोफ्यूल फॉर एविएशन' शीर्षक से शोध को अंजाम दिया। इस तेल को रतनजोत के अलावा ऐसे अखाद्य तेलों, लकड़ी और उसके उत्पादों, जानवरों की वसा और बायोमास से बनाया जा सकता है। इस तेल के एक हिस्से को पारंपरिक ईंधन पेट्रोल और डीजल में मिलाकर वायुयान चलाए जा सकते हैं।
- अमेरिका में अनाज को सड़ाकर भी बड़ी मात्रा में जैव ईंधन बनाया जा रहा है। भारत में एक टन चावल के भूसे से 280 लीटर एथोनॉल का उत्पादन किया जा रहा है। इसका उपयोग वैकल्पिक ईंधन व ईंधन में मिश्रण के रूप में किया जाता है। इसका निर्माण भांग, गन्ना, आलू, मक्का, गेहूं का भूसा और बांस के छिलकों से भी किया जाता है। फसलों के जो अवशेष मनुष्य के खाने लायक नहीं होते, उससे एथोनॉल का उत्पादन सबसे अधिक होता है।
- भारत सरकार ने 2009 से जैव ईंधन के प्रयोग की शुरुआत की थी। साल 2017-18 में एथोनॉल के मिश्रण से 597 मिलियन डॉलर की बचत हुई। सरकार का लक्ष्य है कि जैव ईंधन के प्रयोग से 1.74 अरब डॉलर के तेल के आयात में कमी लाई जाए।
- इस मकसद की पूर्ति के लिए 12 जैव ईंधन रिफाइनरियों की स्थापना की जानी है। दक्षिण एशियाई देश जो अपने तेल की 80 प्रतिशत आपूर्ति अरब देशों से तेल आयात करके करते हैं, वे इन रिफाइनरियों में 1.5 अरब डॉलर की पूंजी लगाएंगे। इससे 15000 नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद भी की जा रही है।
- 2007-08 में मध्य-प्रदेश सरकार ने रतनजोत के उत्पादन को प्रोत्साहित किया था। जबकि इसके बीज से तेल बनाने का कोई संयंत्र मध्य प्रदेश में आज भी नहीं है। निःशुल्क बीज देकर रतनजोत का उत्पादन कराया गया, लेकिन खरीदार नहीं मिले। नतीजतन किसानों ने इसका उत्पादन बंद कर दिया।
- इसके बीज जहरीले होते हैं। इस कारण 2007-08 में सैकड़ों बच्चों ने इसके फल पौष्टिक मानते हुए खा लिए। इस कारण अनेक बच्चों को अस्पतालों में भर्ती करना पड़ा। फिलहाल भारत के पास रतनजोत से ही जैव ईंधन बनाने की तकनीक है। भविष्य में नाहॉर और सैपियन नामक वनस्पतियों से जैव ईंधन बनाने की कोशिशें की जा रही हैं।

बायो-फ्यूल

- जेट्रोफा बीज और विमानन टर्बाइन ईंधन से तेल के मिश्रण ने देहरादून और दिल्ली के बीच देश की पहली जैव जेट ईंधन संचालित उड़ान को प्रेरित किया। 43 मिनट की उड़ान स्पाइसजेट के बॉम्बार्डियर क्यू-400 विमान द्वारा संचालित की गई थी, जिसमें 20 अधिकारी

और पाँच चालक दल के सदस्य थे।

- स्पाइसजेट के विमान ने 27 अगस्त, 2018 को बायोफ्यूल के इस्तेमाल से देहरादून से दिल्ली तक उड़ान भरी। स्पाइसजेट के विमान क्यू-400 को देहरादून में ही एक दिन पहले 10 मिनट तक बायो-फ्यूल के साथ उड़ाया गया. इस उड़ान के बाद इसे बायोफ्यूल द्वारा ही देहरादून से दिल्ली तक लाया गया।
- यह भारत में बायोफ्यूल से उड़ने वाली पहली फ्लाइट है। अभी तक केवल अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में यह प्रयोग सफल रहा है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च के तहत देहरादून में संचालित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने 400 किलोग्राम बायो जेट फ्यूल तैयार किया है।
- विमान के दो इंजनों में से एक में जैव जेट ईंधन का 25% और विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) का 75% मिश्रण किया गया था, जबकि अन्य इंजन केवल एटीएफ ले गए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानक एटीएफ के साथ 50% जैव ईंधन की मिश्रण दर परमिट करते हैं।
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम (आईआईपी) के साथ देहरादून में स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) प्रयोगशाला द्वारा स्वदेशी विकसित ईंधन लगभग आठ साल में बना है।
- वर्जिन अटलांटिक ने 2008 में वैश्विक स्तर पर पहली टेस्ट उड़ान के बाद संस्थान ने जैव ईंधन पर अपना प्रयोग शुरू किया। परीक्षण के समय विमान में 300 लीटर बायोफ्यूल के साथ 900 लीटर एटीएफ विमान के दाहिने विंग में भरा गया। बाएं विंग में 1200 लीटर एटीएफ इमरजेंसी के लिए रखा गया।
- जेट्रोफा को भारत में पहले जंगली अरण्डी के नाम से भी जाना जाता था। इसकी उपयोगिता एवं महत्त्व की जानकारी के अभाव में इसकी व्यापारिक तौर पर खेती नहीं की जा रही थी। विगत वर्षों से इसका उपयोग बायोडीजल के रूप में होने के कारण यह केरोसिन तेल, डीजल, कोयला, आदि के विकल्प के रूप में उभरा है। जेट्रोफा के तेल से बने डीजल में सल्फर की मात्रा बहुत ही कम होने के कारण इसको बायोडीजल की श्रेणी में रखा गया है।
- बायोफ्यूल जेट्रोपा (रतनजोत) के बीजों का उत्पाद है। जेट्रोपा यूफोर्बियेसी परिवार का सदस्य है और अमेरिकी मूल का है। स्थानीय भाषा में इसे बरगंडी भी कहते हैं। जेट्रोपा का पौधा तीन-चार मीटर ऊँचा होता है और प्रतिकूल मौसम और विपरीत जलवायु में भी फलता-फूलता है।
- केंद्र सरकार ने इसी साल चार जून को जैव ईंधन नीति 2018 घोषित की। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व बायोफ्यूल दिवस पर इस नीति को राष्ट्र को समर्पित किया। भारत सरकार ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों की कमेटी बनाई है, जिसमें छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया है।
- बायोडीजल पारंपरिक या जीवाश्म डीजल के मुकाबले एक वैकल्पिक ईंधन है। आपको बता दें कि इसे सीधे तौर पर वनस्पति तेल, पशुओं के वसा, तेल और खाना पकाने के अपशिष्ट तेल से बनाया जाता है। इन तेलों को बायोडीजल में परिवर्तित करने के लिए प्रयक्त प्रक्रिया को ट्रान्स-इस्टरीकरण कहा जाता है।
- बायोडीजल जैविक स्रोतों से प्राप्त डीजल के जैसा ही गैर-पराम्परागत ईंधन होता है। इसका नवीनीकरण ऊर्जा स्त्रोतों से बनाया जाता है। यह परम्परागत ईंधनों का एक स्वच्छ विकल्प है। इसमें कम मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ मिलाया जाता है और विभिन्न प्रकार की गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है।
- इस प्रक्रिया में वनस्पति तेल या वसा से ग्लीसरीन को निकालना होता है। इसके बाद इसमें मेथिल इस्टर और ग्लीसलीन आदि सह-उत्पाद भी मिलाए जाते हैं। बायोडीजल में हानिकारक तत्त्व सल्फर और आरोमैटिक्स नहीं मिलाए जाते हैं, जैसा कि परम्परागत ईंधनों में होता है। बायोडीजल को बनाने के लिए जरूरी चीजें जेट्रोफा तेल, मेथेनोल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड होती हैं।
- जटरोपा से बायोडीजल का उत्पादन वर्तमान में केवल बीज से हो रहा है। पौधे के तने में सेलूलोज होता है जो कि ज्वलनशील है। परन्तु सेलूलोज को ईंधन में परिवर्तित करने की तकनीक फिलहाल विकसित नहीं हुई है यद्यपि इस पर वैश्विक स्तर पर शोध चल रहा है। सेलूलोज से उत्पादन हो जाये तो बायोडीजल बनाने में लागत कम आयेगी।
- जट्रोफा गर्म मौसम और बंजर मिट्टी में उग सकता है। इसके बीज में पाए गए तेल को उच्च गुणवत्ता वाले डीजल ईंधन में परिवर्तित किया जा सकता है। चूँकि जेट्रोफा अखाद्य है, इसलिए इसका ईंधन में ही मुख्यत: उपयोग हो सकता है। इसके अलावा सूखे का सामना करने की क्षमता होना, स्वाभाविक रूप से कीट-खरपतवार से लड़ने की क्षमता और एवरेज क्वालिटी की मिट्टी में उग जाना, इसे बायोफ्यूल की दुनिया का गेम-चेंजर बनाता है। भारत में खेती के लिए उपलब्ध जमीन में से 20% से अधिक जमीन को उपर्युक्त मानकों के हिसाब से 'जट्रोफा आरक्षित' जमीन कहा जा सकता है।

भारत उन चार देशों में शामिल हो गया है, जिन्होंने बायोफ्यूल का इस्तेमाल करके हवाई जहाज उड़ाया है। बाकी तीन हैं- अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इसमें से भी केवल अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ही बायोफ्यूल का इस्तेमाल कॉमर्शियल फ्लाइट्स में हो रहा है।

PT / Mains - प्रश्न

संभावित प्रश्न

1. जैव-ईंधन परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
   1. जैव-ईंधन से विमान उड़ाने का खर्च 15 करोड़ रहा।
   2. इस कामयाबी से भारत अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे कुल 4 देशों की श्रेणी में शुमार हो गया है जहाँ विमानों में जैव-ईंधन का प्रयोग होता है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

   (उत्तर-A)

2. अभी भारत में कितने करोड़ के कच्चे तेल का आयात होता है?
   (a) आठ हजार करोड़
   (b) आठ लाख करोड़
   (c) आठ अरब करोड़
   (d) सात लाख करोड़

   (उत्तर-B)

3. निम्नलिखित में से कौन-सी कंपनी ने जैव-ईंधन से विमान उड़ाने का कीर्तिमान भारत में स्थापित किया?
   (a) एयर इंडिया
   (b) इंडिगो
   (c) स्पाइसजेट
   (d) जेट एयरवेज

   (उत्तर-C)

4. ''वैमानिक शास्त्र' पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं?
   (a) माधव आशीष
   (b) महर्षि दयानंद
   (c) तीस्ता बाघची
   (d) महर्षि भारद्वाज

   (उत्तर-D)

5. भारत की मौजूदा जैव-ईंधन नीति के संदर्भ में भारत की चुनौतियों की समीक्षा करें।

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न

1. शैवाल आधारित जैव-ईंधन का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग को बढ़ावा देने में विकासशील देशों की समस्याएँ क्या हैं?
   1. शैवाल आधारित जैव-ईंधन का उत्पादन समुद्रों में संभव है, लेकिन महाद्वीपों पर नहीं।
   2. शैवाल आधारित जैव-ईंधन उत्पादन को स्थापित करने एवं अभियांत्रिकी में उच्च स्तर की कुशलता/तकनीक की जरूरत है, जब तक निर्माण पूर्ण न हो जाए।
   3. आर्थिक रूप से संभव उत्पादन में वृहद् स्तर की सुविधाओं की स्थापना की जरूरत है जिससे पारिस्थितिक एवं सामाजिक चिंताएँ आ सकती हैं।

   नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें-
   (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
   (c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2017, उत्तर-B)

2. निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें-

समाचारों में रहने वाले		**उनका उद्भव**
1. एनेक्स-I देश	-	कार्टाजेना प्रोटोकॉल
2. सर्टिफाइड इमीशन रिडक्शन्स	-	नगोया प्रोटोकॉल
3. क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म	-	क्योटो प्रोटोकॉल

   उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सुमेलित है/हैं?
   (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
   (c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2016, उत्तर-C)

3. निम्नलिखित में से कौन-सा केंद्रीय मंत्रालय बायोडीजल मिशन (नोडल मंत्रालय के रूप में) को क्रियान्वित कर रहा है?
   (a) कृषि मंत्रालय
   (b) विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय
   (c) नये एवं पुनर्नवीकरण मंत्रालय
   (d) ग्रामीण विकास मंत्रालय

   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2008, उत्तर-D)

4. यह कहा जाता है कि भारत में देश की 25 वर्ष की आवश्यकता पूर्ति के लिए शिला-तेल और गैस का पर्याप्त भण्डार है, तथापि कार्यसूची में संपत्ति की निकासी उच्च स्थान पर नजर नहीं आती। इसकी प्राप्यता तथा आवेष्टित समस्याओं की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए।

   (IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-1, वर्ष-2013)

5. परंपरागत ऊर्जा की कठिनाइयों को कम करने के लिए भारत की 'हरित ऊर्जा पट्टी' पर एक लेख लिखिए।

   (IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-3, वर्ष-2013)

GS World
Committed To Excellence

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिका और चीन की कारोबारी में जंग छिड़ी हुई है। एक समय अमेरिका विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाता था, लेकिन आज अमेरिकी राष्ट्रपति डब्ल्यूटीओ को नुकसानदेह बता रहे हैं। अमेरिका को मुक्त व्यापार में अब विश्व के तमाम देशों से टक्कर लेनी पड़ रही है, जिसमें वह असफल हो रहा है। अपने मंतव्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने डब्ल्यूटीओ को ही खंडित करने की रणनीति बना ली है। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार-पत्रों 'बिजनेस स्टैंडर्ड' तथा 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

क्षेत्रीय व्यापार संधियाँ और मुक्त व्यापार (बिजनेस स्टैंडर्ड)

भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग संधि (सीईसीए) में आ रही धीमापन देश की मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) नीति में कमजोरी का एक और संकेत है। एफटीए वार्ता में यह धीमापन आंशिक रूप से इसलिए आ रहा है क्योंकि भारत को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समूह आसियान से दबाव का सामना करना पड़ रहा है। यह दबाव क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) को निपटाने से संबंधित है। आरसीईपी के देश पिछले छह साल से इस वार्ता में उलझे हुए हैं। यह उलझन काफी हद तक भारत की ओर से सीमित और अलग-अलग टैरिफ उदारीकरण से ताल्लुक रखती है। हाल ही में वस्तु एवं सेवा कारोबार को उदार करने के लिए ऐसी ही एक वार्ता पर जोर दिया गया। अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध के माहौल को देखते हुए आसियान के सदस्य आरईसीपी की बातचीत को समाप्त करने के अपने तय लक्ष्य के प्रति गंभीर हैं। वे नवंबर 2018 की आसियान शिखर बैठक में इस पर हस्ताक्षर चाहते हैं। काफी संभावना है कि अगर भारत पहले जैसे हालात बरकरार रखता है तो अन्य सदस्य देश बिना भारत के समझौते पर आगे बढ़ जाएँगे। देश के नीति निर्माता इस संभावना को लेकर सहज हैं लेकिन देश की एफटीए नीति की समीक्षा की आवश्यकता है, ताकि हम इस भागीदारी को लेकर सही रुख अपना सकें।

पहली बात, एफटीए को बहुपक्षीय या विश्व व्यापार संगठन की भागीदारी के बरअक्स अनैतिक नहीं माना जाना चाहिए। एफटीए एकदम वैध व्यापारिक तरीका है। इसे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड (गैट) के अनुच्छेद-24 के तहत मंजूरी प्राप्त है। इनकी प्रकृति प्राथमिकता वाली होती है और ये अधिकाधिक देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने का काम करते हैं। ये डब्ल्यूटीओ के मुक्त और निष्पक्ष व्यापार के लक्ष्य के अनुरूप ही है। कई विकसित और विकासशील देशों ने बहुपक्षीय व्यापार उदारीकरण के साथ एफटीए को अपनाकर लाभ कमाया। सन 2000 के दशक में एफटीए की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। दोहा विकास एजेंडे के तहत डब्ल्यूटीओ की प्रक्रिया धीमी पड़ने के बाद इसमें और प्रगति हुई। कई देशों को यह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार का आसान जरिया लगा। सन 2000 से 2017 के बीच क्षेत्रीय व्यापार संधियों की संख्या 79 से बढ़कर 287 हो गई। इतना ही नहीं हर वर्ष वस्तुओं ने सेवा क्षेत्र को पीछे छोड़ा। पूर्वी एशिया जो विश्व व्यापार के तीन ध्रुवों में से एक है (दो अन्य हैं यूरोप और उत्तरी अमेरिका), वहाँ 83 क्षेत्रीय समझौते प्रवर्तन में हैं। यूरोप 97 समझौतों के साथ शीर्ष पर है।

दूसरा, मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य में अमेरिका और चीन की कारोबारी जंग छाई हुई है। इस दौरान डब्ल्यूटीओ के तरजीही मुल्क

खतरे में डब्ल्यूटीओ: अमेरिका अन्य देशों से मुक्त व्यापार का मुकाबला करने में असफल (दैनिक जागरण)

एक समय अमेरिका विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभा रहा था, लेकिन आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसी डब्ल्यूटीओ को नुकसानदेह बता रहे हैं। इसे समझने के लिए पहले मुक्त व्यापार के सिद्धांत को समझें। सिद्धांत यही है कि हर एक क्षेत्र किसी खास वस्तु के उत्पादन में महारत रखता है। जैसे भुसावल में केले का उत्पादन सस्ता पड़ता है और मेरठ में चीनी का। दोनों के लिए लाभप्रद है कि भुसावल केले का उत्पादन करके मेरठ को भेजे और मेरठ चीनी का उत्पादन कर उसे भुसावल भेजे। इससे दोनों को केला और चीनी सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन अब दूसरी स्थिति को समझें, जिसमें अमेरिका लड़ाकू विमान सस्ता बनाता है और भारत दूध का उत्पादन सस्ता करता है।

मुक्त व्यापार के सिद्धांत के अनुसार अमेरिका को लड़ाकू विमानों का निर्यात करना चाहिए और भारत को दूध का। अब मान लीजिए कि अमेरिका लड़ाकू विमानों का दुनिया में इकलौता उत्पादक है और उसके एवज में वह मनचाहा दाम चाहता है। ऐसे में भारत के हित में यही होगा कि वह अपने देश में ही लड़ाकू विमान बनाए।

मुक्त व्यापार का सिद्धांत तब नाकाम हो जाता है, जब किसी विशेष देश का किसी माल पर एकाधिकार होता है जैसे लड़ाकू विमान के मामले में अमेरिका का है। 1990 के दशक में अमेरिका में नए तकनीकी आविष्कार हो रहे थे, जैसे- माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज सॉफ्टवेयर बनाया, सिस्को ने राउटर सिस्टम बनाए, एचपी ने प्रिंटर इत्यादि बनाए। अमेरिका इन एकाधिकार वाली वस्तुओं को दुनिया भर में बेचना चाहता था। तब उसके लिए मुक्त विश्व व्यापार दोहरे लाभ का सौदा था।

एक तरफ विंडोज सॉफ्टवेयर जैसे एकाधिकार वाले माल को अमेरिका मुँहमांगे दाम पर बेचकर दुनिया भर से लाभ कमाता था। दूसरी ओर, भारत से सस्ती चीनी का आयात करके लाभ उठाता था। इसीलिए अमेरिका ने उस समय मुक्त व्यापार की जोरशोर से पैरवी की और डब्ल्यूटीओ को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। पिछले कुछ समय में हालात बदल गए हैं। अब विंडोज जैसे सॉफ्टवेयर, सिस्को के राउटर या प्रिंटर जैसे माल तमाम देश बनाने लगे हैं। अमेरिका के पास एकाधिकार वाले उत्पाद कम रह गए हैं। ऐसे में अमेरिका के लिए विश्व व्यापार घाटे का सौदा हो गया है। एकाधिकार वाली वस्तुओं की संख्या कम होने से उसके पास महँगा माल बेचने के आज कम अवसर हैं। अब अमेरिका की स्थिति भुसावल और मेरठ जैसी हो गई है। अमेरिका सेब का उत्पादन करके भारत को भेज सकता है और भारत चीनी का उत्पादन कर अमेरिका को भेज सकता है।

इस प्रकार का विश्व व्यापार वास्तव में दोनों देशों के लिए लाभप्रद है, लेकिन इस स्थिति में अमेरिका और भारत के श्रमिकों के वेतन भी बराबर

के सिद्धांत की अनदेखी हुई है और इस बात ने बहुपक्षीय व्यवस्था को कमजोर किया है। अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ की विवाद निस्तारण अपीलीय संस्था को अवरुद्ध किया है। इससे भी बहुपक्षीय व्यवस्था को ठेस पहुंची है। प्रासंगिकता बनाए रखने के क्रम में डब्ल्यूटीओ अमेरिका और जापान जैसे विकसित देशों के दबाव में ई-कॉमर्स आदि को लेकर नए नियम बना सकता है। वह राज्य आपूर्ति या सब्सिडी कार्यक्रम में पारदर्शिता और सीमा को लेकर नियम प्रस्तुत कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में बहुपक्षीय व्यवस्था में भारत की भागीदारी चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। भारत पहले ही निर्यात सब्सिडी कार्यक्रम को लेकर अमेरिका द्वारा उत्पन्न विवाद से जूझ रहा है।

तीसरा, आरसीईपी को एक व्यापक समझौते के रूप में तैयार करने का विचार था, जहाँ वस्तुओं और सेवाओं को लेकर एक साथ बातचीत हो सके। परंतु फिलहाल भारत आसियान के साथ एफटीए के कारण अनावश्यक प्रभाव में आ रहा है। भारत-आसियान सेवा एफटीए पर वस्तु एफटीए के चार साल बाद हस्ताक्षर किए गए। अभी भी इसे सभी सदस्य देशों की मंजूरी का इंतजार है। वस्तु क्षेत्र के एफटीए ने द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित नहीं किया है और व्यापार संतुलन आसियान के पक्ष में है। यह भी सच है कि कुछ आसियान सदस्यों के साथ भारत के व्यापार समझौते का प्रदर्शन अन्य क्षेत्रीय देशों के समक्ष प्रदर्शन से कुछ खास अलग नहीं रहा है। भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) फिलहाल समीक्षाधीन है। भारतीय कारोबारी सख्त नियमों के चलते सीईपीए का पूरा लाभ उठा पाने में नाकामयाब रहे हैं। कोरिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा है, लेकिन भारत से कोरिया को होने वाला निर्यात स्थिर रहा है।

समीक्षा की प्रक्रिया में जहाँ नियम आसान किए जाने हैं वहीं सीईपीए का विस्तार सेवा क्षेत्र में करने की बात भी इसमें शामिल है। ये वे सेवा क्षेत्र हैं जो भारत के अनुकूल हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा क्षेत्र। चुनिंदा उत्पादों के लिए कोरियाई बाजार की पहुँच सुधारना भी इसके लक्ष्यों में शामिल है। 2011 में सीईपीए पर हस्ताक्षर के बाद से ही भारत-जापान द्विपक्षीय व्यापार में ठहराव रहा या गिरावट आई। मलेशिया के साथ व्यापार भी यही कहानी कहता है। जापान भारत में सबसे बड़ा निवेशकों में से एक है लेकिन आवक का आकार छोटा है और सीईपीए के बाद भी निवेश में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। सेवा क्षेत्र में व्यापार काफी छोटा है। भारत-सिंगापुर सीईसीए पर 2005 में हस्ताक्षर हुए थे। यहाँ शुरुआती वर्षों में वस्तु व्यापार में प्रदर्शन अच्छा रहा लेकिन सेवा व्यापार वृद्धि 2015 तक सिंगापुर के अनुकूल रही। निवेश वृद्धि इसलिए दिखी क्योंकि तीसरे मुल्कों ने सिंगापुर के जरिये निवेश किया।

भारत के लिए आरसीईपी वार्ता में मुद्दा वस्तु और सेवाओं के क्षेत्र में उदारीकरण को समान रूप से न केवल उठाना चाहिए बल्कि यह भी देखना होगा कि क्या यह भागीदारी भारत को अहम अवसर मुहैया कराती है या नहीं? चीन से आयात वृद्धि की आशंका को आरसीईपी में घबराहट का मुद्दा नहीं बनने देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा को लेकर खुलापन घरेलू उत्पादकों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे-जैसे अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध बढ़ेगा और कंपनियाँ चीन से अपनी फैक्टरियाँ हटा कर अन्य देशों में ले जाएँगी, भारत को विकल्प बनने का अवसर मिलेगा। ऐसा तभी होगा जब भारत अन्य क्षेत्रीय सहयोग संधियों में शामिल रहे। आरसीईपी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ ऐसे अवसर मुहैया कराती है। सरकार को आरसीईपी को लेकर अधिक समझदारी भरा रुख अपनाना चाहिए। वस्तु व्यापार को उदार बनाने की प्रक्रिया में क्षेत्रवार सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए ताकि घरेलू उत्पादकों के हितों का बचाव किया जा सके। जहाँ तक सेवा क्षेत्र के उदारीकरण की बात है तो मौजूदा सीईसीए समीक्षा प्रक्रिया आदि की मदद से जरूरी मुद्दों पर बात हो सकती है।

हो जाएँगे। जैसे अमेरिका में सेब के उत्पादन में यदि श्रमिक की दिहाड़ी 6,000 रुपये है और भारत के कुल्लू में श्रमिक की दिहाड़ी 400 रुपये है तो भारत का सेब अमेरिका के मुकाबले सस्ता पड़ेगा और अमेरिका का सेब भारत में नहीं बिक पाएगा।

खुले विश्व व्यापार का तार्किक परिणाम यह होगा कि संपूर्ण विश्व में वेतन भी बराबर होंगे। यदि ऐसा होता है तो विकसित देशों के वर्तमान में ऊँचे वेतन नीचे आएंगे जो अमेरिका को स्वीकार नहीं हैं। इसलिए अमेरिका चाहता है कि अब यह विश्व व्यापार से पीछे हट जाए जिससे भारत का सस्ता सेब और सस्ती चीनी, अमेरिका में प्रवेश न करे और अमेरिका के सेब उत्पादक अपने श्रमिकों को पहले की ही तरह ऊँचा वेतन देते रहें। इसी सोच के तहत अमेरिका ने बीते दिनों भारत और चीन से आयात होने वाले इस्पात पर भारी आयात कर लगाया।

भारत में इस्पात का उत्पादन सस्ता पड़ता है, क्योंकि यहाँ श्रमिकों के वेतन कम हैं। ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले इस्पात पर आयात कर इसलिए बढ़ाए ताकि अमेरिका के इस्पात उत्पादकों का धंधा चौपट न होने पाए। अमेरिका का मुक्त व्यापार से पीछे हटना यह बताता है कि अब वहाँ नई तकनीकों का सृजन कम हो रहा है। अमेरिका को मुक्त व्यापार में अब विश्व के तमाम देशों से टक्कर लेनी पड़ रही है जिसमें वह असफल हो रहा है। अपने मंतव्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने डब्ल्यूटीओ को ही खंडित करने की रणनीति बना ली है। डब्ल्यूटीओ के नियमों में व्यवस्था है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर कोई भी देश किसी विशेष माल पर आयात कर लगा सकता है। इस प्रावधान का उपयोग करते हुए अमेरिका ने भारत में उत्पादित इस्पात पर आयात कर बढ़ाया, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि इस्पात के उत्पादन में राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई पेंच नहीं है।

अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मनचाही मात्रा में इस्पात का उत्पादन कर सकता है। उसके लिए भारत से इस्पात के आयात का कोई संकट पैदा नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ढाल के रूप में उपयोग करते हुए भारत से आयातित इस्पात पर आयात कर बढ़ा दिया। उन्होंने एक कानून बनाने का प्रस्ताव रखा है जिसके अंतर्गत डब्ल्यूटीओ के नियमों के बावजूद अमेरिकी सरकार उत्पादों पर मनचाहे आयात कर लगा सकेगी। डब्ल्यूटीओ संधि करते समय सभी देशों ने अपने द्वारा लगाए जाने वाले अधिकतम आयात कर की सीमा निर्धारित कर दी थी।

अब ट्रंप ने नया कानून बनाकर उस संधि को पलटने की योजना बनाई है। यदि अमेरिका ने पूर्व में डब्ल्यूटीओ को आश्वासन दे रखा है कि वह किसी विशेष उत्पाद पर एक सीमा तक ही आयात कर लगाएगा तो अब वह उससे ज्यादा आयात कर लगाने के लिए डब्ल्यूटीओ की मूल भावना के विपरीत कानून बनाने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने डब्ल्यूटीओ की भावना के खिलाफ एक और कदम उठाया है। डब्ल्यूटीओ में देशों के बीच कोई विवाद उठने पर उसकी अपील डब्ल्यूटीओ की अपीलीय व्यवस्था में की जाती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपीलीय व्यवस्था में नए जजों की नियुक्ति पर सहमति नहीं दी है। वहाँ जजों की संख्या कम होती जा रही है और शीघ्र ही अपीलीय व्यवस्था में एक भी जज नहीं रह जाएगा। ऐसे में अपीलीय व्यवस्था निरस्त हो जाएगी और डब्ल्यूटीओ के दायरे में विवादों को हल करने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। तब अमेरिका समेत हर देश खुलकर डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन कर सकेगा, क्योंकि इस मामले में अपील ही नहीं हो पाएगी।

वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने सही कदम उठाते हुए तमाम देशों को आमंत्रित किया था कि डब्ल्यूटीओ पर नई पहल की जाए, लेकिन भारत अथवा किसी दूसरे विकासशील देश द्वारा की गई इस पहल का सफल होना लगभग असंभव है। इसका कारण यह है कि विश्व व्यापार मूलत: विकसित देशों के लिए अब उतना लाभदायक नहीं रह गया है। विश्व अर्थव्यवस्था संपूर्ण विश्व में श्रम के एक ही वेतन की ओर बढ़ रही है जो कि विकसित देशों को स्वीकार नहीं है। इसलिए विश्व अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार के अंत की आशंका ही अधिक दिखती है।

Committed To Excellence

सारांश

- भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग संधि (सीईसीए) में आ रहा धीमापन देश की मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) नीति में आ रही कमजोरी का एक और संकेत है। एफटीए वार्ता में यह धीमापन आंशिक रूप से इसलिए आ रहा है क्योंकि भारत को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समूह आसियान से दबाव का सामना करना पड़ रहा है। यह दबाव क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) को निपटाने से संबंधित है। आरसीईपी के देश पिछले छह साल से इस वार्ता में उलझे हुए हैं।
- अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध के माहौल को देखते हुए आसियान के सदस्य आरईसीपी की बातचीत को समाप्त करने के अपने तय लक्ष्य के प्रति गंभीर हैं। वे नवंबर 2018 की आसियान शिखर बैठक में इस पर हस्ताक्षर चाहते हैं। काफी संभावना है कि अगर भारत पहले जैसे हालात बरकरार रखता है तो अन्य सदस्य देश बिना भारत के समझौते पर आगे बढ़ जाएँगे।
- एफटीए एकदम वैध व्यापारिक तरीका है। इसे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स ऐंड ट्रेड (गैट) के अनुच्छेद-24 के तहत मंजूरी प्राप्त है। इनकी प्रकृति प्राथमिकता वाली होती है और ये अधिकाधिक देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने का काम करते हैं।
- ये डब्ल्यूटीओ के मुक्त और निष्पक्ष व्यापार के लक्ष्य के अनुरूप ही है। कई विकसित और विकासशील देशों ने बहुपक्षीय व्यापार उदारीकरण के साथ एफटीए को अपना कर लाभ कमाया। सन 2000 के दशक में एफटीए की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। दोहा विकास एजेंडे के तहत डब्ल्यूटीओ की प्रक्रिया धीमी पड़ने के बाद इसमें और प्रगति हुई।
- कई देशों को यह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार का आसान जरिया लगा। सन 2000 से 2017 के बीच क्षेत्रीय व्यापार संधियों की संख्या 79 से बढ़कर 287 हो गई। इतना ही नहीं हर वर्ष वस्तुओं ने सेवा क्षेत्र को पीछे छोड़ा। पूर्वी एशिया जो विश्व व्यापार के तीन ध्रुवों में से एक है (दो अन्य हैं यूरोप और उत्तरी अमेरिका), वहाँ 83 क्षेत्रीय समझौते प्रवर्तन में हैं। यूरोप 97 समझौतों के साथ शीर्ष पर है।
- मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य में अमेरिका और चीन की कारोबारी जंग छिड़ी हुई है। इस दौरान डब्ल्यूटीओ के तरजीही मुल्क के सिद्धांत की अनदेखी हुई है और इस बात ने बहुपक्षीय व्यवस्था को कमजोर किया है। अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ की विवाद निस्तारण अपीलीय संस्था को अवरुद्ध किया है।
- प्रासंगिकता बनाए रखने के क्रम में डब्ल्यूटीओ, अमेरिका और जापान जैसे विकसित देशों के दबाव में ई-कॉमर्स आदि को लेकर नए नियम बना सकता है। वह राज्य आपूर्ति या सब्सिडी कार्यक्रम में पारदर्शिता और सीमा को लेकर नियम प्रस्तुत कर सकता है।
- आरसीईपी को एक व्यापक समझौते के रूप में तैयार करने का विचार था जहाँ वस्तुओं और सेवाओं को लेकर एक साथ बातचीत हो सके। परंतु फिलहाल भारत आसियान के साथ एफटीए के कारण अनावश्यक प्रभाव में आ रहा है। भारत-आसियान सेवा एफटीए पर वस्तु एफटीए के चार साल बाद हस्ताक्षर किए गए। अभी भी इसे सभी सदस्य देशों की मंजूरी का इंतजार है।
- 2011 में सीईपीए पर हस्ताक्षर के बाद से ही भारत-जापान द्विपक्षीय व्यापार में ठहराव रहा या गिरावट आई। मलेशिया के साथ व्यापार भी यही कहानी कहता है। जापान भारत में सबसे बड़ा निवेशकों में से एक है लेकिन आवक का आकार छोटा है और सीईपीए के बाद भी निवेश में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है।
- जैसे-जैसे अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध बढ़ेगा और कंपनियाँ चीन से अपनी फैक्टरियां हटा कर अन्य देशों में ले जाएँगी, भारत को विकल्प बनने का अवसर मिलेगा। ऐसा तभी होगा जबकि भारत अन्य क्षेत्रीय सहयोग संधियों में शामिल रहे। आरसीईपी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ ऐसे अवसर मुहैया कराती है।
- मुक्त व्यापार के सिद्धांत यही है कि हर एक क्षेत्र किसी खास वस्तु के उत्पादन में महारत रखता है। जैसे भुसावल में केले का उत्पादन सस्ता पड़ता है और मेरठ में चीनी का। दोनों के लिए लाभप्रद है कि भुसावल केले का उत्पादन करके मेरठ को भेजे और मेरठ चीनी का उत्पादन कर उसे भुसावल भेजे।
- मुक्त व्यापार के सिद्धांत के अनुसार अमेरिका को लड़ाकू विमानों का निर्यात करना चाहिए और भारत को दूध का। अब मान लीजिए कि अमेरिका लड़ाकू विमानों का दुनिया में इकलौता उत्पादक है और उसके एवज में वह मनचाहा दाम चाहता है। ऐसे में भारत के हित में यही होगा कि वह अपने देश में ही लड़ाकू विमान बनाए।
- मुक्त व्यापार का सिद्धांत तब नाकाम हो जाता है जब किसी विशेष देश का किसी माल पर एकाधिकार होता है जैसे लड़ाकू विमान के मामले में अमेरिका का है। 1990 के दशक में अमेरिका में नए तकनीकी आविष्कार हो रहे थे जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज सॉफ्टवेयर बनाया, सिस्को ने राउटर सिस्टम बनाए, एचपी ने प्रिंटर इत्यादि बनाए। अमेरिका इन एकाधिकार वाली वस्तुओं को दुनियाभर में बेचना चाहता था। तब उसके लिए मुक्त विश्व व्यापार दोहरे लाभ का सौदा था।
- एक तरफ विंडोज सॉफ्टवेयर जैसे एकाधिकार वाले माल को अमेरिका मुँहमांगे दाम पर बेचकर दुनिया भर से लाभ कमाता था। दूसरी ओर भारत से सस्ती चीनी का आयात करके लाभ उठाता था। इसीलिए अमेरिका ने उस समय मुक्त व्यापार की जोरशोर से पैरवी की और डब्ल्यूटीओ को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। पिछले कुछ समय में हालात बदल गए हैं। अब विंडोज जैसे सॉफ्टवेयर, सिस्को के राउटर या प्रिंटर जैसे माल तमाम देश बनाने लगे हैं। अमेरिका के पास एकाधिकार वाले उत्पाद कम रह गए हैं। ऐसे में अमेरिका के लिए विश्व व्यापार घाटे का सौदा हो गया है।
- खुले विश्व व्यापार का तार्किक परिणाम यह होगा कि संपूर्ण विश्व में वेतन भी बराबर होंगे। यदि ऐसा होता है तो विकसित देशों के वर्तमान में ऊँचे वेतन नीचे आएंगे जो अमेरिका को स्वीकार नहीं हैं।
- भारत में इस्पात का उत्पादन सस्ता पड़ता है, क्योंकि यहाँ श्रमिकों के वेतन कम हैं। ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले इस्पात पर आयात कर इसलिए बढ़ाए ताकि अमेरिका के इस्पात उत्पादकों का धंधा चौपट न होने पाए। अमेरिका का मुक्त व्यापार से पीछे हटना यह बताता है कि अब वहाँ नई तकनीकों का सृजन कम हो रहा है।
- डब्ल्यूटीओ के नियमों में व्यवस्था है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर कोई भी देश किसी विशेष माल पर आयात कर लगा सकता है।

इस प्रावधान का उपयोग करते हुए अमेरिका ने भारत में उत्पादित इस्पात पर आयात कर बढ़ाया, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि इस्पात के उत्पादन में राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई पेंच नहीं है।

- अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मनचाही मात्रा में इस्पात का उत्पादन कर सकता है। उसके लिए भारत से इस्पात के आयात का कोई संकट पैदा नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ढाल के रूप में उपयोग करते हुए भारत से आयातित इस्पात पर आयात कर बढ़ा दिया। उन्होंने एक कानून बनाने का प्रस्ताव रखा है जिसके अंतर्गत डब्ल्यूटीओ के नियमों के बावजूद अमेरिकी सरकार उत्पादों पर मनचाहे आयात कर लगा सकेगी। डब्ल्यूटीओ संधि करते समय सभी देशों ने अपने द्वारा लगाए जाने वाले अधिकतम आयात कर की सीमा निर्धारित कर दी थी।
- अब ट्रंप ने नया कानून बनाकर उस संधि को पलटने की योजना बनाई है। यद्यपि अमेरिका ने पूर्व में डब्ल्यूटीओ को आश्वासन दे रखा है कि वह किसी विशेष उत्पाद पर एक सीमा तक ही आयात कर लगाएगा तो अब वह उससे ज्यादा आयात कर लगाने के लिए डब्ल्यूटीओ की मूल भावना के विपरीत कानून बनाने की तैयारी कर रहा है।
- डब्ल्यूटीओ में देशों के बीच कोई विवाद उठने पर उसकी अपील डब्ल्यूटीओ की अपीलीय व्यवस्था में की जाती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपीलीय व्यवस्था में नए जजों की नियुक्ति पर सहमति नहीं दी है। वहाँ जजों की संख्या कम होती जा रही है और शीघ्र ही अपीलीय व्यवस्था में एक भी जज नहीं रह जाएगा। ऐसे में अपीलीय व्यवस्था निरस्त हो जाएगी और डब्ल्यूटीओ के दायरे में विवादों को हल करने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। तब अमेरिका समेत हर देश खुलकर डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन कर सकेगा, क्योंकि इस मामले में अपील ही नहीं हो पाएगी।
- वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने सही कदम उठाते हुए तमाम देशों को आमंत्रित किया था कि डब्ल्यूटीओ पर नई पहल की जाए, लेकिन भारत अथवा किसी दूसरे विकासशील देश द्वारा की गई इस पहल का सफल होना लगभग असंभव है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO)

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) अनेक देशों के बीच व्यापार के नियमों के संदर्भ में एक संगठन है जो कि उनके मध्य के अनेक व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देने में न केवल मदद करता है बल्कि व्यापारिक कार्यक्रमों के संदर्भ में अनेक गतिविधीयों को अंजाम देता है।
- यह विश्व के देशों के बीच एक व्यापार के सन्दर्भ में वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह समझौतों के माध्यम से अपनी व्यापारिक गतिविधियों को सम्पादित करता है जो कि इन्हीं देशों के सामूहिक हस्ताक्षर के द्वारा प्रकाश में आये हुए रहते हैं। इस संस्था में लागू किये जाने वाले कानून उन देशों के सांसदों द्वारा पारित किये हुए रहते हैं।
- विश्व व्यापार संगठन वैश्विक व्यापार और वैश्वीकरण की शुरुआत करने वाले संगठन का नाम है। यह संगठन विश्व व्यापार के लिए दिशानिर्देशों को जारी करता है। यह विश्व का सबसे प्रमुख मौद्रिक संगठन है। संगठन अपने सदस्य देशों को जरुरत के अनुसार ऋण उपलब्ध कराता है। डब्लयूटीओ का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
- विश्व व्यापार संगठनश की स्थापना 1 जनवरी, 1995 को की गई थी। यह संगठन नए व्यापार समझौतों में बदलाव और उन्हें लागू कराने के लिए उत्तरदायी है। भारत भी इसका एक सदस्य देश है। 'विश्व व्यापार संगठन' को 'जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड' (गैट) के स्थान पर बनाया गया था।
- ग्गैटश की स्थापना 1948 में तब हुई थी, जब 23 देशों ने कस्टम टेरिफ कम करने के लिए हस्ताक्षर किए थे। डब्ल्यूटीओ गैट का वृहद स्वरूप है। जहाँ गैट मात्र मर्केडाइज सामानों को नियंत्रित करता था, वहीं डब्ल्यूटीओ के कार्य-क्षेत्र में सेवा व्यापार, जैसे- दूरसंचार और बैंकिंग तथा दूसरे मुद्दे, जैसे- इंटेलेक्चुअल संपत्ति अधिकार भी हैं।
- यह विश्व व्यापार समझौता एवं बहुपक्षीय तथा बहुवचनीय समझौतों के कार्यन्वयन,प्रशासन एवं परिचाल हेतु सुविधाएँ प्रदान करता है, व्यापार और प्रशुल्क से संबंधित किसी भी भावी मसाले पर सदस्यों के बीच विचार-विमर्श हेतु एक मंच के रूप में कार्य करता हैं। विवादों के निपटारे से संबंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं को प्रशासित करता है। वैश्विक आर्थिक निति निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव लाने के ले लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व वैंक से सहयोग करता है।
- यह एक ऐसा विश्व-स्तरीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिये दिशानिर्देशों को जारी करता है और सदस्य देशों को जरुरत के मुताबिक ऋण उपलब्ध कराता है। यह नए व्यापार समझौतों में बदलाव और उन्हें लागू कराने के लिए उत्तरदायी है। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य देश है। वर्तमान में इसके 164 सदस्य हैं। चीन इसमें 2001 में शामिल हुआ था।
- डब्ल्यूटीओ की सबसे बड़ी संस्था मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (मिनिस्ट्रयल कॉन्फ्रेंस) है, यह प्रत्येक दो वर्ष में अन्य कार्यों के साथ संस्था के महासचिव और मुख्य प्रबंधकर्त्ता का चुनाव करती है। साथ ही वह सामान्य परिषद (जनरल काउंसिल) का काम भी देखती है। सामान्य परिषद विभिन्न देशों के राजनयिकों से मिल कर बनती है जो प्रतिदिन के कामों को देखती है। डब्लयूटीओ का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
- डब्ल्यूटीओ समझौते के तहत सरकारों को लागू कानूनों एवं अपनाए गए उपायों के बारे में डब्ल्यूटीओ को सूचित कर अपनी व्यापार नीतियों को पारदर्शी बनाने की आवश्यकता होती है। डब्ल्यूटीओ के कई परिषद और समितियाँ इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं और डब्ल्यूटीओ के समझौतों का कार्यान्वयन उचित तरीके से हो रहा है या नहीं। समय-समय पर डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्यों की व्यापार नीतियों और प्रथाओं की समीक्षा की जाती है। प्रत्येक समीक्षा में संबंधित देश और डब्ल्यूटीओ सचिवालय द्वारा दी गई रिपोर्ट होती है।
- डब्ल्यूटीओ समझौते वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा को कवर करते हैं। यह उदारीकरण के सिद्धान्तों और अनुमित अपवादों की व्याख्या करते हैं। इसमें व्यक्तिगत देशों की कम सीमा शुल्क टैरिफ और अन्य व्यापार बाधाओं के प्रति प्रतिबद्धता एवं सेवा बाजार को खोलने एवं उसे खुला रखना शामिल है।
- विवादों के निपटान के लिए ये प्रक्रियाओं का निर्धारण करते हैं। ये समझौते स्थायी नहीं होते, समय-समय पर इन पर फिर से बातचीत की जाती है और पैकेज में नए समझौते जोड़े जा सकते हैं। नवंबर 2001 में दोहा (कतर) में डब्ल्यूटीओ के व्यापार मंत्रियों द्वारा शुरु किए गए दोहा विकास एजेंडा, के तहत अब कई समझौते किए जा चुके हैं।

PT / Mains - प्रश्न

संभावित प्रश्न

1. भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग संधि सीईसीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
   1. 'सीईसीए' में आ रहा धीमापन देश की मुक्त व्यापार समझौता नीति में आ रही कमजोरी का एक संकेत है।
   2. 'एफटीए' वार्ता में यह धीमापन आंशिक रूप से इसलिए आ रहा है क्योंकि भारत को दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के समूह आसियान से दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

   (उत्तर-A)

2. 'डब्ल्यूटीओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें-
   1. 'डब्ल्यूटीओ' के नियमों के अनुसार कोई भी देश किसी विशेष माल पर आयात कर लगा सकता है।
   2. डब्ल्यूटीओ में देशों के बीच कोई विवाद उठने पर उसकी अपील डब्ल्यूटीओ की अपीलीय व्यवस्था में की जाती है।
   3. 'डब्ल्यूटीओ' व्यापार और विश्व शांति की शुरुआत करने वाले संगठन का नाम है।

   उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
   (a) 1, 2 और 3 (b) 1 और 2
   (c) 1 और 3 (d) 2 और 3

   (उत्तर-B)

3. 'डब्ल्यूटीओ' की स्थापना कब हुई?
   (a) 1 जनवरी, 1994 (b) 2 जनवरी, 1995
   (c) 1 जनवरी, 1995 (d) 1 जनवरी, 1993

   (उत्तर-C)

4. 'डब्ल्यूटीओ' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें
   1. डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय 'न्यूयॉर्क' में है।
   2. डब्ल्यूटीओ समझौते केवल वस्तुओं और सेवाओं को कवर करते हैं।
   3. डब्ल्यूटीओ की सबसे बड़ी संस्था मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) 1 और 2 (b) केवल 3
   (c) 1 और 3 (d) केवल 1

   (उत्तर-B)

5. विश्व व्यापार संगठन के अस्तित्व पर मौजूदा समय में संकट छाया हुआ है। इसमें अमेरिका की भूमिका अग्रणी है। चर्चा करें।

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. भारत में डब्ल्यू.टी.ओ. के व्यापार सरलीकरण समझौते (टी.एफ.ए.) की पुष्टि की है।
   2. टी.एफ.ए., डब्ल्यू.टी.ओ के 2013 के मिनिस्टीरियल पैकेज का एक हिस्सा है।
   3. टी.एफ.ए. जनवरी, 2016 में अस्तित्व में आया।

   उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
   (a) 1 और 2 (b) 1 और 3
   (c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2017, उत्तर-A)

2. निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आप कभी-कभी 'एम्बर बॉक्स', 'ब्लू बॉक्स' एवं 'ग्रीन बॉक्स' को समाचारों में पाते हैं?
   (a) डब्ल्यू.टी.ओ. मामले
   (b) सार्क मामले
   (c) यू.एन.एफ.सी.सी.सी. मामले
   (d) भारत-ई.यू.के एफ.टी.ए. पर समझौते

   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2016, उत्तर-A)

3. निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में यह वाक्यांश 'स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म्स' समाचारों में प्रायः रहता है?
   (a) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम
   (b) विश्व व्यापार संस्था
   (c) आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौता
   (d) जी-20 सम्मेलन

   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2010, उत्तर-B)

4. विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) एक महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जहाँ लिए गए निर्णय देशों को गहराई से प्रभावित करते हैं। डब्ल्यू.टी.ओ. का क्या अधिदेश मैंडेट है और उसके निर्णय किस प्रकार बंधनकारी है? खाद्य सुरक्षा पर विचार-विमर्श के पिछले चक्र पर भारत के दृढ़ मत का समालोचनापूर्वक विश्लेषण कीजिए।

   (IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-2, वर्ष-2014)

5. "विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ) के अधिक व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन और प्रोन्नति करना है। परन्तु संधि वार्ताओं की दोहा परिधि मृतोन्मुखी प्रतीत होती है, जिसका कारण विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद है।" भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस पर चर्चा कीजिए।

   (IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-2, वर्ष-2016)

GS World
Committed To Excellence

गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या का समाधान

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-3 (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए यानी गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के बारे में यह कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इस मसले का समाधान कर लेना चाहिए। एनपीए ऐसा कर्ज है, जिसे नब्बे दिन या उससे अधिक की अवधि में चुकाया न गया हो। जान-बूझकर दिवालिया होने और बैंक से धोखाधड़ी करने को भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में बैड लोन बढ़ने के प्राथमिक कारण के रूप में देखा जाता है। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार-पत्रों 'नवभारत टाइम्स', 'अमर उजाला', 'बिजनेस स्टैंडर्ड' तथा 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

दिवालिया होतीं कंपनियाँ (नवभारत टाइम्स)

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था एक बड़ी परीक्षा के दौर से गुजर रही है। रिजर्व बैंक के नए निर्देशों के मुताबिक करीब 70 कंपनियों को अपना कर्जा चुकाने की व्यवस्था करने के लिए 180 दिनों की जो मोहलत दी गई थी, वह आज यानी 27 अगस्त दिन सोमवार को खत्म हो रही है। कुछ कंपनियों ने इस दौरान अपने लिए खरीदार भी खोजे, लेकिन जिन कंपनियों की यहाँ बात चल रही है, वे इस अवधि में ऐसा कुछ नहीं कर सकीं, जिससे लगे कि वे कर्ज चुकाने की स्थिति में आ गई हैं। आखिरी उपाय के तौर पर कर्जदाता बैंकों ने और इंडस्ट्री ने भी रिजर्व बैंक से मोहलत बढ़ाने की गुजारिश की, लेकिन उसने मना कर दिया।

अब आलम यह है कि 2000 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा का कर्ज लिए बैठी इन कंपनियों की सूची नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) के पास भेजी जाएगी, जहाँ इनके खिलाफ दिवालियेपन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इन कंपनियों पर कुल 3 लाख 80 हजार करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है। समझा जा सकता है कि हमारी बैंकिंग व्यवस्था के लिए यह कितना बड़ा संकट है। ये सभी देश की बड़ी कंपनियाँ हैं। इनमें कितने लोग काम करते हैं और एक बार दिवालियेपन की प्रक्रिया में जाने के बाद इनका नियमित संचालन किस तरह प्रभावित होगा, इन कर्मचारियों की रोजी-रोटी का क्या होगा, इनसे जुड़े परिवारों का भविष्य क्या होगा, ऐसे तमाम जरूरी सवालों का जवाब देने की स्थिति में फिलहाल कोई नहीं है। यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि ये कंपनियाँ 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा कर्ज वाली हैं। 1000 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा कर्ज वाली कंपनियों की बारी इसके बाद आनी है।

इन कंपनियों में उत्पादन बाधित होने से बाजार पर और इनकी सहायक कंपनियों पर पड़ने वाले प्रभावों और इससे पूरी अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसानों को फिलहाल छोड़ दें तो भी यह सवाल मुँहबाए खड़ा है कि क्या यह प्रक्रिया बैंकों को उनका पैसा वापस लौटाने की गारंटी दे पाएगी। अगर 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा कर्ज वाली 12 कंपनियों के साथ जुड़े अनुभव पर गौर करें तो जवाब ना में ही मिलता है। इनमें से 11 कंपनियाँ एनसीएलटी की अलग-अलग बेंचों के जरिये समाधान की अलग-अलग अवस्थाओं में हैं और बैंकों को उनसे अपने पूरे कर्ज की आधी से कुछ ज्यादा रकम ही वापस मिलने की उम्मीद है। जून के अंत तक इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आईबीसी) के तहत जो 32 मामले सुलझाए जा सके थे, उनमें भी रिकवरी कुल दावे की करीब 55 फीसदी ही रही। ऐसे में सवाल यह बनता है कि आईबीसी की यह प्रक्रिया क्या सचमुच हमारी बैंकिंग व्यवस्था की बीमारी दूर कर सकती है? अगर नहीं, तो क्या यह

हारे घोड़ों पर दाँव लगाने की भूल (अमर उजाला)

पिछले कुछ वर्षों से बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए यानी गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के बारे में न केवल काफी चर्चा हो रही है, बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इस मसले का समाधान कर लेना चाहिए। एनपीए या बैड लोन दरअसल ऐसा कर्ज है, जिसे नब्बे दिन या उससे अधिक की अवधि में चुकाया न गया हो। 31 मार्च, 2018 तक सार्वजनिक बैंकों का बैड लोन 8,95,601 करोड़ था, जो बैंकों के कुल बैड लोन का 86.5 प्रतिशत था। इस संदर्भ में सरकार यानी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने लगातार यह कहा है कि पुनर्पूंजीकरण के जरिये बैंकों को चलाया जाएगा।

संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार ने यह कहा कि 2017-18 में उसने राष्ट्रीयकृत बैंकों में 68,729 करोड़ रुपये निवेश किए हैं। जो लोग नहीं जानते, उन्हें बताना जरूरी है कि सरकार के पास सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंक हैं और राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 है; भारतीय स्टेट बैंक और आईडीबीआई बैंक ऐसे दो बैंक हैं, जिनमें सरकार ने क्रमशः 8,800 करोड़ और 7,881 करोड़ रुपये निवेश किए। आज आईडीबीआई बैंक को उस एलआईसी ऑफ इंडिया (भारतीय जीवन बीमा निगम) ने खरीद लिया है, जिसका स्वामित्व भी सरकार के पास है, और उसके पास जो पैसा है, वह देश के नागरिकों का ही है।

बीमारी की जड़

जान-बूझकर दिवालिया होने और बैंक से धोखाधड़ी करने की खबरें आज बेहद बढ़ गई हैं। इसे भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में बैड लोन बढ़ने के प्राथमिक कारण के रूप में देखा जाता है। अलबत्ता बैड लोन की मुख्य वजह आर्थिक वृद्धि की अधिक उम्मीद है, जिस कारण बैंक निरंतर और उदारता से कर्ज बाँटते हैं। लेकिन जब आर्थिक वृद्धि की उम्मीद टूट जाती है और बड़ी-बड़ी विकास परियोजनाओं का काम रुक जाता है, तब कर्ज लेने वाले बैंकों को कर्ज चुका नहीं पाते।

बैंकों में एनपीए बढ़ने से कर्ज देने की व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैड लोन के तहत बड़ी मात्रा में पैसा फँस जाने के मामलों ने बैंकों को अधिक चौकस बना दिया है। नतीजतन आम तौर पर पूरी अर्थव्यवस्था और खासकर उद्योगों के लिए कर्ज हासिल करने का स्रोत सूख गया है, जिससे आर्थिक पुनरुद्धार का काम पहले से अधिक जटिल हो गया है। आज कर्ज चाहने वाले कॉर्पोरेट्स बैंकों में जाने के बजाय वैकल्पिक स्रोतों को वरीयता देते हैं। उतनी ही चिंतनीय सच्चाई यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस तरह काम करते हैं कि उनमें कर्ज देते हुए उसके खतरों या कॉर्पोरेट्स की साख का आकलन करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

बेहतर नहीं होगा कि वसूली में सख्ती के नाम पर अर्थव्यवस्था को और ज्यादा झटके देने के बजाय हम अपना ध्यान बीमारी का कोई बेहतर इलाज खोजने पर केंद्रित करें?

समस्याओं को बढ़ा देने वाला 'कोबरा इफेक्ट'

(बिजनेस स्टैंडर्ड)

हम ब्रिटिश दासता से आजादी के 72वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे मौके पर हमें समाधान के समस्या से भी बदतर हो जाने वाले 'कोबरा इफेक्ट' को ध्यान में रखना चाहिए। यह नामकरण भारत के औपनिवेशक काल की देन है, जब अंग्रेजों ने लुटियंस दिल्ली में जहरीले कोबरा साँपों की समस्या दूर करने के लिए एक नकद प्रोत्साहन योजना चलाई थी। इस योजना के तहत मृत कोबरा साँपों की कई खालें लाने के बावजूद उनका प्रकोप कम नहीं हो रहा था। दरअसल हुआ यह था कि नकद प्रोत्साहन के लालच में दिल्ली के आसपास कई लोग कोबरा पालने लगे थे। लोग वहीं से मरे हुए साँपों की खाल लाकर दिखा देते थे। जब अंग्रेज हुक्मरानों को असलियत पता चली तो फौरन वह प्रोत्साहन योजना रोक दी गई। लेकिन इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि पैसे मिलने का लालच नहीं रहने पर कोबरा पालने वाले तमाम लोगों ने उन्हें खुला छोड़ दिया जिससे दिल्ली में कोबरा साँपों की संख्या और बढ़ गई। इस तरह कोबरा से निजात दिलाने के लिए शुरू की गई योजना के ही चलते समस्या बिगड़ गई।

ऐसा अहसास बाद में भी होता रहा है। बेहद खराब प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक बैंक आईडीबीआई को उबारने के लिए बीमा उपक्रम एलआईसी का इस्तेमाल करने का फैसला करोड़ों पॉलिसी धारकों के जीवन बीमा को ही खतरे में डालने वाला है। इस फैसले में भी कोबरा इफेक्ट को महसूस किया जा सकता है। आखिर हम बैंकिंग अनुभव नहीं रखने वाली एक जीवन बीमा कंपनी से उस बैंक के संचालन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जो अपनी अक्षमता के लिए चर्चित है और उसका एक-तिहाई कर्ज एनपीए हो चुका है?

एक निजी कंपनी आईएल ऐंड एफएस को संकट से निकालने के लिए इस बीमा कंपनी का उपयोग करना इससे भी खराब कोबरा इफेक्ट है। इस निजी कंपनी में जापानी कंपनी ओरिक्स कॉर्पोरेशन (23.5 फीसदी) और अबुधाबी इन्वेस्टमेंट फंड (12.6 फीसदी) के अलावा एचडीएफसी, एसबीआई और सेंट्रल बैंक की भी हिस्सेदारियाँ हैं। इससे पहले शायद ही कभी सुना गया हो कि एक निजी कंपनी को उबारने के लिए एक सार्वजनिक कंपनी ने 650 अरब रुपये के कर्ज की देनदारी का भी बोझ उठाया हो। विदेशी निवेशकों के निकलने के बाद एलआईसी के पास बहुलांश शेयर हो गए। यह स्पष्ट नहीं है कि नुकसान स्वीकार करने के बजाय सार्वजनिक कंपनी के अच्छे धन को भी फंसे कर्ज की वापसी के लिए लगा देना किसके हित में है? यह एलआईसी के अभागे पॉलिसीधारकों के हित में तो कतई नहीं है।

कोबरा इफेक्ट को हमारी व्यापार नीति में भी देखा जा सकता है। आयात में बढ़ोतरी और निर्यात में आई सुस्ती ने व्यापार घाटे की खाई को चौड़ा करने का काम किया है। अंतर्निहित कारणों पर ध्यान देने और निर्यात प्रोत्साहन के तरीके निकालने के बजाय भारत पुराने खराब निरंकुश दौर की ही तरफ लौटता नजर आ रहा है। भारत को इन निरंकुश नीतियों की भारी कीमत चुकानी पड़ी है और करीब चार दशकों तक भारत की आर्थिक प्रगति के 3-4 फीसदी के 'हिंदू वृद्धि दर' तक ही सीमित रहने में इसकी प्रमुख भूमिका रही है। विदेशी मुद्रा विनिमय को लेकर बड़ा

इसे समझने के लिए ढाँचागत क्षेत्र, इस्पात, दूरसंचार और उड्डयन क्षेत्र की ओर नजर दौड़ाना काफी होगा। आर्थिक बेहतरी के दौर में ये सभी क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहे थे, और अपने विस्तार कार्यक्रमों के लिए इन्होंने भारी मात्रा में कर्ज लिया। लेकिन मंदी ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हालाँकि इन कर्जों के एनपीए बन जाने की और भी वजहें थीं। मसलन, पूंजी पर्याप्तता, बैंक का आकार, एनपीए का इतिहास और वित्तीय संपत्तियों पर रिटर्न की संभावना जैसे सूक्ष्म संकेतकों पर गौर न करना भी बैड लोन के बढ़ते चले जाने का कारण है।

यूको बैंक का ही उदाहरण लीजिए। इसका कुल बैड लोन 30,550 करोड़ रुपये है। 2017-18 में सरकार ने इस बैंक में 6,507 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया। यूको बैंक का कर्ज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुल कर्ज के दो फीसदी से भी कम था। लेकिन पुनर्पूंजीकरण के बाद यूको बैंक का कर्ज बढ़कर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुल कर्ज का 7.6 प्रतिशत हो गया। साफ है कि बैंकों के पुनर्पूंजीकरण का यह तरीका वैज्ञानिक तरीका नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ी खामी यह है कि एनपीए से ग्रस्त सभी 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों के समाधान का अलग-अलग तरीका निकाला जाता है।

कदम उठाने का समय

सरकार के लिए यह स्वर्णिम अवसर है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपना स्वामित्व मजबूत करे। इसका तरीका वही है, जैसा उसने 2015 में भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए किया था। कुछ छोटे बैंकों में पुनर्पूंजीकरण जैसे उपाय के बजाय यह तरीका ज्यादा कारगर होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक एक ही काम में हैं, हां, उनकी भौगोलिक अवस्थिति और उनके कारोबार में फर्क है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों का एक में विलय कर देने से न केवल उनकी अनेक शाखाओं और ऑपरेशन में कमी आएगी, बल्कि इससे कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।

यह सोचना बेकार है कि विलय से नौकरियों में कमी आएगी। इसके बजाय इसके सकारात्मक प्रभावों को देखना चाहिए-पारदर्शिता और नवाचार की संस्कृति वाला एक विशाल सरकारी बैंक भविष्य में बैंकिंग के क्षेत्र में कुशल प्रबंधन की गारंटी होगा। इस तरह का फैसला लेने पर पुनर्पूंजीकरण जैसा कदम भी काफी ठोक-बजाकर उठाया जाएगा। इससे एक सामान्य कर्ज नीति भी लागू होगी, जिसका सभी बैंक पालन करेंगे और जिसके तहत कर्ज देते हुए जोखिमों का भी आकलन किया जाएगा।

जब तक सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों का एक बैंक में विलय नहीं करती, जिसमें उसका मालिकाना हिस्सा कम हो, तब तक एनपीए के बोझ से दबे इन बैंकों का आकर्षण कम ही रहेगा। सामान्य ज्ञान यही कहता है कि हारे हुए घोड़े पर दाँव लगाने के बजाय अपना घाटा कम करना बेहतर है। यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है कि सामाजिक क्षेत्र के कर्ज और कॉर्पोरेट कर्ज को अलग-अलग करते हुए गैर वित्तीय संस्थानों के जरिये कर्ज देने की व्यवस्था हो, बजाय इसके कि सरकार सभी क्षेत्रों में हाथ लगाए और स्थिति ऐसी बन जाए कि उसे नियंत्रित करना कठिन हो।

एक दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 21 बैंकों को एक तरीके से चलाने के बजाय उन्हें अलग-अलग तरीके से संचालित करे।

संकट पैदा होने के बाद भारत अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए मजबूर हुआ था, जिसके बाद निजी कंपनियों को भी रफ्तार मिली और देश 7-8 फीसदी की वृद्धि दर हासिल करने में सफल रहा। लेकिन 'मेक इन इंडिया' अब 'मेक इन इंडिया फॉर इंडिया' के रूप में तब्दील हो चुका है। जिस अर्थव्यवस्था को अधिक खुलापन और वैश्विक बाजारों में बड़ी हिस्सेदारी के लिए प्रयास करने चाहिए, वह खुद के भीतर ही सिमटने लगी है। यह रास्ता तो निश्चित रूप से हिंदू विकास दर की तरफ ही जाता है।

हमारी कृषि नीति भी ऐसे ही कोबरा इफेक्ट की शिकार है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लागत से 50 फीसदी अधिक कर हम किसानों को अधिक लुभावनी फसलें उगाने के लिए आजाद नहीं कर रहे हैं। असल में, हम उन्हें अधिक लागत वाली समाजवादी मूल्य-निर्धारण योजना में कैद कर रहे हैं। इसके अलावा किसान ऐसी फसलें उगाने के लिए भी प्रेरित होंगे जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है। उन उपजों को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में ऊँची लागत पर रखा जाएगा। इस समस्या का सटीक समाधान शांता कुमार समिति ने सुझाया था लेकिन उसे लगातार नजरअंदाज किया गया। इसमें एफसीआई की भूमिका कम करने, कृषि मंडियों को अधिक आजादी देने और छोटे किसानों को प्रत्यक्ष लाभ समर्थन देने जैसे उपाय शामिल हैं। लेकिन इन उपायों के बजाय हमने वह उपाय लागू किया है जो किसानों को बाजार में मांग नहीं रहने वाली फसलों के लिए महँगे मूल्य समर्थन पर अधिक आश्रित बना देगा।

मुद्रास्फीति-नियंत्रण ढाँचे में भी कोबरा इफेक्ट को महसूस किया जा सकता है। भारत की मुद्रास्फीति बड़े स्तर पर जिंसों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों और आपूर्ति कारकों से प्रभावित रहती है, जबकि मौद्रिक नीति का प्रभाव सीमित रहता है। इसके बावजूद हमने मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए एमपीसी के तौर पर व्यापक मौद्रिक ढाँचा तैयार किया है। लेकिन एमपीसी अक्सर ब्याज दरों को काफी ऊँचा रखने की गलती करती है जिससे आर्थिक वृद्धि कम होती है और रुपये का अधिमूल्यन एवं प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता कम होती है। एमपीसी को आर्थिक वृद्धि और महँगाई नियंत्रण दोनों को समान तवज्जो देनी चाहिए। कोबरा इफेक्ट का सबसे सटीक उदाहरण तो नोटबंदी के समय देखने को मिला था। काला धन खत्म करने के नाम पर नोटबंदी को बिना सही सलाह और तैयारी के ही लागू कर दिया गया लेकिन इसका काले धन पर कोई भी असर नजर नहीं आया है। इसके बदले खेती एवं असंगठित क्षेत्र अब भी नोटबंदी के गहरे प्रभावों से उबरने की कोशिश कर रहे हैं।

निस्संदेह जीएसटी और दिवालिया कानून जैसे दीर्घावधि सुधार किए गए हैं, जिनके अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (आधार के साथ या बगैर) का विस्तार सही दिशा में उठाया गया कदम है। ये सभी योजनाएँ संप्रग या राजग की पुरानी सरकारों के समय की हैं और उन्हें तमाम दलों का समर्थन हासिल था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की ही संकल्पना पर आधारित आयुष्मान भारत योजना को अगर बढ़िया से डिजाइन और क्रियान्वित किया जाए तो करोड़ों लोगों को बीमारी के चलते गरीबी के दुष्चक्र में फँसने से बचाया जा सकता है। हमें ऐसे ही कुछ और कदमों की जरूरत है, उन कदमों की नहीं जो आगे चलकर बड़ी समस्या पैदा कर देते हैं।

स्वतंत्र भारत अपनी बेशुमार समस्याओं का समाधान तलाशने में लगा हुआ है, ऐसे समय में उसे कोबरा इफेक्ट से बचना होगा। कहीं ऐसा न हो कि लुटियंस दिल्ली में जहरीले साँपों के भय से आजादी के लिए शुरू की गई योजना की ही तरह स्वतंत्र भारत की समस्याएँ कम होने के बजाय बढ़ जाएँ।

पीएम मोदी को ऐसे कदम उठाना चाहिए जिससे बैंक एनपीए के दुष्चक्र से बाहर आएँ (दैनिक जागरण)

प्रधानमंत्री ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का उद्घाटन करते हुए बैंकों के फंसे कर्जे यानी एनपीए के लिए नामदार लोगों के बहाने जिस तरह कांग्रेस को घेरा वह इसलिए उल्लेखनीय है, क्योंकि उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने छल-छद्म का सहारा लेकर उन लोगों को नए सिरे से कर्ज दिलवाया जो दीवालिया होने की कगार पर थे। अगर संप्रग शासन में सचमुच ऐसा ही हुआ तो इसे बैंकिंग व्यवस्था में सेंधमारी के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। बेहतर हो कि पिछली सरकार के नीति-नियंता प्रधानमंत्री के आरोपों का जवाब दें। सवालों के घेरे में खड़े इन लोगों की ओर से यह कहने से काम चलने वाला नहीं कि मोदी सरकार चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, क्योंकि देश को यह आभास है कि संप्रग सरकार के समय किस तरह कपट भरे पूंजीवाद को संरक्षण प्रदान किया गया।

अच्छा होगा कि मोदी सरकार करोड़ों रुपये के कर्ज डकारने वालों के साथ उन्हें भी जवाबदेह बनाए, जिनके कारण बैंक न चाहते हुए भी कर्जे देने के लिए विवश हुए। कम से कम उन नामदार लोगों का नाम तो सामने आना ही चाहिए जिन्हें प्रधानमंत्री बैंकों की बर्बादी के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं कि प्रधानमंत्री बिना नाम लिए कांग्रेसी नेताओं को आईना दिखा रहे हैं। इसके साथ ही ऐसे कदम उठाना भी आवश्यक है जिससे बैंक एनपीए के दुष्चक्र से बाहर आएँ।

यह सही है कि मोदी सरकार ने कर्ज हड़पने और कर्जे देने में आनाकानी करने वालों के खिलाफ सख्ती दिखानी शुरू की है, लेकिन अभी तक अपेक्षित नतीजे सामने नहीं आ सके हैं। इसका कारण यह है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल में पहुँचे मामलों का निस्तारण धीमी गति से हो रहा है। इसके चलते ही फँसे कर्जे वाली राशि घटने का नाम नहीं ले रही है। यह ठीक नहीं कि बीते एक साल में जिन कंपनियों के मामले राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल पहुँचे उनमें से केवल एक का निस्तारण हो पाया है। संभवत: इसी कारण कर्ज के फँसे कर्ज में तब्दील होने का सिलसिला थमता नहीं दिखाई देता।

पाँच माह पहले के एक आँकड़े के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल एनपीए 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया था। यह शुभ संकेत नहीं कि जब बैंक मुनाफे की स्थिति में आने के लिए हाथ-पाँव मार रहे हैं तब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद करीब दो दर्जन बिजली कंपनियों पर बकाया राशि के भी एनपीए में तब्दील होने का अंदेशा उभर आया है।

अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि बैंक घाटे में डूबते दिखने से बचें। इसमें दो राय नहीं कि सरकार बैंकों को घाटे से उबारने की कोशिश कर रही है, लेकिन बात तो तब बनेगी जब यह कोशिश कामयाब होती दिखेगी। फिलहाल यह स्थिति निर्मित होती नहीं दिख रही है। बैंकों को घाटे से उबारने के ठोस उपायों के साथ यह भी समय की मांग है कि उनके विलय की प्रक्रिया आगे बढ़े। इसमें संदेह है कि विलय का फैसला बैंकों पर ही छोड़ने से अभीष्ट की पूर्ति हो सकेगी।

Committed To Excellence

सारांश

- भारतीय बैंकिंग व्यवस्था एक बड़ी परीक्षा के दौर से गुजर रही है। रिजर्व बैंक के नए निर्देशों के मुताबिक करीब 70 कंपनियों को अपना कर्जा चुकाने की व्यवस्था करने के लिए 180 दिनों की जो मोहलत दी गई थी, वह आज यानी 27 अगस्त दिन सोमवार को खत्म हो रही है।
- अब आलम यह है कि 2000 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा का कर्ज लिए बैठी इन कंपनियों की सूची नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) के पास भेजी जाएगी, जहाँ इनके खिलाफ दिवालियेपन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इन कंपनियों पर कुल 3 लाख 80 हजार करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है।
- ये सभी देश की बड़ी कंपनियाँ हैं। इनमें कितने लोग काम करते हैं और एक बार दिवालियेपन की प्रक्रिया में जाने के बाद इनका नियमित संचालन किस तरह प्रभावित होगा, इन कर्मचारियों की रोजी-रोटी का क्या होगा, इनसे जुड़े परिवारों का भविष्य क्या होगा, ऐसे तमाम जरूरी सवालों का जवाब देने की स्थिति में फिलहाल कोई नहीं है। यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि ये कंपनियाँ 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा कर्ज वाली हैं। 1000 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा कर्ज वाली कंपनियों की बारी इसके बाद आनी है।
- इन कंपनियों में उत्पादन बाधित होने से बाजार पर और इनकी सहायक कंपनियों पर पड़ने वाले प्रभावों और इससे पूरी अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसानों को फिलहाल छोड़ दें तो भी यह सवाल मुँहबाए खड़ी है कि क्या यह प्रक्रिया बैंकों को उनका पैसा वापस लौटाने की गारंटी दे पाएगी। अगर 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा कर्ज वाली 12 कंपनियों के साथ जुड़े अनुभव पर गौर करें तो जवाब ना में ही मिलता है।
- इनमें से 11 कंपनियाँ एनसीएलटी की अलग-अलग बेंचों के जरिये समाधान की अलग-अलग अवस्थाओं में हैं और बैंकों को उनसे अपने पूरे कर्ज की आधी से कुछ ज्यादा रकम ही वापस मिलने की उम्मीद है। जून के अंत तक इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आईबीसी) के तहत जो 32 मामले सुलझाए जा सके थे, उनमें भी रिकवरी कुल दावे की करीब 55 फीसदी ही रही।
- एनपीए या बैड लोन दरअसल ऐसा कर्ज है, जिसे नब्बे दिन या उससे अधिक की अवधि में चुकाया न गया हो। 31 मार्च, 2018 तक सार्वजनिक बैंकों का बैड लोन 8, 95,601 करोड़ था, जो बैंकों के कुल बैड लोन का 86.5 प्रतिशत था। इस संदर्भ में सरकार यानी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने लगातार यह कहा है कि पुनर्पूंजीकरण के जरिये बैंकों को चलाया जाएगा।
- संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार ने यह कहा कि 2017-18 में उसने राष्ट्रीयकृत बैंकों में 68,729 करोड़ रुपये निवेश किए हैं। जो लोग नहीं जानते, उन्हें बताना जरूरी है कि सरकार के पास सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंक हैं, और राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 है; भारतीय स्टेट बैंक और आईडीबीआई बैंक ऐसे दो बैंक हैं, जिनमें सरकार ने क्रमशः 8,800 करोड़ और 7,881 करोड़ रुपये निवेश किए।
- बैंकों में एनपीए बढ़ने से कर्ज देने की व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैड लोन के तहत बड़ी मात्रा में पैसा फंस जाने के मामलों ने बैंकों को अधिक चौकस बना दिया है। नतीजतन आम तौर पर पूरी अर्थव्यवस्था और खासकर उद्योगों के लिए कर्ज हासिल करने का स्रोत सूख गया है, जिससे आर्थिक पुनरुद्धार का काम पहले से जटिल हो गया है। आज कर्ज चाहने वाले कॉर्पोरेट्स बैंकों में जाने के बजाय वैकल्पिक स्रोतों को वरीयता देते हैं।
- पूंजी पर्याप्तता, बैंक का आकार, एनपीए का इतिहास और वित्तीय संपत्तियों पर रिटर्न की संभावना जैसे सूक्ष्म संकेतकों पर गौर न करना भी बैड लोन के बढ़ते चले जाने का कारण है।
- यूको बैंक का ही उदाहरण लीजिए। इसका कुल बैड लोन 30,550 करोड़ रुपये है। 2017-18 में सरकार ने इस बैंक में 6,507 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया। यूको बैंक का कर्ज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुल कर्ज के दो फीसदी से भी कम था। लेकिन पुनर्पूंजीकरण के बाद यूको बैंक का कर्ज बढ़कर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुल कर्ज का 7.6 प्रतिशत हो गया। साफ है कि बैंकों के पुनर्पूंजीकरण का यह तरीका वैज्ञानिक तरीका नहीं है।
- सरकार के लिए यह स्वर्णिम अवसर है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपना स्वामित्व मजबूत करे। इसका तरीका वही है, जैसा उसने 2015 में भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए किया था। कुछ छोटे बैंकों में पुनर्पूंजीकरण जैसे उपाय के बजाय यह तरीका ज्यादा कारगर होगा।
- सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों का एक में विलय कर देने से न केवल उनकी अनेक शाखाओं और ऑपरेशन में कमी आएगी, बल्कि इससे कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। यह सोचना बेकार है कि विलय से नौकरियों में कमी आएगी। इसके बजाय इसके सकारात्मक प्रभावों को देखना चाहिए-पारदर्शिता और नवाचार की संस्कृति वाला एक विशाल सरकारी बैंक भविष्य में बैंकिंग के क्षेत्र में कुशल प्रबंधन की गारंटी होगा।
- इससे एक सामान्य कर्ज नीति भी लागू होगी, जिसका सभी बैंक पालन करेंगे और जिसके तहत कर्ज देते हुए जोखिमों का भी आकलन किया जाएगा।
- बेहद खराब प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक बैंक आईडीबीआई को उबारने के लिए बीमा उपक्रम एलआईसी का इस्तेमाल करने का फैसला करोड़ों पॉलिसी धारकों के जीवन बीमा को ही खतरे में डालने वाला है।
- एक निजी कंपनी आईएलऐंडएफएस को संकट से निकालने के लिए इस बीमा कंपनी का उपयोग करना इससे भी खराब कोबरा इफेक्ट है। इस निजी कंपनी में जापानी कंपनी ओरिक्स कॉर्पोरेशन (23.5 फीसदी) और अबुधाबी इन्वेस्टमेंट फंड (12.6 फीसदी) के अलावा एचडीएफसी, एसबीआई और सेंट्रल बैंक की भी हिस्सेदारियां हैं। इससे पहले शायद ही कभी सुना गया हो कि एक निजी कंपनी को उबारने के लिए एक सार्वजनिक कंपनी ने 650 अरब रुपये के कर्ज की देनदारी का भी बोझ उठाया हो।

- विदेशी मुद्रा विनिमय को लेकर बड़ा संकट पैदा होने के बाद भारत अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए मजबूर हुआ था, जिसके बाद निजी कंपनियों को भी रफ्तार मिली और देश 7-8 फीसदी की वृद्धि दर हासिल करने में सफल रहा।
- फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लागत से 50 फीसदी अधिक कर हम किसानों को अधिक लुभावनी फसलें उगाने के लिए आजाद नहीं कर रहे हैं। असल में, हम उन्हें अधिक लागत वाली समाजवादी मूल्य-निर्धारण योजना में कैद कर रहे हैं। इसके अलावा किसान ऐसी फसलें उगाने के लिए भी प्रेरित होंगे जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है।
- उन उपजों को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में ऊँची लागत पर रखा जाएगा। इस समस्या का सटीक समाधान शांता कुमार समिति ने सुझाया था लेकिन उसे लगातार नजरअंदाज किया गया। इसमें एफसीआई की भूमिका कम करने, कृषि मंडियों को अधिक आजादी देने और छोटे किसानों को प्रत्यक्ष लाभ समर्थन देना जैसे उपाय शामिल हैं। लेकिन इन उपायों के बजाय हमने वह उपाय लागू किया है जो किसानों को बाजार में मांग नहीं रहने वाली फसलों के लिए महँगे मूल्य समर्थन पर अधिक आश्रित बना देगा।
- भारत की मुद्रास्फीति बड़े स्तर पर जिंसों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों और आपूर्ति कारकों से प्रभावित रहती है, जबकि मौद्रिक नीति का प्रभाव सीमित रहता है। इसके बावजूद हमने मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए एमपीसी के तौर पर व्यापक मौद्रिक ढाँचा तैयार किया है। लेकिन एमपीसी अक्सर ब्याज दरों को काफी ऊँचा रखने की गलती करती है जिससे आर्थिक वृद्धि कम होती है और रुपये का अधिमूल्यन एवं प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता कम होती है। एमपीसी को आर्थिक वृद्धि और महँगाई नियंत्रण दोनों को समान तवज्जो देनी चाहिए।
- यह सही है कि मोदी सरकार ने कर्ज हड़पने और कर्जे देने में आनाकानी करने वालों के खिलाफ सख्ती दिखानी शुरू की है, लेकिन अभी तक अपेक्षित नतीजे सामने नहीं आ सके हैं। इसका कारण यह है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल में पहुँचे मामलों का निस्तारण धीमी गति से हो रहा है।
- पाँच माह पहले के एक आँकड़े के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल एनपीए 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया था। यह शुभ संकेत नहीं कि जब बैंक मुनाफे की स्थिति में आने के लिए हाथ-पांव मार रहे हैं तब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद करीब दो दर्जन बिजली कंपनियों पर बकाया राशि के भी एनपीए में तब्दील होने का अंदेशा उभर आया है।

गैर निष्पादित परिसंपत्ति

- बैंकों द्वारा वितरित ऐसे सभी ऋण निष्पादनीय परिसम्पत्तियाँ माने जाते है,जिनका मूलधन और उस पर देय ब्याज, समय से बैंको को प्राप्त होता रहे; इसलिए इन्हें मानक परिसम्पत्तियाँ भी माना जाता है।
- लेकिन जब बैंकों द्वारा वितरित धन पर तय समयावधि तक न तो ब्याज न ही मूलधन की प्राप्ति होती है तो इन परिसम्पत्तियाँ को गैर निष्पादित परिसम्पत्तियाँ में गिना जाता है ,क्योकि ये परिसम्पत्तियाँ देश के आर्थिक विकास में कोई योगदान या अर्जन नहीं करती है घ किसी भी प्रकार के आर्थिक उपयोग न होने और अर्थव्यवस्था में विकास को अर्जित करने की असक्षमता के कारण ऐसी परिसम्पत्तियाँ अनर्जक आस्तियाँ या परिसम्पत्तियाँ भी कहलाती है।
- गैर निष्पादित परिसंपत्ति (नॉन-परफॉर्मिंग असेट) वित्तीय संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला वर्गीकरण है जिसका सीधा सम्बन्ध कर्ज/ ऋण/ लोन न चुकाने से होता है। जब ऋण लेने वाला व्यक्ति 90 दिनों तक ब्याज या मूलधन का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसको दिया गया ऋण गैर निष्पादित परिसंपत्ति (नॉन-परफॉर्मिंग असेट) माना जाता है
- बैंक खासकर पीएसयू बैंकों का एनपीए तेजी से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2017 की पहली छमाही में कुल एनपीए 6.7 लाख करोड़ रुपये पर पहुँच गया है। कुल कर्ज का करीब 9.7 फीसदी एनपीए हो चुका है और करीब 80 फीसदी एनपीए सरकारी बैंक के खाते में है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक उद्योगों को 80% ऋण देते हैं और ऋण वितरण का यह हिस्सा एनपीए का बड़ा हिस्सा बनता है। एनपीए के बढ़ने का एक मुख्य कारण कॉर्पोरेट घरानों को बिना उनकी वित्तीय स्थिति और साख रेटिंग का उचित मूल्यांकन किए उन्हें दिए जाने वाले ऋण के नियमों में ढील देना है। साथ ही प्रतिस्पर्धा में बैंक बड़े पैमाने पर असुरक्षित ऋण दे रहे हैं, जो एनपीए के स्तर को बढ़ाने में योगदान करता है।
- बैड बैंक एक आर्थिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देयताओं को एक नये बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है। जब किसी बैंक की गैर निष्पादित संपत्ति सीमा से अधिक हो जाती है तब राज्य के आश्वासन पर एक ऐसे बैंक का निर्माण किया जाता है जो मुख्य बैंक की देयताओं को एक निश्चित समय के लिए धारण कर लेता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों को चार परिस्थितियों में विलफुल डिफॉल्टर यानी जान-बूझ कर कर्ज नहीं लौटाने वाला ग्राहक घोषित कर सकते हैं। पहला, जब देय तिथि को ग्राहक वित्तीय क्षमता होने के बावजूद कर्ज की किस्त नहीं लौटाए।
- दूसरा, कर्ज की राशि का इस्तेमाल उस कार्य के लिए नहीं किया जाए, जिसके लिए उसे प्राप्त किया गया है। तीसरा, कर्ज की राशि का इस्तेमाल संपत्ति निर्माण के लिए नहीं किया गया हो। कंपनी या ग्राहक कर्ज की राशि के उपयोग का कोई औचित्य नहीं बता सके। चौथा, कर्ज की राशि से खरीदी गई संपत्ति को किसी दूसरे पक्ष को बगैर बैंक या वित्तीय संस्थान को जानकारी दिए बेच दिया जाए।
- भारत एशिया की तीसरी बड़ी ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ बैंकिंग सेक्टर में दो-तिहाई से ज्यादा हिस्सेदारी सरकारी बैंकों की है। सरकार की रणनीति अगले 3 वर्षों में सरकारी बैंकों की संख्या घटाकर 10-12 करने की है।

PT / Mains - प्रश्न

संभावित प्रश्न

1. एनपीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
   1. भारत में 11 कंपनियाँ एनसीएलटी की अलग-अलग बेंचों के जरिये समाधान की अलग-अलग अवस्थाओं में हैं।
   2. 2017-18 में भारत सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में 40,729 करोड़ निवेश किए।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

   (उत्तर-A)

2. 'नॉन परफॉर्मिंग एसेट' क्या है?
   (a) वित्तीय संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला वर्गीकरण है, जिसका संबंध लोन चुकाने से होता है।
   (b) यह वित्तीय संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला वह वर्गीकरण है जिसका संबंध लोन न चुकाने से होता है।
   (c) यह उन बैंकों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टर्म है जो घाटे में चल रह होते हैं।
   (d) यह गैर सरकारी संस्थानों में हो रही गड़बड़ी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टर्म है।

   (उत्तर-B)

3. बिलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन नहीं आते हैं?
   (a) जो देयता बैंक को निश्चित तिथि पर वित्तीय क्षमता के बावजूद ऋण न लौटाएं।
   (b) कर्ज की राशि का इस्तेमाल उस कार्य के अलावा किसी और के लिए करें।
   (c) कर्ज की राशि का इस्तेमाल संपत्ति निर्माण के लिए न किया जाए।
   (d) कर्ज की संपत्ति से प्राप्त मुनाफे का इस्तेमाल बैंक से बिना पूछे करना।

   (उत्तर-D)

4. सार्वजनिक बैंक आईडीबीआई को उबारने के लिए किसने हाथ बढ़ाया है?
   (a) एलआईसी (b) वालमार्ट
   (c) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (d) कोटक महेन्द्रा

   (उत्तर-A)

5. भारतीय बैंकों में गैर-निष्पादित संपत्तियों की समस्या से निपटने के लिए सरकारी नीतियों की समीक्षा करें।

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न

1. भारत में बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. बैंकों का राष्ट्रीयकरण
   2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन
   3. बैंक शाखाओं द्वारा गाँवों का गोद लेना

   उपर्युक्त में कौन-सा/से भारत में वित्तीय समावेशन की दिशा में उठाया/उठाये गया/गए कदम है/हैं?
   (a) 1 और 2
   (b) 2 और 3
   (c) केवल 3
   (d) 1, 2 और 3

   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2010, उत्तर-D)

2. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें-
   1. बैंक दर
   2. खुला बाजार क्रियाएँ
   3. सार्वजनिक उधार
   4. सार्वजनिक राजस्व

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से मौद्रिक नीति के अंग है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) 2, 3 और 4
   (c) 1 और 2
   (d) 1, 3 और 4

   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2015, उत्तर-C)

3. निम्नलिखित में से कौन-सा टर्म व्यावसायिक बैंकों द्वारा सरकार को उधार देने की व्यवस्था को इंगित करता है?
   (a) नकद उधार अनुपात
   (b) उधार सेवा बाध्यता
   (c) तरलता समायोजन सुविधाएँ
   (d) सांविधिक तरलता अनुपात

   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2010, उत्तर-D)

4. प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.) बैंकरहितों को संस्थागत वित्त में लाने के लिए आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं कि इससे भारतीय समाज के गरीब तबके के लोगों का वित्तीय समावेश होगा? अपने मत की पुष्टि के लिए तर्क प्रस्तुत कीजिए।

   (IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-3, वर्ष-2016)

GS World
Committed To Excellence

समाधान प्रणाली की तरफ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-3 (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की बनाई एक समिति ने विवाद समाधान प्रक्रिया के नियामकीय ढाँचे में जिससे भारतीय पूंजी बाजार लगातार जूझता रहा है, में सुधारों पर अपनी अनुशंसाएँ दे दी हैं। इसमें मौजूदा समाधान प्रणाली के कुछ मनमाने एवं असाध्य पहलुओं को दुरुस्त करने पर ध्यान दिया गया है। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार-पत्र 'बिजनेस स्टैंडर्ड' में प्रकाशित लेख का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

अच्छी समाधान प्रणाली की तरफ बढ़ा सराहनीय कदम (बिजनेस स्टैंडर्ड)

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की बनाई एक समिति ने विवाद समाधान प्रक्रिया के नियामकीय ढाँचे में सुधारों पर अपनी अनुशंसाएँ दे दी हैं। भारतीय पूंजी बाजार इस मामले में लगातार जूझता रहा है। इस समिति ने कुछ पहल की है और कुछ मोर्चों पर चूक भी की है लेकिन सुधार संबंधी कुछ अहम सुझावों के साथ सामने आना काफी मायने रखता है। इस रिपोर्ट में इस विषय पर अमेरिकी जानकारी की भरमार है लेकिन फैसला सुनाने संबंधी जटिल सुधारों की कमी है। हालाँकि इसमें मौजूदा समाधान प्रणाली के कुछ मनमाने एवं असाध्य पहलुओं को दुरुस्त करने पर ध्यान दिया गया है। समिति ने अर्जित लाभों और निहित हानियों के परिमाणन संबंधी सिद्धांतों पर एक और रिपोर्ट जारी करने की बात कही है जिसका बेसब्री से इंतजार किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कुछ अहम सुधारात्मक उपायों का जिक्र होना प्रशंसनीय है।

पहला, केवल दो सदस्यीय समिति बनाने के लिए सेबी की तारीफ की जानी चाहिए। इस समिति में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय में सेबी के स्थायी वकील को जगह दी गई है। दरअसल अधिक सदस्यों वाली बड़ी समितियाँ किसी जटिल एवं तकनीकी मुद्दे की बारीकियों पर ध्यान केंद्रित करने में चुनौतीपूर्ण साबित होती हैं। दूसरा, मौजूदा समाधान ढाँचे में अपकृत्यों का जातीय स्वरूप भी सुधारों के दायरे में रखा गया है। समिति ने मौजूदा विनियमों में दिखने वाले बेतुकेपन से दूर रहने की बात कही है। मसलन कुछ अपकृत्यों का कभी भी समाधान नहीं हो सकता है, सेबी भले ही अपने विवेक पर उन मामलों का निपटारा भी कर सकता है।

इसके बजाय समिति ने सिद्धांतों पर आधारित समाधान ढाँचे की तरफ बढ़ने का सुझाव रखा है जिसमें बाजार पर व्यापक असर रखने वाले, अधिक निवेशकों को हुए नुकसान और बाजार की निष्ठा को चोट पहुँचाने वाले मामलों का समाधान नहीं करने की बात कही गई है। वैसे यह पैमाना काफी हद तक व्यक्तिनिष्ठ है क्योंकि हरेक मामला तकनीकी रूप से बाजार की प्रामाणिकता को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इस तरह का रवैया रखने से कम-से-कम यह संकेत तो जाएगा कि कुछ अपकृत्य दूसरों से बेहतर या बदतर होते हैं। इससे इन मामलों की सुनवाई होने पर न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों को भी संदेश भेजे जा सकेंगे। ऐसे मामलों का भी निपटारा कर सकने की सेबी की क्षमता को काफी हद तक वस्तुनिष्ठ मानक के जरिये बरकरार रखा गया है, जैसे कथित आरोपी की तरफ से कोई उपचारात्मक उपाय करना।

अनुचित प्रस्ताव (बिजनेस स्टैंडर्ड)

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने खुदरा निवेशकों को शेयर बाजार में बड़ा जोखिम उठाने से रोकने के लिए आय या शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य के आधार पर कारोबारी सीमा तय करने का प्रस्ताव रखा है। यह सुविचारित कदम नहीं है। टी.के. विश्वनाथन की अध्यक्षता में उचित बाजार आचरण को लेकर गठित समिति के प्रस्ताव के मुताबिक सेबी को खुदरा प्रतिभागियों की कारोबारी गतिविधि सीमित करना चाहिए। यह सीमा परिसंपत्ति मूल्य पर आधारित हो सकती है। जानकारी के मुताबिक बाजार नियामक अब ब्रोकरों को ऐसी व्यवस्था बनाने को कह रहा है, जहाँ क्लाइंट ब्रोकरों के पास अपना विशुद्ध परिसंपत्ति मूल्य प्रमाणपत्र पेश करेंगे। उसी के अनुसार कारोबारी सीमा निर्धारित की जाएगी।

माना जा रहा है कि ऐसा करने से छोटे निवेशकों को बड़ा नुकसान होने से रोका जा सकेगा। परंतु इस प्रस्ताव को नकारने की तमाम वजह मौजूद हैं। बाजार नियामक का काम यह सुनिश्चित करना है कि कारोबार सही और पारदर्शी ढंग से हो और बाजार से किसी तरह की छेड़छाड़ न की जाए। इसमें ब्रोकरों की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि विभिन्न एक्सचेंज उचित मार्जिन संग्रह करें ताकि डिफॉल्ट से बचा जा सके। परंतु किसी खास प्रतिभागी को होने वाला नुकसान कम करना बाजार नियामक का काम नहीं है।

परंतु इस मूलभूत सिद्धांत से परे जाकर जोखिम करने की इस व्यवस्था को लागू करने में व्यावहारिक और नैतिक दोनों तरह की कठिनाइयाँ हैं। किसी भी व्यक्ति की कुल परिसंपत्ति नितांत व्यक्तिगत मसला है, बशर्ते कि वह चुनाव मैदान में नहीं उतर रहा हो, क्योंकि चुनाव लड़ने पर आय की घोषणा अनिवार्य है। भारतीय शुद्ध आय पर कर नहीं चुकाते हैं, इसलिए उसका ब्योरा देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इसकी घोषणा का दबाव डाला गया तो यह सूचना सार्वजनिक हो जाएगी और ऐसे में अमीर व्यक्तियों के शोषण की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसी व्यवस्था बनी तो इससे लागत में इजाफा होगा और खुदरा निवेशकों के बाजार में प्रवेश को लेकर अनुपालन संबंधी बाधा उत्पन्न होगी। हर खुदरा प्रतिभागी को कारोबार के पहले मूल्यांकन प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए शुल्क चुकाना होगा। ब्रोकरों को ऐसे प्रमाणपत्रों के प्रमाण के लिए बुनियादी सुविधाएँ जुटानी होंगी। अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो उनको नियामक का कोपभाजन बनना होगा।

इतना ही नहीं शुद्ध आय किसी भी व्यक्ति की निवेश करने की क्षमता का विश्वसनीय संकेतक नहीं है। इससे यह भी पता नहीं चलता है कि उसे वित्तीय निवेश के जोखिम की कितनी समझ है। अगर एक युवा पेशेवर

तीसरा, समाधान का प्रस्ताव पेश कर पाने की समय-सीमा को बदला गया है लेकिन सेबी ने प्राकृतिक न्याय के अनुरूप सुधार करने का शानदार मौका गँवा दिया है। फिलहाल नोटिस मिलने के 60 दिनों के भीतर समाधान के लिए प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। मौजूदा दौर में भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन को लेकर एक अर्द्ध-न्यायिक अधिकारी का नजरिया दूसरे अधिकारी से अलग होता है। कुछ अधिकारी मामले से संबंधित रिकॉर्ड का पूरा मुआयना करने की इजाजत देते हैं जबकि कुछ अधिकारी चुनिंदा तथ्यों तक ही पहुँच होने देते हैं। कई बार तो निष्पक्ष मुआयने की मांग को लेकर महीनों तक कानूनी लड़ाई चलती रहती है।

रिकॉर्ड का मुआयना पूरा हो जाने के बाद 60 दिनों के भीतर जवाब देने की समय-सीमा शुरू होनी चाहिए ताकि कारण बताओ नोटिस में आरोपित व्यक्ति के पास पूरे मामले को समझ पाने का मौका मिले और उसके गुण-दोषों के आधार पर वह समाधान प्रस्ताव रख सके। आरोपों को चुनौती देने का मन बना चुके पक्ष के लिहाज से भी ऐसा करना सही होगा। समिति इस प्रक्रिया में भी सुधारों का प्रस्ताव रख सकती थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। असल में समिति ने यह प्रस्ताव रखा है कि अब 60 दिनों के बजाय 120 दिनों के भीतर समाधान प्रस्ताव रखा जा सकता है लेकिन उसे विलंब के लिए 25 फीसदी वार्षिक दर से ब्याज देने के लिए राजी होना होगा।

चौथा, विवाद निपटान संबंधी नजरिये के संदर्भ में इस समिति ने कहा है कि सेबी को पड़ताल पूरी किए बगैर किसी भी समाधान प्रस्ताव पर विचार नहीं करना चाहिए। वास्तव में, समिति ने यह कहा है कि सेबी को ऐसा रवैया तभी अपनाना चाहिए जब इससे जाँच पूरी करने में मदद मिलती हो। यह पीछे की तरफ जाने वाला कदम है। इसके बजाय समिति को इस पर गौर करना चाहिए था कि आज भी सेबी कुछ मामलों में जाँच पूरी किए बगैर नोटिस जारी करता है। अगर किसी मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है तो उसे समाधान के लायक भी माना जाना चाहिए। समिति ने समाधान प्रक्रिया जारी रहने के दौरान भी अंतरिम आदेश पारित कर पाने की सेबी के अधिकारों को बरकरार रखने की बात कही है। अगर ऐसा है तो नोटिस जारी होने के पहले ही सेबी के शिक्षा ऋण चुकाने वाला है तो संभव है उसकी शुद्ध आय नकारात्मक हो। परंतु अगर उसकी बचत दर अच्छी है तो वह नकदी वाला भी हो सकता है और निवेश सक्षम भी। ऐसी कोई भी सीमा लागू की गई तो ऐसे निवेशक निवेश करने से वंचित रह जाएँगे। वहीं एक बुजुर्ग भूस्वामी का परिसंपत्ति मूल्य काफी अधिक हो सकता है जबकि हो सकता है उसे वित्तीय बाजारों की समझ ही न हो।

निवेशकों को शिक्षित करना यकीनन सेबी के दायरे में आता है और उन ब्रोकरों पर भी लगाम लगानी चाहिए जो जान-बूझकर लोगों को भ्रमित करते हैं। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं और सक्षम कष्ट निवारण तंत्र बनाया जा सकता है। हर निवेशक को निवेश के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति जागरूक रखने के अलावा बाजार नियामक को इस प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। निवेशकों के धन का सूक्ष्म प्रबंधन करने की कोशिश सही नहीं होगी। यह बात खासतौर पर तब अधिक सही है जबकि इसमें शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य और निवेशकों के लिए नए तरह के अनुपालन की शर्त शामिल हो।

पास जाने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग की तर्ज पर इनाम भी रखा जाना चाहिए। आखिर में, इस समिति ने माना है कि समाधान की शर्तों से संबंधित हिस्से या पहचान को गोपनीय रखना भी समाधान की एक शर्त हो सकती है। समिति ने गोपनीयता पर विस्तृत चर्चा की है लेकिन वह इसे एक विचारणीय विषय के तौर पर स्वीकार करने के लिए ही राजी हुई है। इस पर अधिक तवज्जो और चर्चा की जरूरत है। संभवत: सार्वजनिक टिप्पणियाँ आने से इस पर एक जानकारीपरक चर्चा हो सकेगी।

समिति ने अस्वीकृति संबंधी नियमों का विस्तृत खाका भी पेश किया है लेकिन सेबी और आरोपित व्यक्ति के बीच होने वाली शुरुआती चर्चाओं के नियमन पर कोई बात नहीं की है। इस समय दो सिद्धांतों के बीच विरोधाभास नजर आता है। जहाँ बचाव पक्ष की ताकत अप्रासंगिक मानी जाती है वहीं कथित उल्लंघन के 'बड़े' एवं 'छोटे' चरित्र को ध्यान में रखने की बात कही जाती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

GS World टीम...

सारांश

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की बनाई एक समिति ने विवाद समाधान प्रक्रिया के नियामकीय ढाँचे में सुधारों पर अपनी अनुशंसाएँ दे दी हैं। भारतीय पूंजी बाजार इस मामले में लगातार जूझता रहा है। इस समिति ने कुछ पहल की है और कुछ मोर्चों पर चूक भी की है लेकिन सुधार संबंधी कुछ अहम सुझावों के साथ सामने आना काफी मायने रखता है।
- इस रिपोर्ट में इस विषय पर अमेरिकी जानकारी की भरमार है लेकिन फैसला सुनाने संबंधी जटिल सुधारों की कमी है। हालाँकि इसमें मौजूदा समाधान प्रणाली के कुछ मनमाने एवं असाध्य पहलुओं को दुरुस्त करने पर ध्यान दिया गया है। समिति ने अर्जित लाभों और निहित हानियों के परिमाणन संबंधी सिद्धांतों पर एक और रिपोर्ट जारी करने की बात कही है जिसका बेसब्री से इंतजार किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कुछ अहम सुधारात्मक उपायों का जिक्र होना प्रशंसनीय है।
- केवल दो सदस्यीय समिति बनाने के लिए सेबी की तारीफ की जानी चाहिए। इस समिति में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय में सेबी के स्थायी वकील को जगह दी गई है। दरअसल अधिक सदस्यों वाली बड़ी समितियाँ किसी जटिल एवं तकनीकी मुद्दे की बारीकियों पर ध्यान केंद्रित करने में चुनौतीपूर्ण साबित होती हैं।
- मौजूदा समाधान ढाँचे में अपकृत्यों का जातीय स्वरूप भी सुधारों के दायरे में रखा गया है। समिति ने मौजूदा विनियमों में दिखने वाले बेतुकेपन से दूर रहने की बात कही है। मसलन कुछ अपकृत्यों का कभी भी समाधान नहीं हो सकता है, सेबी भले ही अपने विवेक पर उन मामलों का निपटारा भी कर सकता है।
- इसके बजाय समिति ने सिद्धांतों पर आधारित समाधान ढाँचे की तरफ बढ़ने का सुझाव रखा है जिसमें बाजार पर व्यापक असर रखने वाले, अधिक निवेशकों को हुए नुकसान और बाजार की निष्ठा को चोट पहुँचाने वाले मामलों का समाधान नहीं करने की बात कही गई है।
- समाधान का प्रस्ताव पेश कर पाने की समय-सीमा को बदला गया है लेकिन सेबी ने प्राकृतिक न्याय के अनुरूप सुधार करने का शानदार मौका गँवा दिया है। फिलहाल नोटिस मिलने के 60 दिनों के भीतर समाधान के लिए प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। मौजूदा दौर

में भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन को लेकर एक अर्द्ध-न्यायिक अधिकारी का नजरिया दूसरे अधिकारी से अलग होता है। कुछ अधिकारी मामले से संबंधित रिकॉर्ड का पूरा मुआयना करने की इजाजत देते हैं जबकि कुछ अधिकारी चुनिंदा तथ्यों तक ही पहुँच होने देते हैं। कई बार तो निष्पक्ष मुआयने की मांग को लेकर महीनों तक कानूनी लड़ाई चलती रहती है।

- रिकॉर्ड का मुआयना पूरा हो जाने के बाद 60 दिनों के भीतर जवाब देने की समय-सीमा शुरू होनी चाहिए ताकि कारण बताओ नोटिस में आरोपित व्यक्ति के पास पूरे मामले को समझ पाने का मौका मिले और उसके गुण-दोषों के आधार पर वह समाधान प्रस्ताव रख सके।
- असल में समिति ने यह प्रस्ताव रखा है कि अब 60 दिनों के बजाय 120 दिनों के भीतर समाधान प्रस्ताव रखा जा सकता है लेकिन उसे विलंब के लिए 25 फीसदी वार्षिक दर से ब्याज देने के लिए राजी होना होगा।
- विवाद निपटान संबंधी नजरिये के संदर्भ में इस समिति ने कहा है कि सेबी को पड़ताल पूरी किए बगैर किसी भी समाधान प्रस्ताव पर विचार नहीं करना चाहिए। वास्तव में, समिति ने यह कहा है कि सेबी को ऐसा रवैया तभी अपनाना चाहिए जब इससे जाँच पूरी करने में मदद मिलती हो।
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने खुदरा निवेशकों को शेयर बाजार में बड़ा जोखिम उठाने से रोकने के लिए आय या शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य के आधार पर कारोबारी सीमा तय करने का प्रस्ताव रखा है। यह सुविचारित कदम नहीं है। टी.के. विश्वनाथन की अध्यक्षता में उचित बाजार आचरण को लेकर गठित समिति के प्रस्ताव के मुताबिक सेबी को खुदरा प्रतिभागियों की कारोबारी गतिविधि सीमित करना चाहिए। यह सीमा परिसंपत्ति मूल्य पर आधारित हो सकती है। जानकारी के मुताबिक बाजार नियामक अब ब्रोकरों को ऐसी व्यवस्था बनाने को कह रहा है जहाँ क्लाइंट ब्रोकरों के पास अपना विशुद्ध परिसंपत्ति मूल्य प्रमाणपत्र पेश करेंगे। उसी के अनुसार कारोबारी सीमा निर्धारित की जाएगी।
- बाजार नियामक का काम यह सुनिश्चित करना है कि कारोबार सही और पारदर्शी ढंग से हो और बाजार से किसी तरह की छेड़छाड़ न की जाए। इसमें ब्रोकरों की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि विभिन्न एक्सचेंज उचित मार्जिन संग्रह करें ताकि डिफॉल्ट से बचा जा सके।
- भारतीय शुद्ध आय पर कर नहीं चुकाते हैं, इसलिए उसका ब्योरा देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इसकी घोषणा का दबाव डाला गया तो यह सूचना सार्वजनिक हो जाएगी और ऐसे में अमीर व्यक्तियों के शोषण की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसी व्यवस्था बनी तो इससे लागत में इजाफा होगा और खुदरा निवेशकों के बाजार में प्रवेश को लेकर अनुपालन संबंधी बाधा उत्पन्न होगी। हर खुदरा प्रतिभागी को कारोबार के पहले मूल्यांकन प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए शुल्क चुकाना होगा।
- निवेशकों को शिक्षित करना यकीनन सेबी के दायरे में आता है और उन ब्रोकरों पर भी लगाम लगानी चाहिए जो जानबूझकर लोगों को भ्रमित करते हैं। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं और सक्षम कष्ट निवारण तंत्र बनाया जा सकता है। हर निवेशक को निवेश के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति जागरूक रखने के अलावा बाजार नियामक को इस प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को हुई थी । भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की उद्देशिका में सेबी के मूल कार्यों का उल्लेख इस प्रकार है - प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज) में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज मार्केट) के विकास का उन्नयन करना तथा उसे विनियमित करना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना ।
- इसकी स्थापना आधिकारिक तौर पर वर्ष 1988 में भारत सरकार द्वारा की गई और भारतीय संसद द्वारा पारित सेबी अधिनियम, 1992 के साथ 1992 में इसे संवैधानिक अधिकार दिया गया था। सेबी के अस्तित्त्व में आने से पहले पूंजी निर्गम नियंत्रक नियामक प्राधिकरण था, जिसे पूंजी मुद्दे (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त थे।
- सेबी (संशोधन) अधिनियम, 2002 संसद में पारित होकर 29 अक्टूबर, 2002 से लागू हुआ जो शेयर बाजार में गड़बड़ियों के दोषियों को अधिक कठोर सजा के लिए सेबी को व्यापक अधिकार उपलब्ध कराता है। इस अधिनियम के अंतर्गत इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए सेबी द्वारा 25 करोड़ रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। लघु निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामलों में एक लाख रुपये प्रतिदिन की दर से, एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी इस अधिनियम में है। किसी भी शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करने का अधिकार सेबी को प्रदान किया गया है।
- सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और सेबी के कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो क्रमश: दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद में स्थित है।
- सेबी के संपूर्ण प्रबंधन में 6 सदस्य होते हैं। इसमें से एक सदस्य अध्यक्ष होता है,और अन्य पाँच सदस्य के अलग कार्य के होते हैं। सेबी में एक अध्यक्ष होता है, जिसका नामांकन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल 3 साल के लिए होता है या 65 वर्ष की उम्र तक होता है, इसमें से जो भी पहले हो। बाकी चार सदस्यों को भी भारत सरकार ही चुनकर भेजती है। इनमें से 2 सदस्य वित्त मंत्रालय के जानकार और 2 कानून के जानकार होते हैं। शेष 1 सदस्य आरबीआई (RBI) के होते हैं, उनका चयन आरबीआई के अधिकारियों में से किया जाता है।
- समिति ने सिद्धांतों पर आधारित समाधान ढाँचे की तरफ बढ़ने का सुझाव रखा है जिसमें बाजार पर व्यापक असर रखने वाले, अधिक निवेशकों को हुए नुकसान और बाजार की निष्ठा को चोट पहुँचाने वाले मामलों का समाधान नहीं करने की बात कही गई है।
- समिति ने यह प्रस्ताव रखा है कि अब 60 दिनों के बजाय 120 दिनों के भीतर समाधान प्रस्ताव रखा जा सकता है लेकिन उसे विलंब के लिए 25 फीसदी वार्षिक दर से ब्याज देने के लिए राजी होना होगा।
- विवाद निपटान संबंधी नजरिये के संदर्भ में इस समिति ने कहा है कि सेबी को पड़ताल पूरी किए बगैर किसी भी समाधान प्रस्ताव पर विचार नहीं करना चाहिए। वास्तव में, समिति ने यह कहा है कि सेबी को ऐसा रवैया तभी अपनाना चाहिए जब इससे जाँच पूरी करने में मदद मिलती हो। यह पीछे की तरफ जाने वाला कदम है।

PT / Mains - प्रश्न

संभावित प्रश्न

1. सेबी का स्थापना दिवस है-
   (a) 11 अप्रैल, 1994 (b) 12 अप्रैल, 1994
   (c) 12 अप्रैल, 1991 (d) 12 अप्रैल, 1992

(उत्तर-D)

2. निम्नलिखित में से कौन-से कार्य सेबी द्वारा संचालित किया जाता है?
   1. प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना।
   2. प्रतिभूति बाजार के विकास का उन्नयन करना।
   3. बैंकों के लेन-देन पर नजर रखना

   कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें-
   (a) 1 और 2
   (b) 1, 2 और 3
   (c) 1 और 3
   (d) 2 और 3

(उत्तर-A)

3. निम्नलिखित में से कौन-सा/से प्रावधानों को नवनिर्मित समिति ने मानने का प्रस्ताव रखा है?
   1. 60 के बजाय 180 दिनों के भीतर समाधान प्रस्ताव
   2. विलंब के लिए 25फीसदी वार्षिक दर से ब्याज के लिए राजी होना।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

(उत्तर-B)

4. सेबी अधिनियम, 2002 के अनुसार सेबी को निम्नलिखित में से कौन-से अधिकार प्राप्त हुए?
   1. इसके अंतर्गत इनसाइडर ट्रेनिंग के लिए सेबी द्वारा 25 करोड़ रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है।
   2. लघु निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामलों में 1 लाख से 10 लाख रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है।

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

(उत्तर-A)

5. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की भूमिका एवं कार्यों की समीक्षा करें।

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
   भारत में स्टॉक एक्सचेंज एवं फ्यूचर मार्केट में लेन-देन पर करों को-
   1. केंद्र लगाता है
   2. राज्य वसूलते हैं।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

(IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2010, उत्तर-A)

2. जोखिम-पूँजी का अर्थ हैं?
   (a) उद्योगों को लघु अवधि पूँजी प्रदान करना।
   (b) नए व्यवसायियों को दीर्घ-अवधि स्टार्टअप पूँजी प्रदान करना।
   (c) उद्योगों को हानि होने के समय फंड प्रदान करना।
   (d) उद्योगों के पुनर्स्थापन एवं नवीकरण के लिए फंड उपलब्ध कराना।

(IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2014, उत्तर-B)

3. 'राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
   1. यह नीति आयोग का एक अंग है।
   2. वर्तमान में इसकी निधि 4,00,000 करोड़ है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

(IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2017, उत्तर-D)

4. वित्तीय संस्थाओं व बीमा कंपनियों द्वारा की गई विविधता के फलस्वरूप उत्पादों व सेवाओं में उत्पन्न परस्पर व्यापन ने सेबी (SEBI) व इरडा (IRDA) नामक दोनों नियामक अभिकरणों के विलय के प्रकरण को प्रबल बनाया है। औचित्य सिद्ध कीजिए।

(IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-2, वर्ष-2013)

GS World
Committed To Excellence

भारतीय रिजर्व बैंक की नोटबंदी पर सालाना रिपोर्ट

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-3 (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

भारतीय रिजर्व बैंक की नोटबंदी पर सालाना रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में पहली बार रिजर्व बैंक ने यह बताया कि नोट बैन करने के नवंबर, 2016 के फैसले के बाद कितने नोट उसके पास वापस आए। 99.3 फीसदी प्रतिबंधित नोट वापस आ जाने से इस बात का सबूत बताया जा रहा है कि नोटबंदी का फैसला हर तरह से नाकाम रहा। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार-पत्रों 'नवभारत टाइम्स', 'दैनिक जागरण', 'बिजनेस स्टैंडर्ड', 'दैनिक ट्रिब्यून', 'अमर उजाला' तथा 'राष्ट्रीय सहारा' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

नोटबंदी से आगे (नवभारत टाइम्स)

बुधवार को जारी हुई भारतीय रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट (2017-18) एक तरह से नोटबंदी की भेंट चढ़ गई। इस रिपोर्ट में पहली बार रिजर्व बैंक ने यह बताया कि 500 और 1000 रुपये के नोट बैन करने के नवंबर 2016 के फैसले के बाद कितने नोट उसके पास वापस आए। इसके बाद पूरी बहस इसी एक पहलू पर सिमट गई, जिससे इस रिपोर्ट की अन्य महत्त्वपूर्ण बातें काफी कुछ अनदेखी रह गईं। हालाँकि नोटबंदी के व्यापक असर और रिजर्व बैंक द्वारा नोट गिनने में हुए ऐतिहासिक विलंब को देखते हुए न केवल मीडिया बल्कि राजनीति का भी ध्यान इस पहलू पर केंद्रित होना स्वाभाविक था। 99.3 फीसदी प्रतिबंधित नोट वापस आ जाने को विपक्ष की ओर से इस बात का सबूत बताया गया कि नोटबंदी का फैसला हर तरह से नाकाम रहा। बहरहाल, राजनीतिक बयानों से हटकर देखें तो नोटबंदी की इस कवायद ने एक बात साफ कर दी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी का जो हौवा खड़ा किया जाता रहा है, उसकी मौजूदगी नोटों की शक्ल में ना के बराबर ही थी। इस कदम ने कैश इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति पर कुछ अंकुश लगाया, साथ ही चोटी के न सही पर बीच के खिलाड़ियों में यह खौफ कायम किया कि उनके खेल सरकार की नजर में है। कुछ अन्य फायदे क्या इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि इनकी रोशनी में नोटबंदी के फैसले को जरूरी या उचित माना जाए, यह बहस जल्दी हल नहीं होने वाली।

लिहाजा, इसे छोड़कर फिलहाल उन बिंदुओं पर नजर डाली जाए जो रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट से उभर कर सामने आते हैं। इस रिपोर्ट की एक चिंताजनक बात यह है कि बैंकों के एनपीए का स्तर लाख प्रयासों के बावजूद न सिर्फ अभी बल्कि अगले साल भी नीचे आता नहीं दिख रहा। रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल यह 11.5 फीसदी के मौजूदा स्तर से और ऊपर जा सकता है। विश्व व्यापार में जारी संरक्षणवादी प्रवृत्ति बाहरी बाजारों में भारतीय उत्पादों की मांग को प्रभावित करेगी। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल कीमतों के और चढ़ने का अंदेशा है, जबकि डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत अभी और नीचे जाने की आशंका बनी हुई है। इन सबसे एक तरफ व्यापार घाटा बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है, दूसरी तरफ आयातित महँगाई की तलवार भी सिर पर लटकी हुई है। इन चुनौतियों के बरक्स अच्छी बात यह है कि कृषि उत्पादन लगातार तीसरे साल अच्छा रहने की उम्मीद है। जीडीपी की अनुमानित वृद्धि दर 7.4 फीसदी बताई गई है जो पिछले साल के 6.7 फीसदी से काफी बेहतर है। आगे हमें घरेलू बाजार को इतनी मजबूती देनी होगी कि बाहरी बाजारों से होने वाले नुकसान की अधिक से अधिक भरपाई की जा

नोटबंदी पर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट को लेकर विपक्षी दलों के मोदी सरकार पर चौतरफे हमले (दैनिक जागरण)

नोटबंदी पर रिजर्व बैंक की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट आने के बाद विपक्षी दलों समेत अन्य आलोचकों की ओर से सरकार को घेरना स्वाभाविक ही है। रिजर्व बैंक के अनुसार नोटबंदी के समय देश भर में पाँच सौ और एक हजार के कुल 15 लाख 41 हजार करोड़ रुपये के नोट चलन में थे, लेकिन उनमें से 15 लाख 31 हजार करोड़ रुपये के नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए। इसका मतलब है कि करीब दस हजार करोड़ रुपये ही वापस नहीं आ सके। यह कोई बड़ी रकम नहीं। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि दावा तो यह किया गया था कि कालेधन के रूप में लगभग ढाई-तीन लाख करोड़ रुपये बैंकों में लौटने वाले नहीं और वे रद्दी हो जाएँगे। ऐसा नहीं हुआ तो इसका एक बड़ा कारण यह रहा कि बैंकिंग तंत्र ने कालेधन वालों से मिलीभगत कर ली।

हैरानी है कि इतना बड़ा फैसला लेने के पहले किसी ने यह क्यों नहीं सोचा कि कहीं बैंककर्मी सारी मेहनत पर पानी न फेर दें? आखिर इसे लेकर कोई सही आकलन क्यों नहीं किया जा सका कि लोग अपने कालेधन को सफेद बनाने के लिए क्या-क्या जतन कर सकते हैं? अच्छा होगा कि सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया जाए कि जब दस हजार करोड़ रुपये छोड़कर सारी रकम बैंकों में आ गई तो नोटबंदी को सफल कैसे कहा जा सकता है? चूँकि करीब इतनी ही रकम नए नोट छापने और उन्हें देश के सभी इलाकों में भेजने में खर्च हो गई, इसलिए इस पर आश्चर्य नहीं कि नोटबंदी को व्यर्थ की कसरत बताया जा रहा है।

ध्यान रहे कि नोटबंदी से नकली नोटों के साथ ही आतंकी एवं नक्सली गुटों पर लगाम लगने के दावे भी बहुत पुख्ता नहीं कहे जा सकते। करदाताओं की संख्या में वृद्धि को नोटबंदी की एक सफलता के तौर पर अवश्य रेखांकित किया जा सकता है, लेकिन सभी जानते हैं कि यह इस फैसले का मूल मकसद यह नहीं था। मूल मकसद तो कालेधन वालों की कमर तोड़ना था।

नोटबंदी पर विपक्ष के तीखे सवालों के बीच सरकार की ओर से एक बार फिर यह कहा गया कि बैंकों में जमा हो गए सारे धन को सफेद नहीं कहा जा सकता और करीब 18 लाख जमाकर्त्ता संदिग्ध किस्म के पाए गए हैं। ये वे लोग हैं जिनसे यह पूछा जा रहा है कि उन्होंने बैंक में जमा अपना पैसा कैसे अर्जित किया? सरकार की मानें तो इनमें से तमाम से टैक्स और जुर्माना वसूल किया जा रहा है। बेहतर हो कि सरकार की ओर से यह साफ किया जाए कि अब तक टैक्स और जुर्माने से कितनी राशि वसूल की जा चुकी है और सभी संदिग्ध खाताधारकों की जाँच-पड़ताल कब तक पूरी हो जाएगी?

सके। वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का कठिन कार्यभार भी इस चुनावी साल में पूरा करना होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अच्छी राजनीति का संतुलन हम अच्छी अर्थनीति के साथ किस हद तक बना पाते हैं।

नोटबंदी के निष्कर्ष (बिजनेस स्टैंडर्ड)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की बुधवार को जारी वार्षिक रिपोर्ट कुछ हद तक सरकार की नोटबंदी की कवायद पर भी नतीजे पेश करती है। सरकार ने 8 नवंबर, 2016 को 500 और 1,000 रुपये की तत्कालीन मुद्रा बंद करने की घोषणा की थी जो कुल प्रचलित मुद्रा का 86 फीसदी थी। रातोंरात नोटबंदी के लिए कई दलील दी गई थीं। इनमें नकदी के रूप में भंडारित काले धन का खात्मा, सरकार को प्रचुर लाभ, देश के भुगतान तंत्र के डिजिटलीकरण और बचत को वित्तीय परिसंपत्तियों में बदलने जैसी बातें शामिल थीं। आरबीआई का कहना है कि नोटबंदी में बंद कुल नकदी में से 99.3 प्रतिशत नोट बाद के दिनों में सरकार की घोषणा के मुताबिक विभिन्न बैंकों में बदल लिए गए। आरबीआई की इस बात के लिए सराहना की जानी चाहिए कि उसने अंतिम आँकड़े जारी करने में सावधानी बरती, भले ही ये आँकड़े मौजूदा सरकार के लिए राजनीतिक रूप से शर्मिंदगी भरे क्यों न साबित हों। नीतिगत दृष्टि से देखें तो अब यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि नोटबंदी के लिए तय लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके हैं।

सर्वाधिक आशावादी दृष्टिकोण दो अनुमानों पर आधारित था: पहला अनुमान यह था कि बहुत बड़ी मात्रा में नकदी को कर अधिकारियों से छिपाकर रखा गया है। दूसरा अनुमान यह था कि यह नकदी तंत्र में वापस नहीं आएगी, कम से कम उचित कर दर पर तो बिल्कुल नहीं। अगर नकदी उच्च कर दर पर वापस आती तो सरकार को अच्छा कर प्राप्त होता। अगर ऐसा नहीं होता तो इसे आरबीआई की बैलेंस शीट पर प्रचुर लाभ के रूप में दर्ज किया जाता क्योंकि तब वह इसे सरकार को सौंप सकता था। परंतु 99.3 प्रतिशत बंद नोटों की वापसी ने इस आकलन की धज्जियां उड़ा दीं। अन्य संभावित लाभ की बात भी परवान नहीं चढ़ी। उदाहरण के लिए ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि नकली नोट बनाने वाले नए नोटों की नकल नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा चूँकि 500 और 1,000 रुपये के नोट की जगह 2,000 रुपये के नोट जारी किए गए तो यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि भला उच्च मूल्य मुद्रा में होने वाले लेन-देन या भारी भरकम नकद राशि के भंडारण पर रोक कैसे लगेगी।

दुख की बात तो यह है कि नोटबंदी की कवायद ने आम घरों की बचत पर नकारात्मक प्रभाव डाला। आरबीआई ने बीते वर्षों के दौरान आम घरों की बचत के जो आँकड़े जारी किए हैं वे भी काफी कुछ बताते हैं। आम पारिवारिक बचत में छोटे असंगठित क्षेत्र के उद्यमों की बचत भी शामिल होती है। इन्हें भी नोटबंदी ने तगड़ा झटका दिया। हालाँकि आम पारिवारिक बचत 11 फीसदी सकल राष्ट्रीय व्यय योग्य आय के साथ कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर है परंतु इसकी बनावट का विश्लेषण दिलचस्प है। सच तो यह है कि आम परिवारों के पास अब नोटबंदी के पहले से ज्यादा नकदी बचत के रूप में है। बैंक जमा में आई उल्लेखनीय गिरावट की यह भी एक वजह हो सकती है। हालाँकि शेयर बाजार का बेहतर प्रदर्शन भी इसका एक कारण है। दूसरे शब्दों में कहें तो बचत को वित्तीय तंत्र में लाने की कोशिश नाकाम रही। चाहे जो भी हो, सकल घरेलू उत्पाद में नकदी का अनुमान ऐसे स्तर पर पहुँच चुका है जिसकी तुलना नोटबंदी के पहले के स्तर से की जा सकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि नोटबंदी से जो भी बदलाव आए वे सरकार की अपेक्षाओं से परे थे। अब आशा की जानी चाहिए कि सरकार भविष्य में नीतियाँ बनाते समय इस घटना से जरूरी सबक लेगी और नोटबंदी जैसे ऐसे कदमों से बचेगी जिन्होंने अर्थव्यवस्था को स्पष्ट रूप से धक्का पहुँचाया।

यह ठीक है कि 18 लाख लोगों से जवाब-तलब एक बड़ा काम है, लेकिन यह प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए और इसमें वैसी देर नहीं होनी चाहिए जैसी नोटबंदी पर रिजर्व बैंक की रपट सामने आने में हुई। नोटबंदी जितना अप्रत्याशित उतना ही बड़ा फैसला था। चूँकि इस फैसले ने हर एक पर असर डाला इसलिए सरकार को हर तार्किक सवाल का संतोषजनक जवाब देना चाहिए।

नोटबंदी का सच (दैनिक ट्रिब्यून)

सारे भारत को झकझोर कर बेचैन करने वाली नोटबंदी के परिणामों पर आरबीआई की रिपोर्ट 'खोदा पहाड़ निकली चुहिया' की कहावत को चरितार्थ करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की चूलें हिला देने वाले इस फैसले ने 21वीं सदी में तुगलकी कसरतों की याद दिला दी। कुल प्रतिबंधित मुद्रा का 99.3 फीसदी बैंकों में पहुँच जाना इस कवायद की नाकामी को ही दर्शाता है। लगता है कि जो बची मुद्रा नहीं लौटी, वो अंटी में जमा रखने वालों और उन गृहिणियों की रही होगी, जो भविष्य की जरूरतों के लिये इसे बचाये रखती थीं। इस बची राशि का दूसरा पहलू यह भी है कि भूटान व नेपाल में पुरानी करेंसी चल रही है। हालांकि, इस नोटबंदी को पलीता लगाने वालों में अर्थव्यवस्था की काली भेड़ें भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने शातिर तौर-तरीकों से काले धन को सफेद धन में तब्दील किया। बंद हुई फर्जी कंपनियों व हवाला कारोबारियों की तरफ भी उंगलियां उठीं और सहकारी बैंकों के जरिये राजनेताओं द्वारा काले धन को सफेद करने का मुद्दा भी सामने आया। बहरहाल, इस नोटबंदी ने छोटे उद्योग-धंधों को ठप भी किया। इस दौरान जो कुछ मौतें हुई, उनकी जवाबदेही भी वक्त तय करेगा।

दूसरे, इन नोटों की वापसी, उन्हें गिनने में बाइस महीने लगे और नष्ट करने में जो श्रम लगा, उसकी भरपाई करना संभव नहीं है। विडंबना है कि आज नोटबंदी से तीन लाख करोड़ से ज्यादा मुद्रा फिर चलन में है। इसका साइड इफेक्ट यह भी है कि नोटबंदी के बाद दो हजार व पाँच सौ के नकली नोटों के प्रतिशत में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इसके अलावा नये नोटों को छापने का खर्च बीते वर्ष 133 फीसदी बढ़ा। नकारात्मक पक्ष यह भी है कि बीते वर्ष में रिजर्व बैंक से सरकार को मिलने वाला पैसा भी घटा है। सरकार ने नोटबंदी के चार मकसद बताये थे कि इससे आतंकवाद कम होगा, जो वास्तव में नहीं हुआ। दूसरा, काला धन बाहर आयेगा, वो नहीं आया। सरकार का दावा भ्रष्टाचार कम करने का था, मगर दुनिया के भ्रष्ट देशों में भारत का नंबर जहाँ 2016 में 79वाँ था, वहीं 2017 में वह 81वें स्थान पर पहुँच गया। चौथा फायदा सरकार ने डिजिटल ट्रांजेक्शन का बताया था, इसमें सरकार जरूर कामयाब हुई है। वर्ष 2016 के मुकाबले 2017 में डिजिटल पेमेंट की राशि 40 फीसदी तक बढ़ी है। ऐसे में यह दावा कि अर्थव्यवस्था से तीन-चार लाख करोड़ रुपये का काला धन सिस्टम से बाहर निकल जायेगा, विफल रहा है।

नोटबंदी से नुकसान (अमर उजाला)

सो अब साबित हो गया है कि नोटबंदी से काला धन हासिल नहीं हुआ है। आठ नवंबर, 2016 की मध्य रात्रि से जितने पुराने नोट रद्द किए गए थे, तकरीबन उतने ही बैंकों में वापस आ गए। हासिल केवल यह हुआ है कि जिन अर्थशास्त्रियों और राजनीतिक पंडितों ने उस समय कहा था कि नोटबंदी से नुकसान अधिक होगा और लाभ कम, वे सही निकले हैं। पिछले सप्ताह द वॉशिंगटन पोस्ट जैसे प्रसिद्ध अखबार ने खूब मजा लेते हुए इस बारे में लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी तक नोटबंदी को लेकर कोई सफाई नहीं आई है, पर राहुल गांधी

कुछ हासिल नहीं हुआ (राष्ट्रीय सहारा)

हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि नोटबंदी के बाद बैंकों में 99.3 प्रतिशत मुद्रा लौट आई यानी मात्र .7 प्रतिशत धन बैंकों में वापस नहीं पहुंचा। दस से ग्यारह हजार करोड़ रुपये बिना हिसाब-किताब का था, यह पता लगाने में दो साल का समय लगा दिया गया। हालाँकि यह पता लगाना भी कोईनई बात नहीं है। मैंने जून, 2017 में एक प्रतिष्ठित पत्रिका में अपने लेखमें इस स्थिति का उल्लेख किया था। आरबीआई ने अब जो आँकड़ा दिया है, उस पर मेरा कहना है कि नोटबंदी के बाद शत-प्रतिशत पैसा वापस आया है। नेपाल और भूटान में भारतीय मुद्रा हो सकने के मद्देनजर तो यह तक कह सकते हैं कि आँकड़ा सौ प्रतिशत से ज्यादा हो सकता है। कहना यह कि नोटबंदी के बाद पूरा पैसा प्रणाली में लौट आया है। सारा पैसा खातों में पूरा हो गया है बल्कि नोटबंदी से तो तीस से चार लाख करोड़ रुपये का काला धन नये नोटों में कन्वर्ट हो गया है। नकली मुद्रा की समस्या जस की तस है। पिछले साल चालीस हजार करोड़ की नकली मुद्रा चलन में होने का अनुमान था, आज भी दस हजार करोड़ रुपये की ऐसी करेंसी चलन में हो सकती है। यानी यह जो कमी है, उसके नये नोटों में तब्दील हो चुकने के अंदेशे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो पूछना होगा कि नोटबंदी से कितना काला धन निकला है?नोटबंदी के दौरान जिन खातों में पाँच लाख से ज्यादा धन जमा कराया गया था, उन खातों की तहकीकात किए जाने की बात बताई गई है। इस बाबत आयकर विभाग ने 18 लाख लोगों को नोटिस भी दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि इन नोटिसों का हासिल क्या होगा? एक तो आयकर विभाग में मानव संसाधन की कमी है, और दूसरी बात यह भी है कि आरोपितों को सजा दिलाने में आयकर विभाग के पसीने छूट जाते हैं। कुल मामलों में मुश्किल से चार-पाँच प्रतिशत मामलों में ही विभाग सजा दिला पाता है। इससे भी काले धन की कमाई करने वालों के हौसले सातवें आसमान पर बने रहते हैं। नोटबंदी के बाद ऐसे लोगों के हौसले में पस्ती आ गई हो, यह भी नहीं कहा जा सकता। कह सकते हैं कि काले धन की अर्थव्यवस्था अपना खेल जारी रखे हुए है। काला धन बनाया जाना जारी है। कैश इन हैंड काला धन नहीं होता। पिछले तीन-चार सालों से जमीन-जायदाद का धंधा मंदा पड़ा हुआ था। चूँकि एकाएक नोटबंदी लागू कर दी गई। तो कैश इन हैंड के नाम पर बिल्डर्स ने काफी धन बैंक में जमा कराया। यह काला धन भी हो सकता है, जिसे कैश इन हैंड की आड़ में सफेद किया गया। इसी प्रकार संभव है कि निजी अस्पतालों, निजी स्कूलों आदि ने भी कैश इन हैंड के नाम पर काफी काला धन बैंकों में जमा कराया हो। इस तरीके से काला धन जमा कराने वालों को पकड़ पाना संभव नहीं होगा। नोटबंदी के बाद काला धन बनाने के तौर-तरीके निर्बाध जारी हैं। अंडर इन्वॉयसिंग और ओवर इन्वॉयसिंग के जरिये काला धन पैदा किया जाना नहीं रुका है। कहा गया है कि नोटबंदी से टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। दरअसल, पहले जो लोग टीडीएस के दायरे में नहीं थे, वे टैक्स रिटर्न नहीं भर रहे थे। उन लोगों द्वारा रिटर्न भरे जाने से टैक्स रिटर्नस की संख्या में इजाफा दिखाई दे रहा है। हकीकत तो यह है कि टैक्स रिटर्नस भरने वालों में प्रभावी करदाताओं की संख्या अभी भी 2012-13 के समान ही है। तो इसके कोईमायने नहीं है कि टैक्स रिटर्न्स भरने वाले कितने हैं, महत्त्वपूर्ण यह है कि वास्तविक करदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, या नहीं। उस मामले में हमें कोई उत्साहजनक तस्वीर देखने को नहीं मिलती। इसी प्रकार की स्थिति जीएसटी को लेकर भी है। काले धन पर प्रभावी रोक के लिए जरूरी है कि कर संग्रहण में इजाफा हो। काले धन के मामले में एक दुष्चक्र है, जिसे टूटना चाहिए। नोटबंदी के प्रभाव को जानने के लिए यह जानना होगा कि अर्थव्यवस्था में काला धन बनना क्या जारी है? खुलकर कह रहे हैं कि मोदी ने नोटबंदी का फैसला संघ परिवार के कुछ बुद्धिजीवियों से सलाह लेकर लिया था। इनके बारे में जाने-माने अर्थशास्त्री जगदीश भगवती ने कभी कहा था कि ये लोग अगर अर्थशास्त्री हैं, तो मैं भरतनाट्यम की नृत्यांगना हूँ।

खैर, जो होना था, हो चुका है। मोदी की समस्या यह है कि अब यह भी साबित होने लगा है कि उनके दौर में रोजगार के नए अवसर इतने कम पैदा हुए कि पिछले हफ्ते जब भारतीय रेल ने 90,000 नौकरियों की घोषणा की, तो करीब ढाई करोड़ युवाओं ने आवेदन किया। हाल में यह खबर भी सुर्खियों में रही है कि देश के नौजवान सरकारी नौकरियाँ पहले से ज्यादा पसंद करने लगे हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र में बहुत कम नई नौकरियाँ आई हैं। बेरोजगारी से नोटबंदी का रिश्ता यह है कि काले धन की तलाश जब युद्ध स्तर पर होने लगती है, तो निवेशक घबरा जाते हैं। मोदी के दौर में कुछ ऐसा ही हुआ है।

ऐसा नहीं है कि देश में काला धन नहीं है। अवश्य है, लेकिन उसे ढूँढ निकालना आसान नहीं है, क्योंकि आजकल लोग इसे नकद में कम ही रखते हैं। अधिकतर लोग इसे जमीन-जायदाद या गहनों में तब्दील कर देते हैं, ताकि ये आयकर विभाग के जासूसों से छिप जाएँ। शायद राजनेता और राजनीतिक दल ही काला धन नकद में रखते हैं, क्योंकि काले धन के बिना चुनावों की गाड़ी नहीं चल सकती। राजनेता अच्छी तरह जानते हैं कि उनका काला धन उद्योगपतियों और कारोबारियों से आता है, सो सत्ता में आते ही इन्हें खोजने की कोशिश में लग जाते हैं। इनकी आदत पुरानी है। पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री बनते ही उन लोगों के घरों में छापे डलवाए थे, जिन्होंने कांग्रेस को चंदा दिया था। आयकर विभाग के अफसरों के लिए ये छापे लाभदायक होते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह।

माना जाता है कि पिछले चार वर्षों में अनेक भारतीय निवेशक देश छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि आयकर अधिकारियों के हस्तक्षेप के कारण कारोबार करने का माहौल बहुत खराब रहा है। नोटबंदी के कारण भी कुछ छोटे कारोबारी कंगाल होने से पहले ही सब कुछ बेचकर भाग गए थे। वे नहीं गए होते, तो निजी क्षेत्र में आज नई नौकरियाँ उपलब्ध होतीं और अगले लोकसभा चुनाव में मोदी की जीत तय होती, क्योंकि अर्थव्यवस्था में ऊर्जा पैदा हो गई होती। पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी को पूर्ण बहुमत मिलने का मुख्य कारण उनका मतदाताओं को यह विश्वास दिलाना था कि वह रोजगार के करोड़ों नए अवसर पैदा करके दिखाएंगे। अगले वर्ष मोदी को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो इसका मुख्य कारण यही होगा कि अर्थव्यवस्था में वही मंदी दिखने लग गई है, जो 2014 में मायूसी फैला रही थी। कहने का मतलब यह है कि काले धन की खोज ने न सिर्फ देश का, बल्कि निजी तौर पर नरेंद्र मोदी का भी नुकसान किया है। लाभ अगर किसी को हुआ है, तो कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को।

Committed To Excellence

और काली कमाई के हालात पूर्ववत हैं क्या? सच तो यह है कि नोटबंदी के बाद ये दोनों ही सवाल अनुत्तरित हैं। नोटबंदी से पहले अक्टूबर, 2016 में हमारी अर्थव्यवस्था चीन से टक्कर ले रही थी। लेकिन इस एक फैसले ने अर्थव्यवस्था को धराशायी कर दिया। डेढ़ लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था को दस लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। असंगठित क्षेत्र की तो कमर ही टूट गई है। किसानी को फसल की बुआईतक में परेशानी हुई। इससे कृषि की उत्पादकता पर बुरा प्रभाव पड़ा। असंगठित क्षेत्र ज्यादातर नकदी का इस्तेमाल होता है। चूँकि नोटबंदी ने इस क्षेत्र की नकदी का क्षरण किया तो इसलिए छोटे-मोटे रोजगार ठप्प पड़ गए। छोटे कारोबारियों को अपने काम-धंधे बंद करने पड़े। कामगारों के पास काम नहीं रहा तो वे अपने घर-गांव लौट गए। बड़ोदा, सूरत, अहमदाबाद, अलीगढ़ और पंजाब के लुधियाना जैसे शहरों में जो छोटे उद्योग हैं, उनका चक्का थम गया। कामगारों के घरों को लौटने के चलते मनरेगा पर दबाव बढ़ा। मनरेगा में बजट आवंटन से ज्यादा राशि की मांग होने लगी है। 2016 के बजट में मनरेगा के लिए 38 हजार करोड़ रुपये का आवंटन हुआ था, जबकि मांग निकली 47 हजार करोड़ रुपये की। नोटबंदी ने असंगठित क्षेत्र की कमर तोड़ी जबकि वास्तविकता यह है कि काला धन संगठित क्षेत्र में पैदा होता है। यह गलत धारणा है कि नकदी की अधिक जरूरत होने से असंगठित क्षेत्र काले धन ज्यादा पैदा करता है। संगठित क्षेत्र में पहले से ही डिजिटलाइजेशन है, तो नोटबंदी के फायदे के तौर पर यह जो गिनाया जा रहा है कि इस फैसले से डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिला है, वह बेमानी है। इस सोच का कोई मायने नहीं है कि नकदी के लेन-देन वाले क्षेत्र में काला धन पैदा होता है। फिर, यह कहने में भी कोई तुक नहीं कि नकदीविहीन बना दिए जाने से भ्रष्टाचार थम जाएगा। नाइजीरिया में जीडीपी का 1.4 प्रतिशत नकदी में है, स्वीडन और जापान में भी करीब-करीब यही आँकड़ा है, लेकिन नाइजीरिया में भ्रष्टाचार जापान और स्वीडन की तुलना में कहीं ज्यादा है। तो यह कहना कि नकदीविहीन हो जाने से भ्रष्टाचार पर लगाम लग जाती है, बेमानी है। फिर यह कहे जाने, कि नोटबंदी से नकदी का प्रवाह कम हुआ है, की पोल यह आँकड़ा खोल देता है कि नवम्बर, 2016 जहाँ 18 लाख करोड़ रुपये का नकदी प्रवाह था, वहीं अब यह 23 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। नोटबंदी के चलते छोटे कारोबारियों को अपनी पूंजी तक खर्च करनी पड़ी है, जिसके निकट भविष्य में बिल्ड-अप होने की संभावना नहीं है। तो कहना यह कि नोटबंदी सटीक फैसला साबित नहीं हुआ।

GS World टीम...

सारांश

- बुधवार को जारी हुई भारतीय रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट (2017-18) एक तरह से नोटबंदी की भेंट चढ़ गई। इस रिपोर्ट में पहली बार रिजर्व बैंक ने यह बताया कि 500 और 1000 रुपये के नोट बैन करने के नवंबर 2016 के फैसले के बाद कितने नोट उसके पास वापस आए। इसके बाद पूरी बहस इसी एक पहलू पर सिमट गई, जिससे इस रिपोर्ट की अन्य महत्त्वपूर्ण बातें काफी कुछ अनदेखी रह गईं।
- हालाँकि नोटबंदी के व्यापक असर और रिजर्व बैंक द्वारा नोट गिनने में हुए ऐतिहासिक विलंब को देखते हुए न केवल मीडिया बल्कि राजनीति का भी ध्यान इस पहलू पर केंद्रित होना स्वाभाविक था। 99.3 फीसदी प्रतिबंधित नोट वापस आ जाने को विपक्ष की ओर से इस बात का सबूत बताया गया कि नोटबंदी का फैसला हर तरह से नाकाम रहा।
- बहरहाल, राजनीतिक बयानों से हटकर देखें तो नोटबंदी की इस कवायद ने एक बात साफ कर दी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी का जो हौवा खड़ा किया जाता रहा है, उसकी मौजूदगी नोटों की शक्ल में ना के बराबर ही थी।
- इस रिपोर्ट की एक चिंताजनक बात यह है कि बैंकों के एनपीए का स्तर लाख प्रयासों के बावजूद न सिर्फ अभी बल्कि अगले साल भी नीचे आता नहीं दिख रहा। रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल यह 11.5 फीसदी के मौजूदा स्तर से और ऊपर जा सकता है।
- विश्व व्यापार में जारी संरक्षणवादी प्रवृत्ति बाहरी बाजारों में भारतीय उत्पादों की मांग को प्रभावित करेगी। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल कीमतों के और चढ़ने का अंदेशा है, जबकि डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत अभी और नीचे जाने की आशंका बनी हुई है। इन सबसे एक तरफ व्यापार घाटा बढ़ने का खतरा मँडरा रहा है, दूसरी तरफ आयातित महँगाई की तलवार भी सिर पर लटकी हुई है।
- इन चुनौतियों के बरक्स अच्छी बात यह है कि कृषि उत्पादन लगातार तीसरे साल अच्छा रहने की उम्मीद है। जीडीपी की अनुमानित वृद्धि दर 7.4 फीसदी बताई गई है जो पिछले साल के 6.7 फीसदी से काफी बेहतर है।
- रिजर्व बैंक के अनुसार नोटबंदी के समय देश भर में पाँच सौ और एक हजार के कुल 15 लाख 41 हजार करोड़ रुपये के नोट चलन में थे, लेकिन उनमें से 15 लाख 31 हजार करोड़ रुपये के नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए। इसका मतलब है कि करीब दस हजार करोड़ रुपये ही वापस नहीं आ सके। यह कोई बड़ी रकम नहीं।
- अच्छा होगा कि सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया जाए कि जब दस हजार करोड़ रुपये छोड़कर सारी रकम बैंकों में आ गई तो नोटबंदी को सफल कैसे कहा जा सकता है? चूँकि करीब इतनी ही रकम नए नोट छापने और उन्हें देश के सभी इलाकों में भेजने में खर्च हो गई इसलिए इस पर आश्चर्य नहीं कि नोटबंदी को व्यर्थ की कसरत बताया जा रहा है।
- ध्यान रहे कि नोटबंदी से नकली नोटों के साथ ही आतंकी एवं नक्सली गुटों पर लगाम लगने के दावे भी बहुत पुख्ता नहीं कहे जा सकते। करदाताओं की संख्या में वृद्धि को नोटबंदी की एक सफलता के तौर पर अवश्य रेखांकित किया जा सकता है, लेकिन सभी जानते हैं कि यह इस फैसले का मूल मकसद नहीं था। मूल मकसद तो कालेधन वालों की कमर तोड़ना था।
- नोटबंदी पर विपक्ष के तीखे सवालों के बीच सरकार की ओर से एक बार फिर यह कहा गया कि बैंकों में जमा हो गए सारे धन को सफेद नहीं कहा जा सकता और करीब 18 लाख जमाकर्त्ता संदिग्ध किस्म के पाए गए हैं।
- सरकार ने 8 नवंबर, 2016 को 500 और 1,000 रुपये की तत्कालीन मुद्रा बंद करने की घोषणा की थी जो कुल प्रचलित मुद्रा का 86 फीसदी थी। रातोंरात नोटबंदी के लिए कई दलील दी गई थीं। इनमें नकदी के रूप में भंडारित काले धन का खात्मा, सरकार को प्रचुर

लाभ, देश के भुगतान तंत्र के डिजिटलीकरण और बचत को वित्तीय परिसंपत्तियों में बदलने जैसी बातें शामिल थीं।

- सर्वाधिक आशावादी दृष्टिकोण दो अनुमानों पर आधारित था: पहला अनुमान यह था कि बहुत बड़ी मात्रा में नकदी को कर अधिकारियों से छिपाकर रखा गया है। दूसरा अनुमान यह था कि यह नकदी तंत्र में वापस नहीं आएगी, कम से कम उचित कर दर पर तो बिल्कुल नहीं। अगर नकदी उच्च कर दर पर वापस आती तो सरकार को अच्छा कर प्राप्त होता। अगर ऐसा नहीं होता तो इसे आरबीआई की बैलेंस शीट पर प्रचुर लाभ के रूप में दर्ज किया जाता क्योंकि तब वह इसे सरकार को सौंप सकता था। परंतु 99.3 प्रतिशत बंद नोटों की वापसी ने इस आकलन की धज्जियां उड़ा दीं।
- दुख की बात तो यह है कि नोटबंदी की कवायद ने आम घरों की बचत पर नकारात्मक प्रभाव डाला। आरबीआई ने बीते वर्षों के दौरान आम घरों की बचत के जो आँकड़े जारी किए हैं वे भी काफी कुछ बताते हैं। आम पारिवारिक बचत में छोटे असंगठित क्षेत्र के उद्यमों की बचत भी शामिल होती है। इन्हें भी नोटबंदी ने तगड़ा झटका दिया। हालाँकि आम पारिवारिक बचत 11 फीसदी सकल राष्ट्रीय व्यय योग्य आय के साथ कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर है परंतु इसकी बनावट का विश्लेषण दिलचस्प है।
- इन नोटों की वापसी, उन्हें गिनने में बाइस महीने लगे और नष्ट करने में जो श्रम लगा, उसकी भरपाई करना संभव नहीं है। विडंबना है कि आज नोटबंदी से तीन लाख करोड़ से ज्यादा मुद्रा फिर चलन में है। इसका साइड इफेक्ट यह भी है कि नोटबंदी के बाद दो हजार व पाँच सौ के नकली नोटों के प्रतिशत में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इसके अलावा नये नोटों को छापने का खर्च बीते वर्ष 133 फीसदी बढ़ा।
- सरकार ने नोटबंदी के चार मकसद बताये थे कि इससे आतंकवाद कम होगा, जो वास्तव में नहीं हुआ। दूसरा, काला धन बाहर आयेगा, वो नहीं आया। सरकार का दावा भ्रष्टाचार कम करने का था, मगर दुनिया के भ्रष्ट देशों में भारत का नंबर जहाँ 2016 में 79वाँ था, वहीं 2017 में वह 81वें स्थान पर पहुँच गया। चौथा फायदा सरकार ने डिजिटल ट्रांजेक्शन का बताया था, इसमें सरकार जरूर कामयाब हुई है। वर्ष 2016 के मुकाबले 2017 में डिजिटल पेमेंट की राशि 40 फीसदी तक बढ़ी है।
- हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि नोटबंदी के बाद बैंकों में 99.3 प्रतिशत मुद्रा लौट आई यानी मात्र .7 प्रतिशत धन बैंकों में वापस नहीं पहुंचा। दस से ग्यारह हजार करोड़ रुपये बिना हिसाब-किताब का था, यह पता लगाने में दो साल का समय लगा दिया गया।
- हकीकत तो यह है कि टैक्स रिटर्नस भरने वालों में प्रभावी करदाताओं की संख्या अभी भी 2012-13 के समान ही है। तो इसके कोईमायने नहीं है कि टैक्स रिटर्न्स भरने वाले कितने हैं, महत्त्वपूर्ण यह है कि वास्तविक करदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, या नहीं। उस मामले में हमें कोई उत्साहजनक तस्वीर देखने को नहीं मिलती।
- नोटबंदी से पहले अक्टूबर, 2016 में हमारी अर्थव्यवस्था चीन से टक्कर ले रही थी। लेकिन इस एक फैसले ने अर्थव्यवस्था को धराशायी कर दिया। डेढ़ लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था को दस लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। असंगठित क्षेत्र की तो कमर ही टूट गई है। किसानी को फसल की बुआई तक में परेशानी हुई। इससे कृषि की उत्पादकता पर बुरा प्रभाव पड़ा। असंगठित क्षेत्र ज्यादातर नकदी का इस्तेमाल होता है। चूँकि नोटबंदी ने इस क्षेत्र की नकदी का क्षरण किया तो इसलिए छोटे-मोटे रोजगार ठप पड़ गए। छोटे कारोबारियों को अपने काम-धंधे बंद करने पड़े। कामगारों के पास काम नहीं रहा तो वे अपने घर-गाँव लौट गए।
- फिर यह कहे जाने, कि नोटबंदी से नकदी का प्रवाह कम हुआ है, की पोल यह आँकड़ा खोल देता है कि नवम्बर, 2016 जहाँ 18 लाख करोड़ रुपये का नकदी प्रवाह था, वहीं अब यह 23 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है।

विमुद्रीकरण (Demonetization)

- नोटबंदी का सही अर्थ विमुद्रीकरण है। जब किसी देश की सरकार किसी पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है तो इसे विमुद्रीकरण कहा जाता है। विमुद्रीकरण के बाद उस मुद्रा की कोई कीमत नहीं रह जाती। उससे किसी तरह की खरीद-फरोख्त नहीं की जा सकती। सरकार द्वारा बंद किए गए नोटों को बैंकों में बदलकर उनकी जगह नए नोट लेने के लिए समय-सीमा तय कर देती है।
- जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है तो इसे विमुद्रीकरण (Demonetization) कहते हैं। इसके बाद पुरानी मुद्रा अथवा नोटों की कोई कीमत नहीं रह जाती। हालाँकि सरकार द्वारा पुराने नोटों को बैंकों से बदलने के लिए लोगों को समय दिया जाता है, ताकि वे अमान्य हो चुके अपने पुराने नोटों को बदल सकें।
- सरकार ऐसा कई कारणों से कर सकती है। सरकार पुराने नोटों की जगह नए नोट लाने पर पुराने नोटों का विमुद्रीकरण कर देती है। मुद्रा की जमाखोरी (कालाधन) को खत्म करने के लिए भी बड़े राशि के नोटों का विमुद्रीकरण किया जाता है। आतंकवाद, अपराध और तस्करी जैसे आपराधिक कामों में भी बड़े पैमाने पर नगद लेन-देन होता है।
- इन कामों में लिप्त लोग कई बार नगद राशि अपने पास जमा रखते हैं। बाजार में कई बार नकली नोट भी प्रचलन में आ जाते हैं। सरकार नकली नोटों से छुटकारा पाने के लिए पुराने नोट बदल देती है। जालसाजी से बचने के लिए नई तकनीकी से तैयार किए गए ज्यादा सुरक्षित नोट लाने पर भी सरकार पुराने नोटों का विमुद्रीकरण कर देती है। टैक्स चोरी के लिए किए जाने वाले नगद लेन-देन को हतोत्साहित करने के लिए भी सरकारें कई बार विमुद्रीकरण का रास्ता अपनाती हैं।
- मुद्रा की जमाखोरी (कालाधन) को खत्म करने, आतंकवाद, अपराध और तस्करी जैसे आपराधिक कामों को रोकने, बाजार में नकली नोटों के प्रचलन को बंद करने, जालसाजी से बचने और टैक्स चोरी के लिए किए जाने वाले नगद लेन-देन को हतोत्साहित करने के लिए भी सरकारें कई बार विमुद्रीकरण का रास्ता अपनाती हैं।
- भारत के 500 और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण, जिसे मीडिया में छोटे रूप में नोटबंदी कहा गया, की घोषणा 8 नवम्बर 2016 को रात आठ बजे (आईएसटी) भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अचानक राष्ट्र को किये गए संबोधन के द्वारा की गयी। इस घोषणा में 8 नवम्बर की आधी रात से देश में 500 और 1000 रुपये के नोटों को खत्म करने का ऐलान किया गया। इसका उद्देश्य केवल काले धन पर नियंत्रण ही नहीं बल्कि जाली नोटों से छुटकारा पाना भी था।

- इससे पहले, इसी तरह के उपायों को भारत की स्वतंत्रता के बाद लागू किया गया था। जनवरी 1946 में, 1000 और 10,000 रुपए के नोटों को वापस ले लिया गया था और 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नए नोट 1954 में पुनः शुरू किये गए थे। 16 जनवरी 1978 को जनता पार्टी की गठबंधन सरकार ने फिर से 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण किया था ताकि जालसाजी और काले धन पर अंकुश लगाया जा सके.
- अब रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के दौरान बैंकिंग सिस्टम में वापस लौटे नोटों के बारे में पूरी जानकारी सामने रख दी है। इसके मुताबिक पाँच सौ और हजार के 99.3 फीसदी नोट बैंकों में लौट आए हैं।
- आरबीआई के मुताबिक नोटबंदी के समय देश भर में 500 और 1000 रुपए के कुल 15 लाख 41 हजार करोड़ रुपए के नोट चलन में थे। इनमें 15 लाख 31 हजार करोड़ के नोट अब सिस्टम में वापस में आ गए हैं, यानी यही कोई 10 हजार करोड़ रुपए के नोट सिस्टम में वापस नहीं आ पाए.
- नोटबंदी लगाए जाने के दो सप्ताह बाद तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी का बचाव करते हुए कहा था, ष्सरकार ने ये कदम उत्तर-पूर्व और कश्मीर में भारत के खलिाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने में इस्तेमाल हो रहे चार लाख से पाँच लाख करोड़ रुपए तक को चलन से बाहर करने के लिए उठाया है।
- नौ दिसंबर, 2016 को रिजर्व बैंक के मुताबिक आम लोगों के पास 7.8 लाख करोड़ रुपए थे, जो जून, 2018 तक बढ़कर 18.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गए हैं। मोटे तौर पर आम लोगों के पास नकदी नोटबंदी के समय से दोगुनी हो चुकी है। इतना ही नहीं रिजर्व बैंक के आँकड़ों से आम लोगों के पास पैसा राष्ट्रीय आमदनी का 2.8 फीसदी तक बढ़ा है, जो बीते छह साल में सबसे ज्यादा आँका जा रहा है।
- रिजर्व बैंक के आँकड़े जारी करने से पहले ही वित्त मामलों की पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी की उस रिपोर्ट को भी भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी के अंदर अपने बहुमत का इस्तेमाल करते हुए सार्वजनिक नहीं होने दिया है, जिसमें नोटबंदी पर सवाल उठाए गए हैं। 31 अगस्त को कमेटी के कार्यकाल का आखिरी दिन है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि नोटबंदी के चलते देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ एक फीसदी कम हुई है।
- नोटबंदी से फायदे से उलट इसे लागू करने में रिजर्व बैंक को हजारों करोड़ का नुकसान अलग उठाना पड़ा। नए नोटों की प्रिंटिंग के लिए रिजर्व बैंक को 7,965 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। इसके अलावा नकदी की किल्लत नहीं हो, इसके लिए ज्यादा नोट बाजार में जारी करने के चलते 17,426 करोड़ रुपए का ब्याज भी चुकाना पड़ा. इसके अलावा देश भर के एटीएम को नए नोटों के मुताबिक कैलिब्रेट करने में भी करोड़ों रुपए का खर्च सिस्टम को उठाना पड़ा है।
- ऐसे में नोटबंदी को लेकर सरकार केवल एक फायदा गिना सकती है, 2017-2018 के इकॉनामिक सर्वे के मुताबिक नोटबंदी के बाद देश भर में टैक्स भरने वाले लोगों की संख्या में 18 लाख की बढ़ोत्तरी हुई है।

PT / Mains - प्रश्न

संभावित प्रश्न

1. कितने प्रतिशत नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं?

(a) 99.1%

(b) 99.3%

(c) 99.2%

(d) 49.4%

(उत्तर-B)

2. सरकार ने नोटबंदी कब लागू की?

(a) 8 नवंबर, 2016

(b) 7 नवंबर, 2016

(c) 9 नवंबर, 2016

(d) 10 नवंबर, 2016

(उत्तर-A)

3. 2017-18 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक नोटबंदी के बाद देश भर में टैक्स भरने वाले लोगों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई?

(a) 13 लाख

(b) 15 लाख

(c) 18 लाख

(d) 20 लाख

(उत्तर-C)

4. विमुद्रीकरण किसे कहते हैं?

(a) पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देना

(b) मुद्रा को कुछ समय के लिए बंद कर देना

(c) मुद्रा की बाजार वेल्यू में गिरावट

(d) वस्तु विनिमय प्रणाली लागू करना

(उत्तर-A)

5. वर्ष 2016 में हुए विमुद्रीकरण पर प्रस्तुत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हालिया रिपोर्ट के संदर्भ में इसके औचित्य की समीक्षा करें।

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न

1. भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्रक उधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा उधार शामिल है?

(a) कृषि क्षेत्र

(b) सूक्ष्म और छोटे उद्योग

(c) कमजोर क्षेत्र

(d) उपर्युक्त सभी

(IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2013, उत्तर-D)

2. 'सीमांत स्थायी सुविधा दर' एवं 'कुल माँग और समय देनदारियाँ' कभी-कभी समाचारों में आते हैं, का संबंध है-

(a) बैंकिंग क्रियाओं से

(b) संचार नेटवर्किंग से

(c) सैन्य सामरिक से

(d) कृषि उत्पादों के माँग एवं आपूर्ति से

(IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2014, उत्तर-A)

3. यदि मुद्रा की आपूर्ति उतनी ही रखी जाए, जब मुद्रा की माँग में बढ़त हो तो क्या होगा?

(a) मूल्यों के स्तर में गिरावट

(b) ब्याज-दरों में बढ़त

(c) ब्याज-दरों में कमी

(d) आय एवं रोजगार के स्तर में बढ़त

(IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2013, उत्तर-B)

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. मुद्रास्फीति से उधारकर्त्ताओं को फायदा होता है।
2. मुद्रास्फीति से बांडधारकों को फायदा होता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

(IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2013, उत्तर-A)

5. अवैध धन स्थांतरण देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के लिए एक गंभीर सुरक्षा जोखिम होता है। भारत के लिए इसका क्या महत्त्व है और इस खतरे से बचने के लिए कौन-से कदम उठाए जाने चाहिए?

(IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-3, वर्ष-2013)

GS World
Committed To Excellence

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-3 (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

हर गरीब, किसान और उपेक्षित व्यक्ति तक बैंकों की सुविधा पहुँचाने के लिए सरकार एक नया बैंक-इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आइपीपीबी) शुरू करने जा रही है। यह अंततः सभी भारतीयों को एक साझा वित्तीय, आर्थिक और डिजिटल धरातल पर ले आएगी। बैंकिंग सेवाओं की कार्यप्रणाली को जो लोग जटिल समझकर दूर रहते थे, आइपीपीबी उन लोगों तक भी बैंकिंग सेवा पहुँचाने का एक प्रयास है। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार-पत्रों 'दैनिक जागरण' तथा 'जनसत्ता' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

मोदी सरकार की सामाजिक क्रांति का आगाज, हर घर तक पहुँचेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (दैनिक जागरण)

भारत जैसे विशाल देश में किसी केंद्रीय सत्ता के 50 माह का कालखंड बहुत छोटा माना जाएगा, लेकिन जब चुनौती बड़ी हो और दाँव पर देश का वर्तमान एवं भविष्य, दोनों ही हों तो सरकार को कम समय में ही ईमानदारी के साथ साहसिक निर्णय लेने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं एक ऐसी ही सरकार का अंग हूँ। हर गरीब, किसान और उपेक्षित व्यक्ति तक बैंकों की सुविधा पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार एक नया बैंक-इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आइपीपीबी) शुरू करने जा रही है। इस बैंक के शुरू होने के साथ ही डाकिया बैंक की सुविधा हर घर तक पहुंचा देगा। बैंकिंग सुविधा की इस होम डिलिवरी के जरिये सरकार समाज में हाशिये पर खड़े आखिरी व्यक्ति को वित्तीय मुख्यधारा में शामिल करने में सफल होगी।

संचार मंत्रालय पिछली सरकार के एक दशक के कार्यकाल के अविश्वास, अनिर्णय, आरोपों के दौर से आगे निकल चुका है। जनता परिणामोन्मुखी सरकार चाहती थी और हमने ऐसा ही करके दिखाया है। सभी भारतीय नागरिकों को जन-धन खाते से जोड़ने के सफल कार्यक्रम केबाद राजग सरकार अब बैंकिंग सेवाओं को जनता के घर तक पहुँचाने जा रही है। देश के कोने-कोने में मौजूद डाककर्मी इस कार्य को अंजाम देंगे। डाकिया सरकार का वह प्रतिनिधि होता है जो जनता के सुख-दुःख से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। उसकी पहुँच हर नागरिक तक होती है, भले ही वह कैसी भी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का हो या कैसे ही दुर्गम स्थान पर रहता हो।

जन-धन योजना, यूनिक पहचान पत्र आधार, मोबाइल और पोस्टल पेमेंट्स बैंक यानी जे यू एम और पी को मिला दें तो जंप बनता है। इस जंप से आर्थिक मोर्चे पर वास्तव में एक ऐसी उछाल आने वाली है जिससे हर नागरिक बैंकिंग सेवाओं से जुड़ जाएगा। यह एक ऐसी सामाजिक क्रांति का आगाज है, जो अंततः सभी भारतीयों को एक साझा वित्तीय, आर्थिक और डिजिटल धरातल पर ले आएगी। बैंकिंग सेवाओं की कार्यप्रणाली को जो लोग जटिल समझकर दूर रहते थे, आइपीपीबी उन लोगों तक भी बैंकिंग सेवा पहुँचाने का एक प्रबल प्रयास है। यह एक सस्ता, सुरक्षित और सरल डिजिटल भुगतान ढाँचा भी प्रदान करेगा, जिससे प्रत्येक भारतीय डिजिटल मेनस्ट्रीम का हिस्सा बन सके।

बैंक वित्तीय सेवा कार्यप्रणाली को सुविधाजनक और सर्वसुलभ बनाने के लिए डाककर्मी की प्रत्यक्ष सहायता भी उपलब्ध कराएगा। इसकी पूरी कार्यप्रणाली हाशिये पर खड़े आखिरी व्यक्ति तक वित्तीय समावेशन को

सचल वित्त (जनसत्ता)

बैंक सेवाओं तक आम लोगों की पहुँच सुनिश्चित करने की मंशा से केंद्र ने डाकघरों को भी बैंकों की तरह काम करने की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की थी। अब वह सेवा शुरू होने जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस सेवा के लिए एक हजार चार सौ पैंतीस करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। अब अगले महीने से डाकघर बैंकों की तरह काम करना शुरू कर देंगे। उनमें कर्ज के लेन-देन के अलावा बैंकों से संबंधित लगभग सभी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। एक लाख रुपए तक का लेन-देन संभव हो सकेगा। इस योजना की शुरुआत में देश भर में साढ़े छह सौ शाखाएँ और सवा तीन हजार ऐसे केंद्र शुरू हो जाएँगे, जहाँ से लोग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। आगे चल कर देश भर में कुल डाकघरों की संख्या बढ़ कर दोगुनी हो जाएगी। अब डाक कर्मचारी सचल बैंककर्मी का भी दायित्व निभा सकेंगे। अभी तक डाकघरों की मार्फत लोग आमतौर पर धनादेश यानी मनीआर्डर वगैरह भेज अथवा प्राप्त या छोटी राशि जमा कर पा रहे थे, पर अब उनमें बैंकों की तरह खाते खुलवा कर न सिर्फ बचत संबंधी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे, बल्कि सरकारी योजनाओं के लाभ भी प्राप्त करेंगे। यह निस्संदेह दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में रहने और छोटी आमदनी वाले लोगों के लिए लाभकारी सुविधा होगी।

यों डाकघरों का काम मुख्य रूप से चिट्ठियाँ और छोटी राशि वाले मनीआर्डर वगैरह लोगों तक पहुंचाना रहा है। पर अब चिट्ठियों आदि के लिए अनेक तरह की तकनीकी और निजी सेवाएँ शुरू हो जाने से इनका चलन कम हो गया है। इसी तरह इंटरनेट बैंकिंग और धन हस्तांतरण की त्वरित सुविधाएँ आने से मनीआर्डर सेवा का भी कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं। जब तार सेवाओं का चलन घट गया था, तो उसे बंद करके उसके कर्मचारियों को डाक सेवा से जोड़ दिया गया। उसी तरह डाक विभाग की जो सेवाएँ पुरानी पड़ गई हैं, उनके स्थान पर नई सेवा शुरू करने से कर्मचारियों का सदुपयोग भी हो सकेगा। इसके अलावा जब इस सेवा में विस्तार होगा, तो बहुत सारे नए लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। कहा जा सकता है कि जब ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों के जरिये हर गांव तक बैंकिंग सेवाएँ पहुँचाने की व्यवस्था पहले से है तो इसमें एक नई व्यवस्था शुरू करने और उस पर अतिरिक्त धन खर्च करने की क्या तुक थी! पर डाकघरों की पहुंच, उनकी विश्वसनीयता और कार्यप्रणाली बैंकों की तुलना में बिल्कुल भिन्न है। डाकघर लोगों तक खुद पहुंचता है, जबकि बैंकों तक लोगों को जाना पड़ता है।

डाकघरों की पहुँच देश के लगभग हर व्यक्ति तक है, चाहे वह पहाड़ की चोटी पर बसा अकेला घर ही क्यों न हो, जबकि बैंकों की सेवाएँ

पहुँचाने में आने वाली सभी बाधाओं से रहित है। पोस्ट ऑफिस के वर्तमान खाताधारकों को भी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सुविधा स्वत: मिल जाएगी। इस बैंक से ऐसे वित्तीय परिवेश के विकास में सहायता मिलेगी जो डिजिटल होगा। इस बैंक की कार्यप्रणाली ग्राहकोन्मुखी और ग्राहक सेवा के अनुभव को अच्छा रखने पर केंद्रित होगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक वर्तमान पोस्टल व्यवस्था और नई तकनीक का सर्वाधिक इस्तेमाल करके बैंकिंग सुविधा की पहुँच को कई गुना बढ़ा देगा।

अभी देश में जो बैंकिंग ढाँचा है उसमें बैंकिंग शाखाओं का एक तिहाई और एटीएम बूथों का लगभग छठा हिस्सा ही ग्रामीण भारत में है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कार्यशील होने के बाद यह परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। इसके 1.50 लाख से अधिक सुविधा केंद्रों में से 90 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण भारत में होंगे। इसके 2.50 लाख से अधिक एजेंट बैंकिंग सुविधा को हर घर तक पहुँचाएंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक विश्व का सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क होगा जो विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देगा।

डाकिया जब बैंकर की भूमिका निभाएगा तो वह बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और अल्पबैंकिंग सुविधाओं वाले लाखों भारतीयों को वित्तीय सेवा मुहैया कराएगा। आइपीपीबी का समग्र उद्देश्य आम जनता के लिए सबसे अधिक पहुँच वाला, किफायती और भरोसेमंद बैंक बनना है। यह सरकार के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करेगा। यह बैंक विविध प्रकार की सेवाएँ प्रदान करेगा जिनमें बचत एवं चालू खाते, धन अंतरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, बिल एवं जनोपयोगी भुगतान और उद्यम एवं व्यापार संबंधी भुगतान शामिल है।

आइपीपीबी द्वारा तीसरे पक्ष की तरफ से भी कई वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। इनमें छोटे कर्ज, बीमा, निवेश और डाकघर बचत खाता शामिल हैं। इसके साथ ही डाकिये के पास पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीन होगी जिससे ग्राहक मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज, बिजली, पानी एवं गैस आदि के बिल सहित बीमा आदि की किश्तों का भी भुगतान कर सकेंगे। आइपीपीबी के लाभों को जनता तक पहुँचाने के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। लोगों को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

हासिल करने के लिए लोगों को घर से दूर चल कर जाना होता है। फिर बैंकों में खाते खुलवाने और उनकी कार्यप्रणाली डाक सेवाओं की तुलना में अधिक तकनीकी है। डाकघर उसकी अपेक्षा आम लोगों की सुविधाओं के बहुत करीब है। डाकघर भी अब संचार तकनीक की आधुनिक सेवाओं से जुड़ चुके हैं, ऐसे में पैसे के लेन-देन में उन्हें मुश्किल नहीं आएगी। खासकर गरीब और अनपढ़ लोग बैंक कर्मियों से संवाद करने की अपेक्षा डाकिये से संवाद करने में ज्यादा सहज महसूस करते हैं, इसलिए वे अपने डाक बैंक खाते के जरिये सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठाने में सहज महसूस करेंगे।

आइपीपीबी के क्रियाशील हो जाने के बाद मनरेगा में दी जाने वाली मजदूरी, छात्रवृत्तियाँ, सामाजिक कल्याण योजनाओं और अन्य सरकारी सब्सिडी भी हर ग्राहक तक डाकिये के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकेगी। उद्यमियों और व्यापारियों के लिए भी इस बैंक की सेवाएँ उपलब्ध होंगी जिनमें डाक-उत्पाद, ई-कॉमर्स व्यावसायिक उत्पादों की कैश ऑन डिलिवरी का डिजिटल पेमेंट भी संभव हो सकेगा। छोटे दुकानदार, लघु उद्यमियों और असंगठित क्षेत्र के व्यापारी भी इस बैंक से लाभान्वित होंगे। आइपीपीबी के लॉन्च के साथ डाकघरों की 650 शाखाएँ और 3,250 सेवा केंद्रों पर इसकी सेवा उपलब्ध होगी।

31 दिसंबर, 2018 तक यह बैंक पूरी तरह से डाक विभाग के नेटवर्क का इस्तेमाल करने लगेगा। जिसके दायरे में देश के कोने-कोने में स्थित 1.55 लाख सेवा केंद्र (डाक घर) और तीन लाख सेअधिक पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक शामिल हैं। इसके चलते देश में ग्रामीण बैंक शाखाओं की संख्या 49,000 से बढ़कर 1,30,000 हो जाएगी। नई दिल्ली में 1 सितंबर को होने वाले राष्ट्रीय लॉन्च कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जब आइपीपीबी का शुभारंभ करेंगे तब वह वित्तीय समावेशन एवं डिजिटलीकरण की दिशा में भारत के निरंतर बढ़ते कदम का 'मील का पत्थर' होगा। इससे निश्चित रूप से हमारे सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को बल मिलेगा और हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन को वास्तविकता में बदलने की दिशा में गतिशील हो पाएंगे।

GS World टीम...

सारांश

- हर गरीब, किसान और उपेक्षित व्यक्ति तक बैंकों की सुविधा पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार एक नया बैंक इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आइपीपीबी) शुरू करने जा रही है। इस बैंक के शुरू होने के साथ ही डाकिया बैंक की सुविधा हर घर तक पहुँचा देगा। बैंकिंग सुविधा की इस होम डिलिवरी के जरिये सरकार समाज में हाशिये पर खड़े आखिरी व्यक्ति को वित्तीय मुख्यधारा में शामिल करने में सफल होगी।
- देश के कोने-कोने में मौजूद डाककर्मी इस कार्य को अंजाम देंगे। डाकिया सरकार का वह प्रतिनिधि होता है जो जनता के सुख-दु:ख से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। उसकी पहुँच हर नागरिक तक होती है, भले ही वह कैसी भी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का हो या कैसे ही दुर्गम स्थान पर रहता हो।
- जन-धन योजना, यूनिक पहचान पत्र आधार, मोबाइल और पोस्टल पेमेंट्स बैंक यानी जे.यू.एम. और पी. को मिला दें तो जंप बनता है। इस जंप से आर्थिक मोर्चे पर वास्तव में एक ऐसी उछाल आने वाली है जिससे हर नागरिक बैंकिंग सेवाओं से जुड़ जाएगा।
- यह एक ऐसी सामाजिक क्रांति का आगाज है, जो अंतत: सभी भारतीयों को एक साझा वित्तीय, आर्थिक और डिजिटल धरातल पर ले आएगी। बैंकिंग सेवाओं की कार्यप्रणाली को जो लोग जटिल समझकर दूर रहते थे, आइपीपीबी उन लोगों तक भी बैंकिंग सेवा पहुँचाने का एक प्रबल प्रयास है। यह एक सस्ता, सुरक्षित और सरल डिजिटल भुगतान ढाँचा भी प्रदान करेगा, जिससे प्रत्येक भारतीय डिजिटल मेनस्ट्रीम का हिस्सा बन सके।
- पोस्ट ऑफिस के वर्तमान खाताधारकों को भी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सुविधा स्वत: मिल जाएगी। इस बैंक से ऐसे वित्तीय परिवेश के विकास में सहायता मिलेगी जो डिजिटल होगा। इस बैंक की कार्यप्रणाली ग्राहकोन्मुखी और ग्राहक सेवा के अनुभव को अच्छा रखने पर केंद्रित होगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक वर्तमान पोस्टल व्यवस्था और नई तकनीक का सर्वाधिक इस्तेमाल करके बैंकिंग सुविधा की पहुँच को कई गुना बढ़ा देगा।
- अभी देश में जो बैंकिंग ढाँचा है उसमें बैंकिंग शाखाओं का एक तिहाई और एटीएम बूथों का लगभग छठा हिस्सा ही ग्रामीण भारत में है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कार्यशील होने के बाद यह परिदृश्य

पूरी तरह बदल जाएगा। इसके 1.50 लाख से अधिक सुविधा केंद्रों में से 90 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण भारत में होंगे। इसके 2.50 लाख से अधिक एजेंट बैंकिंग सुविधा को हर घर तक पहुँचाएंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक विश्व का सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क होगा जो विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देगा।

- डाकिया जब बैंकर की भूमिका निभाएगा तो वह बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और अल्पबैंकिंग सुविधाओं वाले लाखों भारतीयों को वित्तीय सेवा मुहैया कराएगा। आइपीपीबी का समग्र उद्देश्य आम जनता के लिए सबसे अधिक पहुँच वाला, किफायती और भरोसेमंद बैंक बनना है। यह सरकार के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करेगा। यह बैंक विविध प्रकार की सेवाएँ प्रदान करेगा, जिनमें बचत एवं चालू खाते, धन अंतरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, बिल एवं जनोपयोगी भुगतान और उद्यम एवं व्यापार संबंधी भुगतान शामिल हैं।
- आइपीपीबी द्वारा तीसरे पक्ष की तरफ से भी कई वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। इनमें छोटे कर्ज, बीमा, निवेश और डाकघर बचत खाता शामिल हैं। इसके साथ ही डाकिये के पास पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीन होगी, जिससे ग्राहक मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज, बिजली, पानी एवं गैस आदि के बिल सहित बीमा आदि की किश्तों का भी भुगतान कर सकेंगे। आइपीपीबी के लाभों को जनता तक पहुँचाने के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। लोगों को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- आइपीपीबी के क्रियाशील हो जाने के बाद मनरेगा में दी जाने वाली मजदूरी, छात्रवृत्तियाँ, सामाजिक कल्याण योजनाओं और अन्य सरकारी सब्सिडी भी हर ग्राहक तक डाकिये के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकेगी। उद्यमियों और व्यापारियों के लिए भी इस बैंक की सेवाएँ उपलब्ध होंगी जिनमें डाक-उत्पाद, ई-कॉमर्स व्यावसायिक उत्पादों की कैश ऑन डिलिवरी का डिजिटल पेमेंट भी संभव हो सकेगा। छोटे दुकानदार, लघु उद्यमियों और असंगठित क्षेत्र के व्यापारी भी इस बैंक से लाभान्वित होंगे। आइपीपीबी के लॉन्च के साथ डाकघरों की 650 शाखाएँ और 3,250 सेवा केंद्रों पर इसकी सेवा उपलब्ध होगी।
- 31 दिसंबर, 2018 तक यह बैंक पूरी तरह से डाक विभाग के नेटवर्क का इस्तेमाल करने लगेगा। जिसके दायरे में देश के कोने-कोने में स्थित 1.55 लाख सेवा केंद्र (डाक घर) और तीन लाख सेअधिक पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक शामिल हैं। इसके चलते देश में ग्रामीण बैंक शाखाओं की संख्या 49,000 से बढ़कर 1,30,000 हो जाएगी। नई दिल्ली में 1 सितंबर को होने वाले राष्ट्रीय लॉन्च कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जब आइपीपीबी का शुभारंभ करेंगे तब वह वित्तीय समावेशन एवं डिजिटलीकरण की दिशा में भारत के निरंतर बढ़ते कदम का 'मील का पत्थर' होगा।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस सेवा के लिए एक हजार चार सौ पैंतीस करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। अब अगले महीने से डाकघर बैंकों की तरह काम करना शुरू कर देंगे। उनमें कर्ज के लेन-देन के अलावा बैंकों से संबंधित लगभग सभी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। एक लाख रुपए तक का लेन-देन संभव हो सकेगा। इस योजना की शुरुआत में देश भर में साढ़े छह सौ शाखाएँ और सवा तीन हजार ऐसे केंद्र शुरू हो जाएँगे, जहाँ से लोग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। आगे चल कर देश भर में कुल डाकघरों की संख्या बढ़ कर दो गुनी हो जाएगी। अब डाक कर्मचारी सचल बैंककर्मी का भी दायित्व निभा सकेंगे।
- जब तार सेवाओं का चलन घट गया था, तो उसे बंद करके उसके कर्मचारियों को डाक सेवा से जोड़ दिया गया। उसी तरह डाक विभाग की जो सेवाएँ पुरानी पड़ गई हैं, उनके स्थान पर नई सेवा शुरू करने से कर्मचारियों का सदुपयोग भी हो सकेगा। इसके अलावा जब इस सेवा में विस्तार होगा, तो बहुत सारे नए लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक

- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक डाक विभाग के तहत 17 अगस्त, 2016 को खोला गया है। इसका 100 फीसदी मालिकाना हक भारत सरकार के पास है। IPPB ने 30 जनवरी, 2017 को 2 पायलट ब्रांच खोलकर अपने ऑपरेशन की शुरुआत की है।
- देश के प्रत्येक जिले में इस बैंक की कम से कम एक शाखा होगी। IPPB में मुख्य खासियत यह है कि इसमें आप तीन तरह के सेविंग्स अकाउंट्स जीरो बैलेंस पर खोल सकेंगे। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के इस बैंक में अकाउंट खुलवाने वाले कस्टमर को इंश्योरेंस समेत अन्य सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। IPPB के तहत पोस्टमैन ग्रामीण इलाकों में लोगों के घर तक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज मुहैया कराएंगे।
- पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन और उसके बाद घोषित सात दिन के राष्ट्रीय शोक के कारण इस बैंक की शुरुआत को आगे के लिए टाल दिया गया था। इससे पहले बैंक का उद्घाटन 21 अगस्त को होना था।
- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आपको तीन तरह के सेविंग अकाउंट खोलने की सुविधा देगा। रेगुलर सेविंग अकाउंट, डिजिटल सेविंग अकाउंट और बेसिक सेविंग अकाउंट। ये तीनों अकाउंट जीरो बैलेंस पर खोले जा सकते हैं। खाता खुलने के बाद आप पैसा जमा व निकासी कर सकते हैं। इन सभी के लिए सालाना ब्याज दर 4 फीसदी रहेगी।
- आइपीपीबी के तहत देश के 1.55 लाख डाकघरों को ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ देने के लिए तैयार किया जाएगा। हर जिले में आइपीपीबी की कम से कम एक शाखा होगी। सरकार की देश-भर में आईपीपीबी की 650 शाखाएँ लॉन्च करने की योजना है।
- डाकघरों में 3,250 एक्सेस पॉइंट होंगे और साथ ही 11,000 डाकिये होंगे। ये ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में घर के दरवाजे पर बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराएंगे। IPPB को 17 करोड़ डाक बचत बैंक खाते को अपने खाते से जोड़ने की अनुमति है। इसके जरिये ग्राहकों की सुविधा बढ़ जाएगी और वो कोर बैंकिंग से जुड़ जाएँगे। ग्रामीण इलाकों में तकरीबन 1.30 लाख डाकघरों के जरिये आइपीपीबी की सेवाएँ पहुँचेंगी। अभी ग्रामीण इलाकों में केवल 49 हजार बैंक शाखाएँ हैं।
- एक लाख रुपये से अधिक जमा स्वीकार करने के लिए आइपीपीबी को तकरीबन 17 करोड़ डाकघर बचत बैंक (पीओएसबी) खातों से संबद्ध होने की अनुमति मिली है। यह कार्य चरणों में होगा। इससे जब कभी भी जमा रकम एक लाख रुपये को पार करेगी, उसे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक खातों में हस्तांतरित किया जा सकेगा।
- आइपीपीबी तीसरी एंटिटी है जिसे पेमेंट बैंक के लिए मंजूरी मिली है। इससे पहले एयरटेल और पेटीएम को भी अनुमति मिल चुकी है।

पेमेंट बैंकों का संचालन सामान्य बैंकों के मुकाबले थोड़ा अलग ढंग से होता है। ये केवल जमा तथा विदेशों से भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा स्वीकार कर सकते हैं। इसके अलावा इन्हें इंटरनेट बैंकिंग तथा कुछ अन्य विशिष्ट सेवाएँ प्रदान करने का अधिकार होता है।

- आईपीपीबी की स्थापना केंद्र सरकार के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को तेजी से पाने के लिए की गई है। इसकी कल्पना आम आदमी के लिए एक सस्ते, भरोसेमंद और आसान पहुँच वाले बैंक के तौर पर की गई है। इस भुगतान बैंक में भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी है। इस डाक विभाग के व्यापक नेटवर्क और तीन लाख से अधिक डाकियों और ग्रामीण डाकसेवकों का लाभ मिलेगा। देश के 1.55 लाख डाकघरों को 31 दिसंबर, 2018 तक आईपीपीबी प्रणाली से जोड़ लिया जाएगा। आईआईपीबी अपने खाताधारकों को भुगतान बैंक के साथ-साथ चालू खाता, धन हस्तांतरण, प्रत्यक्ष धन अंतरण, बिलों के भुगतान इत्यादि की सेवाएँ भी उपलब्ध कराएगा।
- देश भर में इसके एटीएम और माइक्रो एटीएम भी काम करेंगे। साथ ही मोबाइल बैंकिंग एप, एसएमएस और आईवीआर जैसी सुविधाओं के माध्यम से भी बैंकिंग सेवाएँ लोगों तक पहुँचाएगा। इस हफ्ते की शुरुआत में मंत्रिमंडल ने आईआईपीबी के व्यय को बढ़ाकर 1,435 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दे दी थी। ताकि आईआईपीबी इस क्षेत्र में पहले से मौजूद पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक इत्यादि से प्रतिस्पर्धा कर सके।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के इन डाकघरों के 11,000 के करीब पोस्टमैन सीधे दरवाजे पर बैंकिंग सेवाएँ देने के लिये उपलब्ध होंगे। आईपीपीबी को 17 करोड़ पोस्टल सेविंग्स बैंक खातों को अपने साथ जोड़ने की अनुमति दी गई है। आईपीपीबी के काम शुरू करने के बाद ग्रामीण इलाकों में लोगों को डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की सुविधा मिलने लगेगी। वह किसी भी बैंक खाते में धन हस्तांतरित कर सकेंगे। यह काम वह मोबाइल एप अथवा डाकघर में जाकर कर सकेंगे।

PT / Mains - प्रश्न

संभावित प्रश्न

1. पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   1. इसके 1.50 लाख से अधिक सुविधा केंद्रो में से 90 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण भारत में होंगे।
   2. इसमें 2 लाख से अधिक एजेंट बैंकिंग सुविधा को हर घर तक पहुँचाएंगे।

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

   (उत्तर-A)

2. पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा तीसरे पक्ष की तरफ से भी कई वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएगी। निम्नलिखित में से कौन-सी सेवाएँ इनमें शामिल हैं?
   1. छोटे कर्ज
   2. बीमा
   3. निवेश
   4. डाकघर बचत खाता

   कूट-
   (a) 1, 2, 3 और 4
   (b) 1, 2 और 3
   (c) 2, 3 और 4
   (d) 2 और 4

   (उत्तर-A)

3 किस तिथि तक बैंक पूरी तरह से डाक विभाग के नेटवर्क का इस्तेमाल करने लगेगा?
   (a) 31 दिसंबर, 2018
   (b) 1 अप्रैल, 2019
   (c) 1 फरवरी, 2019
   (d) 30 नवंबर, 2018

   (उत्तर-A)

4. पोस्ट पेमेंट बैंकों में सालाना ब्याज दर कितनी रखी गई है?
   (a) 8 फीसदी (b) 7 फीसदी
   (c) 4 फीसदी (d) 2 फीसदी

   (उत्तर-A)

5. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आइपीपीबी) की शुरुआत हो गई है। इसके माध्यम से भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में होने वाले संभावित प्रभावों पर चर्चा करें।

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

   भारत में व्यावसायिक बैंकों के कार्यों में शामिल हैं-
   1. ग्राहकों के पक्ष में शेयरों और सिक्योरिटीज की खरीद-फरोख्त
   2. वसीयत के निष्पादक एवं ट्रस्टी के रूप में कार्य करना।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2010, उत्तर-B)

2. भारत में 'पेमेंट्स बैंकों' की स्थापना वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए की जा रही है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   1. मोबाइल टेलीफोन कंपनी एवं सुपरमार्केट चेन, जिनका नियंत्रण एवं स्वामित्व नागरिकों द्वारा होता है, पेमेंट्स बैंकों के प्रमोटर बनने योग्य हैं।
   2. पेमेंट्स बैंक क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं।
   3. पेमेंट्स बैंक उधार क्रियाओं को शुरू नहीं कर सकते।

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने-
   (a) 1 और 2
   (b) 1 और 3
   (c) केवल 2
   (d) 1, 2 और 3

   (IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2016, उत्तर-B)

3. प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.) बैंकरहितों को संस्थागत वित्त में लाने के लिए आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं कि इससे भारतीय समाज के गरीब तबके के लोगों का वित्तीय समावेश होगा? अपने मत की पुष्टि के लिए तर्क प्रस्तुत कीजिए।

   (IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-3, वर्ष-2016)

GS World
Committed To Excellence

अंतरिक्ष में जाने का भारतीय सपना

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-3 (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) से संबंधित है।

2022 में भारत अंतरिक्ष में मानव मिशन भेज कर ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश हो जाएगा। 'गगनयान' नाम के इसके अभियान को कामयाब बनाने के लिए भारत जरूरी प्रौद्योगिकी विकसित कर चुका है। भारत जो मिशन भेजेगा, वह पूरी तरह स्वदेशी होगा। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार-पत्रों 'हिन्दुस्तान' तथा 'जनसत्ता' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

दूर आसमान तक पहुँचते कदम (हिन्दुस्तान)

अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ, तो 2022 में भारत उन देशों में शुमार हो जाएगा, जो अंतरिक्ष में इंसान को भेजने में सक्षम हैं। अभी इस सूची में मात्र तीन देश हैं। रूस ने यह उपलब्धि सबसे पहले हासिल की थी। उसने 1961 में ही यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रच दिया था। फिर अमेरिका ने यह कारनामा दोहराया और तीसरी उपलब्धि चीन के खाते में आई है। अंतरिक्ष का मानव मिशन कितना दुरुह होता है, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि चीन 2003 में इसमें सफल हुआ था, और पिछले डेढ़ दशक में अन्य कोई अन्य स्पेस एजेंसी ऐसा नहीं कर सकी है, जबकि दुनिया में तकनीक लगातार अत्याधुनिक होती जा रही है। जाहिर है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) यदि इस अभियान में कामयाब होता है, तो दुनिया भर में उसका डंका बजेगा। इस मिशन का नाम गगनयान रखा गया है।

इसरो उसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसकी एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के अपने संबोधन में दिखाई थी। उनका कहना था कि 2022 में जब देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे तो उससे पहले ही भारत माँ का कोई लाल, चाहे बेटा हो या बेटी, अंतरिक्ष में पहुँचे। इसरो की अब तक की उपलब्धियों को देखते हुए अंतरिक्ष में मानव को भेजना भले ही एक तय प्रक्रिया मानी जाए, लेकिन यह एक बड़ी घोषणा थी। मुमकिन है कि इसमें उनकी सियासी सोच भी छिपी हो। अगले साल के मध्य में वह चुनाव में उतरने वाले हैं। इसलिए इस घोषणा को अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाने की कोशिश से जोड़कर भी देखा जाएगा ही। मगर सच यह भी है कि प्रधानमंत्री 'स्पेस टेक्नोलॉजी' का इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत होने वाले कामों में ही उन्होंने जिस तरह 'जियो टैगिंग' को अनिवार्य बनाया है, वह इस योजना में पारदर्शिता लाने में काफी कारगर साबित हो रहा है।

कहा यह भी जा रहा है कि अंतरिक्ष में इंसान को भेजने का यह काम इसरो बहुत पहले कर सकता था। बेशक, इसरो के पास पहले से ही काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है। उसने बेहतरीन रॉकेट भी बनाए हैं। प्रक्षेपण में भी उसके हाथ सधे हुए हैं। अच्छे सैटेलाइट और रॉकेट होने के कारण इंसान को अंतरिक्ष में भेजने में देरी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि हमारा जीएसएलवी मार्क-2 फेल हो रहा था और अंतर्राष्ट्रीय उठा-पटक के कारण, खासतौर से यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं थी। अब हमारी आर्थिक सेहत सुधरी है और सफलता की दर में भी हम दूसरी तमाम अंतरिक्ष

अंतरिक्ष की ओर (जनसत्ता)

अंतरिक्ष में जाना मानव का शुरू से ही सपना रहा है। अमेरिका, रूस और चीन ने तो दशकों पहले ही इसमें बाजी भी मार ली थी, लेकिन भारत के लिए यह अब तक एक सपना ही बना रहा। लेकिन अब वह वक्त दूर नहीं जब भारत का यह सपना साकार होगा। चार साल बाद यानी 2022 में भारत अंतरिक्ष में मानव मिशन भेज कर ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश हो जाएगा। साल 1984 में भारत के पहले और एकमात्र अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। लेकिन तब भारत के पास इसके लिए कोई सुविधा नहीं थी और उन्हें अमेरिकी यान टी सोयूज की मदद से भेजा गया था। अब भारत जो मिशन भेजेगा, वह पूरी तरह स्वदेशी होगा। 'गगनयान' नाम के इसके अभियान को कामयाब बनाने के लिए भारत जरूरी प्रौद्योगिकी विकसित कर चुका है।

अंतरिक्ष की उपलब्धियों के संदर्भ में देखें तो भारत ने काफी कुछ हासिल किया है, लेकिन दुनिया के कई देशों की तुलना में हम अभी बहुत पीछे हैं। जब पहली बार चाँद पर मानव ने कदम रखा था, तब भारत के वैज्ञानिक राकेट के हिस्सों को साइकिल पर रख कर प्रक्षेपण स्थल तक ले जाते थे। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अब तक ढेरों अंतरिक्ष मिशन पर काम किया है। दूसरे ग्रहों तक अपने यान भेजे। चाँद पर अमेरिका और रूस अपने अंतरिक्ष यात्रियों को दशकों पहले उतार चुके हैं। चीन भी जल्द ही चंद्रमा पर अपना मानव मिशन भेजने और अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की तैयारी में है। अगर इन सब उपलब्धियों से तुलना करके देखें तो लगता है भारत ने अभी तक कुछ नहीं किया। इसलिए भारत को अभी काफी कुछ हासिल करना है। फिर भी यह तथ्य है कि भारत आज राकेट, प्रक्षेपण यान और उपग्रह बनाने और छोड़ने में कामयाबी हासिल कर चुका है। अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने का मिशन काफी जोखिम भरा होता है। भारत के लिए यह चुनौती भरा इसलिए भी है कि पहली बार इतने बड़े मिशन को अंजाम दिया जाना है।

अंतरिक्ष यान, उसे भेजने के लिए प्रक्षेपण यान, यात्रियों के लिए जरूरी सुरक्षा तकनीक इसरो पहले ही विकसित कर चुका है। यह यान अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर लौटेगा भी। दस हजार करोड़ रुपए की लागत वाले इस अभियान को कामयाब बनाने के लिए इसरो कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता। इसलिए पहले दो मानव-रहित मिशन अंतरिक्ष में भेजे जाएँगे। इसरो के पूर्व प्रमुख जी माधवन नायर ने तो अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण में अमेरिका या रूस की मदद लेने की जरूरत बताई है, क्योंकि भारत के पास फिलहाल ऐसी सुविधा नहीं है। भारत को अभी अपना अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने में काफी वक्त लगेगा। यों तो,

एजेंसियों पर बीस साबित हुए हैं। लिहाजा यह सही वक्त है कि हम मानव मिशन की ओर तेजी से कदम बढ़ाएँ।

मानव मिशन की राह में अब हमें ज्यादा मुश्किलों का शायद ही सामना करना पड़े। 'गगनयान' जीएसएलवी मार्क-3 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह हमारा सबसे भारी-भरकम और सफल रॉकेट है। इसीलिए मैं इसे 'रॉकेट का बाहुबली' भी कहता हूँ। इतना ही नहीं, 2014 में ही इसरो क्रू मॉड्यूल टेस्ट कर चुका है। क्रू मॉड्यूल वही ढाँचा होता है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठते हैं और सुरक्षित धरती पर लौटते हैं। 'स्पेस सूट' तो हम तैयार कर ही चुके हैं। साफ है कि अब एक प्रोजेक्ट के तौर पर इस मिशन को आगे बढ़ाने की देर है। इसरो ने भी कहा ही है कि वह पहले दो मानव रहित यान भेजेगा और फिर मानव मिशन।

'गगनयान मिशन' की सफलता की इसलिए भी उम्मीद बँधती है कि इसरो ने अब तक जो भी वादे किए हैं, वे पूरे हुए हैं। चंद्रयान इसने समय पर छोड़ा है और मंगलयान भी। गगनयान के लिए उसे नौ-दस हजार करोड़ रुपये की जरूरत है, जो भारत जैसी उभरती आर्थिक ताकत के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। फिर, इस मिशन से 15 हजार के करीब नए रोजगार का भी सृजन होगा और आने वाले समय में अंतरिक्ष में जाने की लोगों की आकांक्षाएँ भी पूरी होंगी।

हां, एक-दो मुश्किलें हैं, जिन्हें जल्दी से जल्दी दूर करना जरूरी है। जैसे, इसरो की चिंता यह है कि अभी उसके पास 'बायोलॉजिकल साइंटिस्ट' और 'ह्यूमन मेडिकल सिस्टम' के अच्छे विशेषज्ञ नहीं हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जो जीवन रक्षक तंत्र बनाया जाएगा, उसमें इन विशेषज्ञों की खासी जरूरत होती है। हो सकता है कि इसके लिए भारतीय वायुसेना और इंस्टीट्यूट ऑफ एयरो स्पेस मेडिसिन से मदद मांगी जाए। अच्छी बात यह है कि इसरो अपने गगनयान मिशन को निजी मिशन बताने की बजाय 'राष्ट्रीय मिशन' बता रहा है। यानी यह इसरो का निजी प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि राष्ट्र का प्रोजेक्ट है। जाहिर है, इस नजरिये के साथ आगे बढ़ने से इसरो का काम आसान हो जाएगा।

अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने का काम 2004 में शुरू हो चुका था, लेकिन बाद में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तब से यह मिशन आगे नहीं बढ़ पाया। हालाँकि इस दिशा में छोटे-मोटे प्रयोग होते रहे।

दो साल पहले तक भी इसरो प्रमुख ने कहा था कि अंतरिक्ष में मानव को भेजना प्राथमिकता नहीं है। जाहिर है, ऐसे मिशन सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व की इच्छाशक्ति की वजह से सिरे नहीं चढ़ पाए। भारत के पास वैज्ञानिक प्रतिभाओं की कमी नहीं है। वैज्ञानिक संस्थानों को धन और संसाधनों के अभाव से जूझना पड़ता है और तमाम बड़ी परियोजनाएँ फाइलों में दबी रह जाती हैं। अगर वैज्ञानिक संस्थानों को पैसे की कमी और सरकारी अड़ंगों का सामना नहीं करना पड़ता, और राजनीतिक इच्छाशक्ति होती तो शायद हम काफी पहले ही अंतरिक्ष में जाने का सपना पूरा कर लेते!

चुनौती जीएसएलवी मार्क-3 का लगातार सफल प्रक्षेपण होने की भी है। अभी तक इसका एक ही सफल प्रक्षेपण हुआ है। आने वाले दिनों में अगर इसका एक भी प्रक्षेपण असफल हुआ, तो अंतरिक्ष में मानव को भेजने की इस योजना पर ग्रहण लग सकता है। हालाँकि इसरो के साथ-साथ तमाम लोगों की यही उम्मीदें हैं कि ऐसा खतरा सामने नहीं आएगा और हम सफल रहेंगे। इसरो की असफलता की दर काफी कम है। यह हमारे भरोसे को मजबूत बनाता है।

स्पेस के क्षेत्र में भारत काफी बेहतर स्थिति में है। हम अपना रॉकेट खुद बना रहे हैं। सैटेलाइट भी तैयार कर रहे हैं। एप्लीकेशन में तो हम अव्वल हैं ही। फिर कम खर्च में सैटेलाइट बनाने और उसे लॉन्च करने में भी हमें महारत हासिल हो चुकी है। ऐसे में, इस मिशन के साथ हमारी निगाहें भविष्य की उस स्थिति पर भी बनी हुई है, जब चंद्रमा और मंगल पर लोग बसेंगे। इसरो उसी ओर अपनी उड़ान भर रहा है। यदि जरूरत महसूस हुई, तो हम भी वहाँ कॉलोनी बसा सकेंगे। गगनयान हमें इस सपने के करीब लाने वाला मिशन साबित होगा।

GS World टीम...

सारांश

- अमेरिका, रूस और चीन ने तो दशकों पहले ही इसमें बाजी भी मार ली थी, लेकिन भारत के लिए यह अब तक एक सपना ही बना रहा। लेकिन अब वह वक्त दूर नहीं जब भारत का यह सपना साकार होगा। चार साल बाद यानी 2022 में भारत अंतरिक्ष में मानव मिशन भेज कर ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश हो जाएगा।
- साल 1984 में भारत के पहले और एकमात्र अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। लेकिन तब भारत के पास इसके लिए कोई सुविधा नहीं थी और उन्हें अमेरिकी यान टी. सोयूज की मदद से भेजा गया था। अब भारत जो मिशन भेजेगा, वह पूरी तरह स्वदेशी होगा। 'गगनयान' नाम के इसके अभियान को कामयाब बनाने के लिए भारत जरूरी प्रौद्योगिकी विकसित कर चुका है।
- अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अब तक ढेरों अंतरिक्ष मिशन पर काम किया है। दूसरे ग्रहों तक अपने यान भेजे। चाँद पर अमेरिका और रूस अपने अंतरिक्ष यात्रियों को दशकों पहले उतार चुके हैं। चीन भी जल्द ही चंद्रमा पर अपना मानव मिशन भेजने और अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की तैयारी में है।
- अंतरिक्ष यान, उसे भेजने के लिए प्रक्षेपण यान, यात्रियों के लिए जरूरी सुरक्षा तकनीक इसरो पहले ही विकसित कर चुका है। यह यान अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर लौटेगा भी। दस हजार करोड़ रुपए की लागत वाले इस अभियान को कामयाब बनाने के लिए इसरो कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता। इसलिए पहले दो मानव-रहित मिशन अंतरिक्ष में भेजे जाएँगे।
- इसरो के पूर्व प्रमुख जी माधवन नायर ने तो अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण में अमेरिका या रूस की मदद लेने की जरूरत बताई है, क्योंकि भारत के पास फिलहाल ऐसी सुविधा नहीं है। भारत को अभी अपना अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने में काफी वक्त लगेगा।
- अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ, तो 2022 में भारत उन देशों में शुमार हो जाएगा, जो अंतरिक्ष में इंसान को भेजने में सक्षम

हैं। अभी इस सूची में मात्र तीन देश हैं। रूस ने यह उपलब्धि सबसे पहले हासिल की थी। उसने 1961 में ही यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रच दिया था। फिर अमेरिका ने यह कारनामा दोहराया और तीसरी उपलब्धि चीन के खाते में आई है।

- इसरो उसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसकी एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के अपने संबोधन में दिखाई थी। उनका कहना था कि 2022 में जब देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे या हो सके, तो उससे पहले ही भारत माँ का कोई लाल, चाहे बेटा हो या बेटी, अंतरिक्ष में पहुँचे।
- 'गगनयान' जीएसएलवी मार्क-3 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह हमारा सबसे भारी-भरकम और सफल रॉकेट है। इतना ही नहीं, 2014 में ही इसरो क्रू मॉड्यूल टेस्ट कर चुका है। क्रू मॉड्यूल वही ढाँचा होता है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठते हैं और सुरक्षित धरती पर लौटते हैं। 'स्पेस सूट' तो हम तैयार कर ही चुके हैं।
- 'गगनयान मिशन' की सफलता की इसलिए भी उम्मीद बंधती है कि इसरो ने अब तक जो भी वादे किए हैं, वे पूरे हुए हैं। चंद्रयान इसने समय पर छोड़ा है और मंगलयान भी। गगनयान के लिए उसे नौ-दस हजार करोड़ रुपये की जरूरत है, जो भारत जैसी उभरती आर्थिक ताकत के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। फिर, इस मिशन से 15 हजार के करीब नए रोजगार का भी सृजन होगा और आने वाले समय में अंतरिक्ष में जाने की लोगों की आकांक्षाएं भी पूरी होंगी।
- चुनौती जीएसएलवी मार्क-3 का लगातार सफल प्रक्षेपण होने की भी है। अभी तक इसका एक ही सफल प्रक्षेपण हुआ है। आने वाले दिनों में अगर इसका एक भी प्रक्षेपण असफल हुआ, तो अंतरिक्ष में मानव को भेजने की इस योजना पर ग्रहण लग सकता है।

गगनयान

- भारत का मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरी झंडी दिखाई गयी और इसका लॉन्च 2022 के लिए तय किया गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के. शिवान के अनुसार पूर्णत: संभव है।
- जब भारत यह लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, तो भारत सोवियत, अमेरिकी और चीनी एजेंसिओं के बाद पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला चौथा राष्ट्र होगा। 1984 में, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर (सेवानिवृत्त) राकेश शर्मा ने सोवियत मिशन के हिस्से के रूप में पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया था।
- गगनयान भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम का आधार बनने के लिए एक भारतीय चालित कक्षीय अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष यान को तीन लोगों को ले जाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, और एक नियोजित अपग्रेड किए गए संस्करण को डॉकिंग क्षमता से लैस किया जाएगा।
- अपने पहले चालित मिशन में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्य रूप से स्वायत्त 3.7 टन कैप्सूल पृथ्वी पर तीन व्यक्तियों के दल के साथ सात दिनों तक 400 किमी (250 मील) ऊँचाई पर पृथ्वी की कक्षा में होगा। चालित वाहन को 2022 में इसरो के जीएसएलवी एमके III पर लॉन्च करने की योजना है। इस एचएएल-निर्मित क्रू मॉड्यूल की 18 दिसंबर, 2014 को पहली गैर-चालित प्रयोगात्मक उड़ान थी।
- गगनयान का विकास सामान्य नाम "ऑर्बिटल वाहन" के तहत 2006 में शुरू हुआ। इस योजना का लक्ष्य बुध-स्तर के अंतरिक्ष यान के समान एक साधारण कैप्सूल को अंतरिक्ष में लगभग एक सप्ताह रखने के लिए डिजाइन करने का था। इसे दो अंतरिक्ष यात्री ले जाने और वायुमंडल में फिर से प्रवेश पर पानी में उतरने के लिए डिजाइन किया गया था।
- डिजाइन को मार्च 2008 तक अंतिम रूप दिया गया था, और इसे वित्त पोषण के लिए भारत सरकार को सौंप दिया गया था। इंडियन ह्यूमन स्पेसफाइट कार्यक्रम के लिए वित्त पोषण फरवरी 2009 में स्वीकृत किया गया था। प्रारंभ में, ऑर्बिटल वाहन की पहली गैर-चालित उड़ान 2013 में होने की उम्मीद थी।
- इसरो स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपीरिमेंट (एसआरई) के डिजाइन पर कक्षीय वाहन, गगनयान आधारित है। इसरो ने जनवरी 2007 में 550 किलोग्राम स्पेस रिकवरी कैप्सूल लॉन्च और उसे पुनर्प्राप्त किया था। पूर्ण पैमाने पर चालित अंतरिक्ष यान इसी से लिया गया था, हालाँकि इसरो की प्रकाशित अवधारणा ने एसआरई की तुलना में अधिक विस्तारित शंकु आकार दिखाया था।
- गगनयान का विकास 2006 में शुरू हुआ था। अंतरिक्ष में एक सप्ताह गुजरने में योग्य मर्क्यूरी-क्लास अंतरिक्ष यान के समान एक साधारण जहाज तैयार करने की योजना थी। यह दो अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए और पुन: प्रवेश पर पानी में उतरने के लिए बनाया जाना था। मार्च 2008 तक डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया और वित्तपोषण के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया था।
- इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में घोषणा की थी कि भारत 2022 तक अंतरिक्ष में एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजेगा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अंतरिक्ष में इंसान को भेजने वाला चौथा देश होगा।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष के. शिवान ने कहा कि अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने के लिए प्रस्तावित 'गगनयान' मिशन में तीन क्रू सदस्य होंगे जो 5-7 दिनों तक अंतरिक्ष में रहेंगे। शिवान ने बताया कि मिशन की शुरुआत के बाद यह 16 मिनट में कक्षा में पहुँचेगा। पृथ्वी पर लौटते वक्त क्रू गुजरात तट के पास अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में उतर सकता है या जमीन पर भी उतर सकता है।

PT / Mains - प्रश्न

संभावित प्रश्न

1. भारत की अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की महत्त्वाकांक्षी परियोजना का क्या नाम है?

(a) मानवयान (b) गगनयान
(c) अंतरिक्ष यान (d) चंद्रयान

(उत्तर-B)

2. निम्नलिखित में से कौन-से इसरो के अंतरिक्ष मिशन हैं?

1. गगनयान
2. चंद्रयान
3. एस्ट्रोसैट
4. इरोसैट

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें-

(a) 1, 2 और 3 (b) 1, 2 और 4
(c) 1, 3 और 4 (d) 2, 3 और 4

(उत्तर-A)

3. भारतीय मानव अंतरिक्ष मिशन 'गगनयान' की प्रक्षेपण तिथि किस वर्ष नियत की गई?

(a) 2022 (b) 2023
(c) 2024 (d) 2025

(उत्तर-A)

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. गगनयान की नियत तिथि 2022 में निर्धारित की गई है।
2. यह पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है।
3. यह जीएसएलवी मार्क-3 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) 1, 2 और 3 (b) 1 और 2
(c) 2 और 3 (d) 1 और 3

(उत्तर-A)

5. भारतीय अंतरिक्ष मिशन 'गगनयान' से संबंधित चुनौतियों एवं उपलब्धियों पर चर्चा करें।

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न

1. 'एस्ट्रोसैट' के संबंध में जो भारत द्वारा प्रक्षेपित खगोलीय वेद्यशाला है, के संदर्भ में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. यू.एस.ए. एवं रूस के अलावा, भारत एकमात्र देश है जिसने अंतरिक्ष में एक समान वेद्यशाला प्रक्षेपित किया है।
2. एस्ट्रोसैट एक 2000 कि.ग्रा. का सैटेलाइट है जिसे धरती की सतह से 1650 किमी. ऊपर कक्षा में स्थापित किया गया है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें-

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

(IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2016, उत्तर-D)

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

इसरो द्वारा प्रक्षेपित मंगलयान

1. को मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं।
2. ने भारत को यू.एस.ए. के बाद दूसरा ऐसा देश बना दिया जिसने मंगल की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजा है।
3. ने भारत को एकमात्र देश बना दिया, जिसने प्रथम प्रयास में मंगल की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजा है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) 2 और 3
(c) 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

(IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2016, उत्तर-A)

3. सेलेन-1, लूनर ऑर्बिटर मिशन किससे संबंधित है?

(a) चीन
(b) यूरोपियन यूनियन
(c) जापान
(d) यू.एस.ए

(IAS प्रारंभिक परीक्षा, वर्ष-2008, उत्तर-C)

4. 'नासा' का जूनो मिशन पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास को समझने में किस प्रकार सहायता करता है?

(IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-1, वर्ष-2017)

5. जी.पी.एस. युग में, 'मानक स्थिति-निर्धारण प्रणालियों' से आप क्या समझते हैं? केवल सात उपग्रहों का इस्तेमाल करते हुए अपने महत्त्वाकांक्षी आई.आर.एन.एस.एस. कार्यक्रम से भारत किन लाभों को देखता है, इस पर चर्चा कीजिए।

(IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-3, वर्ष-2015)

6. भारत ने चंद्रयान एवं मंगलकक्षीय मिशनों सहित मानव-रहित अंतरिक्ष मिशनों में असाधारण सफलता प्राप्त की है, लेकिन मानव-सहित अंतरिक्ष मिशनों में प्रवेश का साहस नहीं किया है। मानव-सहित अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने में प्रौद्योगिकीय व सुप्रचालनिक सहित मुख्य रुकावटें क्या हैं? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

(IAS मुख्य परीक्षा, पेपर-3, वर्ष-2017)

GS World
Committed To Excellence

IAS GS World PCS

Committed To Excellence

IAS Pre.-2019

Online link

http://www.gsworldonlinetest.com

NCERT Based - 4, Topic Wise - 10, Eco. Surevey & Budget- 1, India Year Book- 1, CSAT - 4, GS Full Test- 3

(Total Test - 23)

Fee:- GSW St. : 4500/- | Online St. : 5000/- | Other St. : 6500/-

Test No.	Date	Day	Topic	Ref. Books
Test - 1	23 Sep.	Sunday	History	Class-11 & 12 (Old + NEW NCERT + Current Affairs-May 2018)
Test - 2	7 Oct.	Sunday	Geography	Class-11 & 12 (Old + NEW NCERT + Current Affairs- June 2018)
Test - 3	14 Oct.	Sunday	Polity	Class-11 & 12 (Old + NEW NCERT + Current Affairs- July 2018)
Test - 4	21 Oct.	Sunday	Economy	Class-11 & 12 (Old + NEW NCERT + Current Affairs- Aug. 2018)
Test - 5	28 Oct.	Sunday	**CSAT**	
Test - 6	4 Nov.	Sunday	Ancient + Medieval + Art. & Cult. (History)*	Ancient & Medival India by TMH, Indian Art. & Cult. By Nitin Singhaniya, GS World Notes + Current Affairs- Sep. 2018
Test - 7	18 Nov.	Sunday	Modern History*	India's Struggle for Independence- Vipin Chandra, A Brief History of Modern India- Spectrum Publication, GS World Notes
Test - 8	2 Dec.	Sunday	World Geography*	Mahesh Barnwal, Oxford School Atlas, GS World Notes
Test - 9	16 Dec.	Sunday	Indian Geography*	Mahesh Barnwal, Oxford School Atlas, GS World Notes
Test - 10	30 Dec.	Sunday	Indian Constitution and Polity-1st*	M. Laxmikant, D.D. Bashu, GS World Notes + Current Affairs- Oct. 2018
Test - 11	13 Jan.	Sunday	Indian Constitution and Polity-2nd*	M. Laxmikant, D.D. Bashu, GS World Notes + Current Affairs- Nov. 2018
Test - 12	27 Jan.	Sunday	Economy*	S.N. Lal, GS World Notes + Current Affairs- Dec. 2018
Test - 13	10 Feb.	Sunday	Environment-1*	Erach Bharucha, IGNOU, GS World Notes, Current Affairs- Jan. 2019
Test - 14	3 Mar.	Sunday	Environment-2*	Erach Bharucha, IGNOU, GS World Notes
Test - 15	17 Mar.	Sunday	General Sci. and Sci. & Tech.*	NCERT + Vivas Panorma, GS World Notes
Test - 16	31 Mar.	Sunday	Economic Survey & Budget	Finance Ministry, Govt. of India, GS World Notes + Current Affairs- Feb. 2019
Test - 17	7 Apr.	Sunday	India Year Book	Information & Technology Ministry, Govt. of India, GS World Notes + Current Affairs- March. 2019
Test - 18+19	14 Apr.	Sunday	**GS + CSAT - Full Test**	
Test - 20+21	21 Apr.	Sunday	**GS + CSAT - Full Test**	
Test - 22+23	28 Apr.	Sunday	**GS + CSAT - Full Test**	

*** पिछले दो वर्षों (2016–18) में इन विषयों से चर्चा में रहे टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जाएंगे।**

629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09 #7042772063 9654349902